

राष्ट्रीय मासिक

मूल्य : 40/-

# रफ्तार

वर्ष : 04 | अंक 31

## मीडिया

अप्रैल, 2026

### गैस के बाद अब खाद संकट

ईरान युद्ध से बिगड़ी सप्लाई चेन  
खरीफ़ से पहले सरकार की अग्नि परीक्षा

तेल से जीरे तक मसाला संकट  
ग्लोबल तनाव से बदलता बाजार

क्लाइमेट पॉलिसी का सच  
कीमत चुका रहे हैं किसान

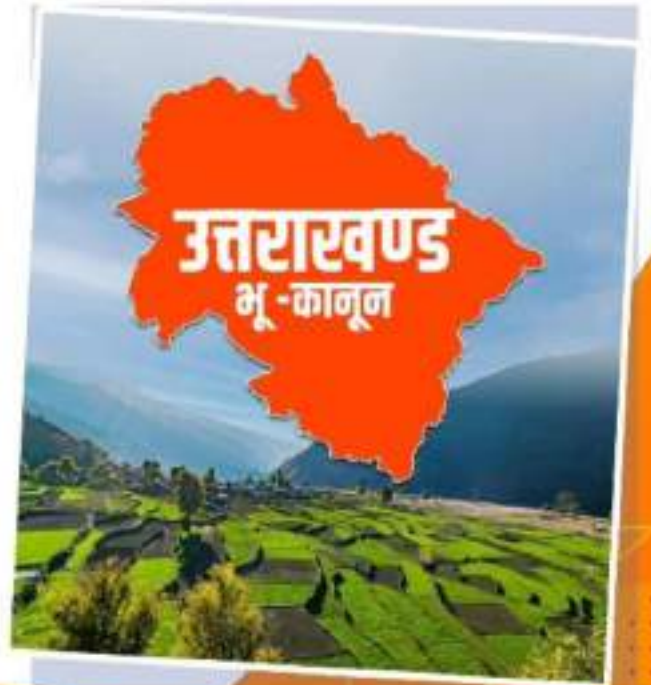
जब खेत उगाएँगे दवाएँ  
खेती की बदलती पहचान

# 4 साल बेमिसाल

## उत्तराखण्ड में सशक्त भू-कानून



- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद को छोड़कर उत्तराखण्ड के अन्य 11 पर्वतीय जिलों में दूसरे राज्यों के लोगों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं
- पर्वतीय जिलों में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर लगी रोक
- डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर लगाम, साथ ही देवभूमि की सनातन संस्कृति और पारंपरिक सामाजिक पहचान भी होगी मजबूत



PAGE 04



रफ्तार मीडिया कवर स्टोरी

प्रबंध संपादक | गौरव कुमार

डिप्टी एडिटर | अरविंद कुमार

## संपादकीय कार्यालय

उत्तम निवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर अरगोड़ा  
थाना, हरमू, रांची. पिन-834002  
ईमेल articleraftaar@gmail.com  
विज्ञापन: 9709289751



पिछला अंक

मुद्रक : प्रकाशक एवम स्वतन्त्राधिकारी गौरव कुमार के  
पक्ष में शिवसाई पब्लिकेशन प्रा.लिमिटेड, काठीटांड, नियर  
टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप, पोस्ट एवं थाना रांची  
835222 झारखंड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

# कर्ज, फसल और मौत, कब थमेगा किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला?

पंजाब में ₹25 लाख के कर्ज तले दबे किसानों की मौत ने फिर एक असहज सच उजागर किया है - भारत का अन्नदाता आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दबाव के ऐसे चक्र में फंसा है, जहाँ से निकलना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है।

पंजाब में ₹25 लाख के कर्ज तले दबे किसानों की मौत कोई अलग-थलग घटना नहीं है - यह उस गहरे संकट का लक्षण है, जिसमें भारत का कृषि तंत्र फँस चुका है। यह एक पैटर्न है, जो वर्षों से दोहराया जा रहा है। देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं - और अधिकांश मामलों में कर्ज एक केंद्रीय कारण बनकर उभरता है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन परिवारों की हकीकत है, जो हर सीजन उम्मीद और भय के बीच झूलते हैं। भारत खुद को कृषि प्रधान देश कहता है, लेकिन यहीं देश अपने अन्नदाता को आर्थिक असुरक्षा, कर्ज और अनिश्चितता के हवाले छोड़ चुका है। खेती



अरविंद कुमार  
डिप्टी एडिटर

अब लाभ का नहीं, बल्कि जीवित रहने का संघर्ष बन चुकी है। किसानों की आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है - कर्ज का बढ़ता बोझ। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और डीजल - हर इनपुट महंगा होता जा रहा है। इसके उलट, फसलों के दाम अक्सर या तो स्थिर रहते हैं या बाजार की अस्थिरता में दब जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उसका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुँचता। ऐसे में किसान के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं। बैंक ऋण तक पहुँच अभी भी असमान है, और कई किसान अंततः गैर-संस्थागत स्रोतों - साहूकारों - का सहारा लेते हैं, जहाँ ब्याज ऊँचा और दबाव तत्काल होता है। यही कर्ज धीरे-धीरे एक ऐसे जाल में बदल जाता है, जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इस आर्थिक दबाव को और गहरा बनाती हैं प्राकृतिक अनिश्चितताएँ।

सूखा, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि - एक ही फसल का नुकसान किसान की पूरी साल भर की आय को खत्म कर सकता है। फसल बीमा योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन उनका लाभ अक्सर समय पर और पर्याप्त रूप में नहीं पहुँच पाता। जब तक राहत आती है, तब तक नुकसान स्थायी हो चुका होता है। लेकिन यह संकट केवल आर्थिक नहीं है। इसका एक गहरा मानसिक और सामाजिक आयाम भी है। कर्ज सिर्फ बैंक का आंकड़ा नहीं - यह सम्मान, जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव से जुड़ा होता है। जब किसान इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो यह असफलता का भाव गहराता जाता है। कई बार यही भाव उसे अंतिम कदम उठाने की ओर धकेल देता है। शहरों में महंगाई पर बहस होती है, गाँवों में जीवन दांव पर लगा है।

सरकारें समय-समय पर कर्ज माफी की घोषणाएँ करती रही हैं। यह कदम तत्काल राहत जरूर देता है, लेकिन यह समाधान नहीं है। कर्ज माफी समस्या के लक्षण को संबोधित करती है, कारण को नहीं। असली चुनौती है - ऐसी व्यवस्था बनाना जहाँ किसान कर्ज के जाल में फँसे ही नहीं। इसके लिए तीन स्तरों पर सुधार जरूरी हैं। पहला, आय सुरक्षा - किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत और स्थिर मूल्य मिलना चाहिए। MSP की पहुँच और प्रभाव दोनों को व्यापक बनाना होगा। दूसरा, लागत नियंत्रण और सस्ती वित्तीय पहुँच - इनपुट लागत पर नियंत्रण और सरल, सुलभ संस्थागत ऋण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसान साहूकारों के चक्र से बाहर रह सके। तीसरा, सामाजिक और मानसिक समर्थन - किसानों के लिए परामर्श सेवाएँ, हेल्पलाइन और सामुदायिक सहायता तंत्र विकसित करना उतना ही जरूरी है जितना आर्थिक सुधार। किसानों की आत्महत्या कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है।

कॉर्पोरेट एवं व्यावसायिक कार्यालय : अजीत कुमार, 8/18 सेकेंड प्लोर, नेहरु नगर, नई दिल्ली 110065 ईमेल raftaarhr@gmail.com CONTACT NO. 6203592707

सुबई कार्यालय : चंद्रमान विश्वनाथ मौर्य, रुम नंबर A56/3/5 संत रोहिदास मार्ग खंबादेव नगर धारावी मुंबई- 400017

देहरादून कार्यालय : आयुष निगम, खबर हाउस, नेवासा रोहन मोटर्स के पीछे, जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखंड, 248001 |

राजकुमार, एस.सी.एफ. 254, प्रथम मंजिल, सेक्टर 16, पंचकूला (हरियाणा) | स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया CG-MP H-14, डेवर पिक सिटी, गायत्री नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ | शाहिद सिद्दीकी, 21, बीसी गोमती रीजेंसी, साड़ी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ | रवि नंदन सिंह (स्टेट हेड), 200/1D, डीजी मिश्रा पथ, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना (बिहार) 800013 |



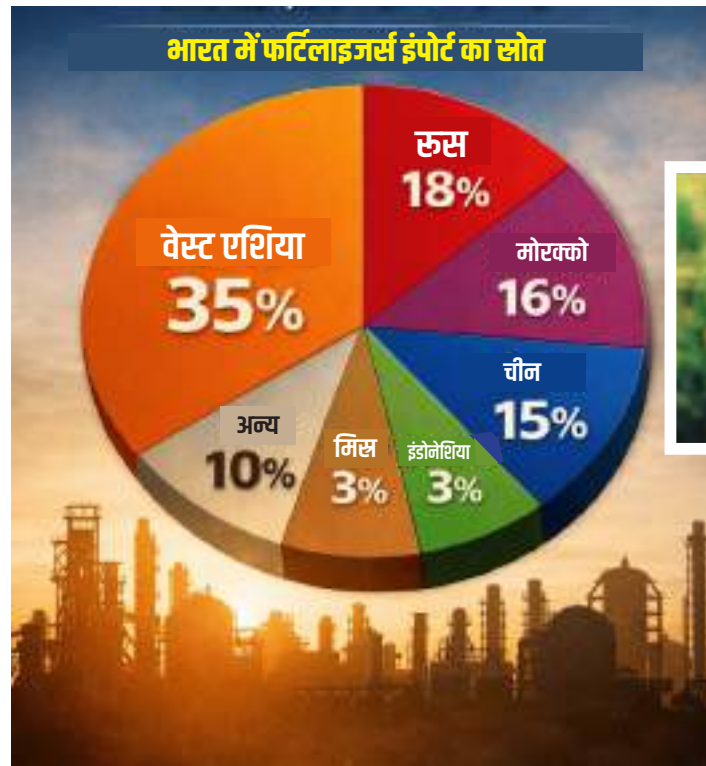
## गैस के बाद अब

ईरान युद्ध से बिगड़े वैश्विक हालात ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बाद अब खाद आपूर्ति को भी संकट के दायरे में ला खड़ा किया है। बढ़ती कीमतें, आयात पर गहरी निर्भरता और सप्लाई में अनिश्चितता के बीच खरीफ सीजन से पहले चुनौती और गंभीर हो गई है—जिसका सीधा असर देश की खेती, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों किसानों की आजीविका पर पड़ सकता है।

# खाद पर सतर्क सरकार

### एन कुमार

ईरान युद्ध से वेस्ट एशिया में उपजे हालात का असर भारत पर भी पड़ा है। एनर्जी के मामले में व्यापक रूप से इंपोर्ट पर निर्भरता की वजह से खास करके गैस को लेकर जो आपाधापी और लोगों की घबराहट दिखी, वह शायद इससे पहले कभी नहीं दिखी। हालांकि सरकार बार बार लोगों से पैनिक ना करने की आग्रह और अपील करती रही। बावजूद इसके मार्च के पहले 2 हफ्तों में लोगों को समझना इन बड़ी चुनौती बन गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सरकार ने इस मामले में बेहद मुस्तैदी दिखाई और चौतरफा सक्रियता दिखाते हुए हालात को काफी हद तक काबू में कर लिया। हालांकि कि सप्लाई में जो खाड़ी देशों की भूमिका से जुड़े सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सरकार की परीक्षा की बारी अब राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील खेती और किसानों को लेकर है। क्योंकि खेती के लिए भारी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स को लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं।



## खरीफ सीजन से पहले बढ़ता दबाव



सामने खरीफ का सीजन है, जिसमें मुख्य रूप से धान, कपास, सोयाबीन, उड़द, अरहर, मूंगफली और गन्ने की खेती होती है। ऐसे में अप्रैल-मई से लेकर सितंबर तक फर्टिलाइजर्स की भारी मांग बनी रहती है। यह वही समय होता है जब खेतों में तैयारी और बोआई की प्रक्रिया तेज होती है, इसलिए खाद की उपलब्धता और कीमत दोनों ही सीधे तौर पर उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

## खेत से आवाज: बढ़ती चिंता, घटता भरोसा

ग्राउंड पर किसानों की चिंताएं इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के एक कपास किसान बताते हैं कि पिछले साल भी उन्हें डीएपी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा था और अगर इस बार शुरुआत में ही दिक्कत हुई तो पूरी फसल पर असर पड़ सकता है। पंजाब के एक धान उत्पादक किसान का अनुभव है कि हर बार सरकार आश्वासन देती है, लेकिन सीजन आते ही दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाने वाले किसानों का कहना है कि अगर खाद मंहंगी हुई तो लागत बढ़ेगी और अगर समय पर उपलब्ध नहीं हुई तो पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। इन अनुभवों से साफ है कि यह संकट केवल सप्लाई या कीमत का नहीं, बल्कि भरोसे का भी है।



## कैसे बढ़ा खाद संकट



## वैश्विक बाजार में कीमतों का उछाल

ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित होने से वैश्विक बाजार में फर्टिलाइजर के दाम 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के बाधित होने से यूरिया और अमोनिया की उपलब्धता कम हुई है, जिससे खरीफ सीजन से पहले नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों की कीमतों में तेज उछाल आया है। मार्च की शुरुआत में ही यूरिया की कीमतें 485 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 600 डॉलर प्रति टन के पार पहुंच गईं। हालांकि भारत में सरकार सब्सिडी के जरिए किसानों को राहत देती है, जिससे यहां कीमतें नियंत्रित रहती हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में किसान इस समय कहीं अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हैं।

### फर्टिलाइजर संकट : एक नजर में

भारत की सालाना खपत	650 लाख टन
यूरिया की खपत	365 लाख टन
कुल आयात निर्भरता	25%
पोटाश	100% आयात
DAP	50-60% आयात
यूरिया	25% आयात
ग्लोबल कीमत बढ़ोतरी	30-40%

## किन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर?

इस संभावित संकट का प्रभाव पूरे देश में समान नहीं रहने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य, जहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहां उर्वरकों की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कपास और सोयाबीन की खेती पर इसका असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में धान और गन्ने की खेती दोनों प्रभावित हो सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत में दालों और तिलहनों की खेती भी इस संकट की चपेट में आ सकती है। इस तरह यह स्थिति क्षेत्रीय असंतुलन को और बढ़ा सकती है।

## आपूर्ति सबसे बड़ी चुनौती

आपूर्ति को लेकर चिंता सबसे ज्यादा है क्योंकि देश में करीब 25 प्रतिशत फर्टिलाइजर्स का आयात करना पड़ता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से सप्लाई प्रभावित होने की आशंका ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान देकर भरोसा दिलाया कि जैसे कोरोना काल में किसानों पर असर नहीं पड़ने दिया गया, वैसे ही इस वैश्विक संकट से भी उन्हें बचाया जाएगा। उन्होंने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

## आयात पर गहरी निर्भरता

घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत अभी भी फर्टिलाइजर्स के मामले में आयात पर काफी हद तक निर्भर है। पोटाश का लगभग पूरा आयात किया जाता है, जबकि डीएपी के मामले में 50 से 60 प्रतिशत तक आयात पर निर्भरता है। यूरिया का बड़ा उत्पादक होने के बावजूद इसमें भी लगभग 25 प्रतिशत आयात करना पड़ता है। फास्फोरिक एसिड, अमोनिया और पोटाश जैसे कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता सीमित होने के कारण यह निर्भरता बनी हुई है।

## कालाबाजारी और जमाखोरी का खतरा

ऐसी परिस्थितियों में केवल आपूर्ति ही नहीं, बल्कि वितरण प्रणाली भी चुनौती बन जाती है। अतीत में कई बार देखा गया है कि जैसे ही कमी की आशंका बढ़ती है, बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। डीलर स्तर पर स्टॉक रोककर ऊंचे दाम वसूलने की शिकायतें सामने आती हैं और किसानों को तय कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ता है। कई बार उन्हें लंबी कतारों में इंतजार भी करना पड़ता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार राज्यों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे रही है।

## खपत का बढ़ता दबाव

भारत में सालाना लगभग 650 लाख टन फर्टिलाइजर्स की खपत होती है, जिसमें यूरिया का हिस्सा सबसे ज्यादा, करीब 365 लाख टन है। वित्त वर्ष 2025 में कुल बिक्री 600 लाख टन से बढ़कर 656 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस बढ़ती मांग के बीच भारत हर साल बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात भी करता है। हालांकि सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देकर खपत को संतुलित करने की कोशिश कर रही है।



## गैस संकट का सीधा असर

फर्टिलाइजर्स उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस पर निर्भर करता है, खासकर यूरिया के उत्पादन में नेचुरल गैस प्रमुख कच्चा माल है, जो लागत का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाता है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 21 से 23 बीसीएम गैस की खपत होती है, जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत एलएनजी के रूप में आयात की जाती है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण सप्लाई बाधित होने से कई यूरिया संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भविष्य में कमी की आशंका बढ़ गई है।



## वैश्विक संकट: क्या यह नया सामान्य है?

यह संकट केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक सप्लाई चेन में आई अस्थिरता का हिस्सा है। कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और अब वेस्ट एशिया का तनाव-इन सभी ने मिलकर यह संकेत दिया है कि खाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनिश्चितता अब बार-बार सामने आ सकती है। बड़े निर्यातक देशों की नीतियां भी बाजार को प्रभावित करती हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है।

## सरकारी रणनीति और दावे

सरकार का दावा है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है और किसी भी स्थिति में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। मार्च तक देश में 177 से 180 लाख टन का बफर स्टॉक उपलब्ध बताया जा रहा है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात स्रोतों में विविधता लाने और ग्रीन अमोनिया जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

## क्या ये उपाय पर्याप्त हैं?

इसके बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या ये उपाय पर्याप्त साबित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कच्चे माल के स्तर पर आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ेगी, तब तक जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सब्सिडी व्यवस्था किसानों को राहत तो देती है, लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ता है। वहीं नए विकल्पों की प्रभावशीलता अभी बड़े स्तर पर पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है।

## आत्मनिर्भरता की चुनौती

लंबी अवधि में समाधान आयात पर निर्भरता को कम करने में ही निहित है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, ग्रीन अमोनिया, जैविक खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग जैसे उपायों को अपनाया होगा। साथ ही तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देना भी जरूरी होगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और उत्पादन पर असर कम पड़े।

## DAP इंपोर्ट: किस पर कितनी निर्भरता?

रूस	50%
कनाडा	25%
जॉर्डन	9%
इजरायल	8%
तुर्कमेनिस्तान	8%



## सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है

फिलहाल सरकार आश्वस्त नजर आती है और तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब खरीफ सीजन अपने चरम पर होगा। यदि सप्लाई सुचारु

रही और कीमतें नियंत्रित रहीं तो यह एक बड़ी सफलता होगी, लेकिन अगर वैश्विक संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर सीधे किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़

सकता है। गैस के बाद अब खाद - यह साफ इशारा है कि वैश्विक अस्थिरता का सबसे भारी बोझ आखिरकार खेत और किसान ही उठा रहे हैं।



# देश में बिजली उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पर UP प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता

उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में देश के टॉप-5 राज्यों में 5वें स्थान पर है। जबकि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यह बयान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश में जारी भीषण बिजली संकट को लेकर जारी किया है। अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि देश के सभी राज्य अपने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में गर्मी में ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई का प्रयास करते हैं। देश के पांच टॉप राज्यों में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता किस राज्य में कितनी है, यह भी उपभोक्ताओं को बताना जरूरी है। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसलिए आने वाले वर्षों में उत्पादन की स्थापित क्षमता उपभोक्ताओं के हित में स्टेट सेक्टर में बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि स्टेट सेक्टर के उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली खरीद पर रोक लगाती है। स्टेट सेक्टर की बिजली हमेशा सस्ती रही है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष

और सर्वोच्च सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में विशेषकर उत्तर भारत में भीषण बिजली संकट का दौर चल रहा है। ऐसे समय में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 73 लाख के आसपास पहुंच

लाख के करीब हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ 10 लाख के करीब और कर्नाटक में भी लगभग 2 करोड़ 25 लाख के करीब हैं।

उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक की स्थापित विद्युत क्षमता के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल होने के बावजूद राज्य क्षेत्र की

परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक रूप से निजी और केंद्रीय क्षेत्र पर निर्भर है। भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को बड़े स्तर पर राज्य क्षेत्र में नए तापीय, सौर और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना



**राज्य अपने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में गर्मी में ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई का प्रयास करते हैं। देश के पांच टॉप राज्यों में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता किस राज्य में कितनी है, यह भी उपभोक्ताओं को बताना जरूरी है। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है।**

चुकी है, वहां राज्य क्षेत्र (State Sector) में नए पावर हाउस स्थापित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ 85 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। तमिलनाडु में 2 करोड़ 30

उत्पादन क्षमता में सबसे निचले पायदान पर है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के आधार पर 30 अप्रैल 2026 तक के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 5,37,264.41 मेगावाट है।

करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में तेजी से इजाफा किया जाए।



# 1794 की रामचरितमानस और दुर्लभ गीता पांडुलिपि को देखने वाले देखते ही रह गए

राजधानी स्थित उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार में ज्ञानभारतम् मिशन के अंतर्गत बुधवार को आयोजित 'पांडुलिपि अभिरुचि कार्यशाला' में भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास और प्राचीन धरोहरों के संरक्षण को लेकर विशेष मंथन हुआ। इस मौके पर 'ज्ञानभारतम् निर्देशिका' और 'कोलोनियल लखनऊ' नामक दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला में प्रदेश भर से आए विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन कर भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत को करीब से समझा। अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि ज्ञानभारतम् मिशन के माध्यम से देश लगभग एक करोड़ पांडुलिपियों को एकत्रित और संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज ऐसा मजबूत मिशन तैयार हो चुका है, जिसके जरिए आम लोग भी अपनी पारिवारिक और निजी पांडुलिपियों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने शोधार्थियों से इतिहास के महत्व को समझने और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, साथ ही विश्वास जताया कि पांडुलिपियों के

संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करेगा।

विशिष्ट अतिथि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय इतिहास विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय ने "भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की अनेक चुनौतियों का समाधान

पांडुलिपियों का अवलोकन किया। यहां प्रदर्शित श्रीमद्भगवद्गीता की दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपि विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वर्ष 1967 की इस पांडुलिपि में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित सात सुंदर चित्रों के साथ भगवद्गीता के सभी 700 श्लोक संकलित हैं। रामचरितमानस की प्राचीन हिन्दी पांडुलिपि ने भी प्रतिभागियों को आकर्षित किया। वर्ष 1794 की इस दुर्लभ पांडुलिपि में

ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा देश की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 'ज्ञानभारतम् मिशन' जैसी पहले सिर्फ पांडुलिपियों के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास, दर्शन, साहित्य और लोक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने का माध्यम बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि



भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है और पांडुलिपियां हमारी बौद्धिक विरासत की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से आए लगभग 250 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। दुर्लभ

भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों से जुड़े लगभग 400 मनोहारी चित्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर दोहा और चौपाई के साथ चित्रों का विस्तृत विवरण भी अंकित है, जो इसे बेहद विशेष बनाता है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह

**कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉ. वंदना सिंह ने ज्ञानभारतम् पोर्टल, मोबाइल एप और पांडुलिपि सर्वेक्षण पर विस्तार से जानकारी दी। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. अशोक शतपथी ने पांडुलिपियों की पहचान और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।**

उत्तर प्रदेश पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और शोध के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। युवाओं को अपनी जड़ों और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने में यह अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा।



## लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार 30 मई को CM योगी और रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सीजी सिटी लखनऊ में निर्माणाधीन नौसेना शौर्य संग्रहालय (नौसेना शौर्य वाटिका) का निरीक्षण किया। 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका सिर्फ पार्क नहीं, बल्कि यह हमारी सेना के बहादुर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह राजधानीवासियों के लिए राज्य सरकार का तोहफा है। आगंतुक इस संग्रहालय को देखकर नौसेना के कर्तव्य और पराक्रम पर गर्व करेंगे। गोमती पोत लखनऊ की पहचान बनेगा। साथ ही एक पर्यटन केंद्र के रूप में दर्शकों को आकर्षित करेगा। नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। यह पार्क हमारे समुद्र की रक्षा करने वाली नौसेना की वीरता, शक्ति, पराक्रम और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।

भारतीय नौसेना पोत गोमती 28 मई को राष्ट्र की 34 वर्षों के गौरवशाली सेवा के बाद रिटायर हो

गया था। पार्क में घूमते हुए दर्शकों को वास्तविक नौसैनिक यंत्र दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ भारतीय नौसेना पोत गोमती से संबंधित हैं। यहां दर्शायी गई हर वस्तु समुद्र में जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है। इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2366.92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व स्वीकृति परियोजना 2366.92 लाख

शामिल करते हुए 2366.92 लाख रुपए की धनराशि का संशोधित आगणन कराया गया। इस पर पीएफएडी से 2317.95 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में ओपन एयर म्यूजियम में टीयू-142 विमान की स्थापना और क्यूरेशन कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया

का प्रोपेलर आदि शामिल हैं। लखनऊ स्थित नौसेना शौर्य संग्रहालय में क्यूरेशन कार्य और लखनऊ स्थित शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में टीयू-142 विमान और एसके-42बी हेलीकॉप्टर को स्थानांतरित कर संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार अतनीश



रुपए के तहत प्रथम खंड में ओपन म्यूजियम के लिए 939.76 लाख रुपए और द्वितीय खंड में इंटरप्रिडेशन सेंटर के लिए 1427.16 लाख रुपए की धनराशि शामिल थी। नवीन ड्राइंग/ डिजाइन और प्रथम फेज के कार्यों को

है। भारतीय नौसेना की गोमती पोत पर विभिन्न उपकरण स्थापित किए गए हैं। इनमें लंगर एके-726 मीडियम रेंज तोप, सीईटी-53एम पनडुब्बी अवरोध, जिफ-101 लांचर विथ आरजे, कैपस्टन ड्रम, मुख्य मस्तूल जहाज

अवस्थी, महानिदेशक पर्यटन वेदपति मिश्रा, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल संतोष कुमार सिंह, जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी अय्यर और नौसेना की ओर से कोमोडोर एस. दुरई बाबू उपस्थित रहे।



## गाजियाबाद में जनगणना कार्यों में लापरवाही करने वालों पर DM सख्त, 10 कार्मिकों पर FIR के निर्देश

गाजियाबाद में जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन पूरी कहां से अलर्ट मोड में है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडड़ द्वारा प्रतिदिन जनगणना कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जा सके. जिला प्रशासन की ओर से जनगणना कार्य शुरू होने से पहले ही कार्मिकों को चेतावनी दी गई थी कि किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. वहीं,

अब जिला प्रशासन द्वारा जनगणना के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडड़ ने जनगणना कार्य में लगे दस लापरवाह कार्मिकों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने बताया कि जिले के नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1900 ऐसे कार्मिक हैं, जिन्होंने अभी तक घर-घर जाकर जनगणना कार्य शुरू नहीं किया है. प्रशासन द्वारा जनगणना संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

गए हैं. साथ ही प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी की जा रही है. डीएम ने बताया, लगातार चेतावनी के बावजूद करने में लापरवाही बरतने वाले 10 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. मंगलवार शाम तक सभी दस कर्मचारी के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य है की जनगणना 2027 का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाए. जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ आगे भी एफआईआर

दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. गाजियाबाद में 7 मई से 21 में तक सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य जारी रहा, जबकि 22 में से घर-घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है. जनगणना कार्य शुरू होने के चार दिन बाद भी कई ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने अभी तक फील्ड विजिट कर जानकारी जुटाने का काम शुरू नहीं किया है. 20 जून तक जनगणना का कार्य पूर्ण होना है. जनगणना 2027 के लिए गाजियाबाद में कुल 9456 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है.





## अब घर बैठे होगा किडनी डायलिसिस... आरएनटी मेडिकल कॉलेज में CAPD तकनीक शुरू

झीलों की नगरी उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग ने किडनी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने पहली बार कॉन्टिन्युअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस (सीएपीडी) तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस नई सुविधा से गंभीर किडनी मरीजों को बार-बार अस्पताल आने, लंबी प्रतीक्षा और भारी खर्च की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अब मरीज घर पर स्वयं या परिवार की मदद से डायलिसिस कर सकेंगे।

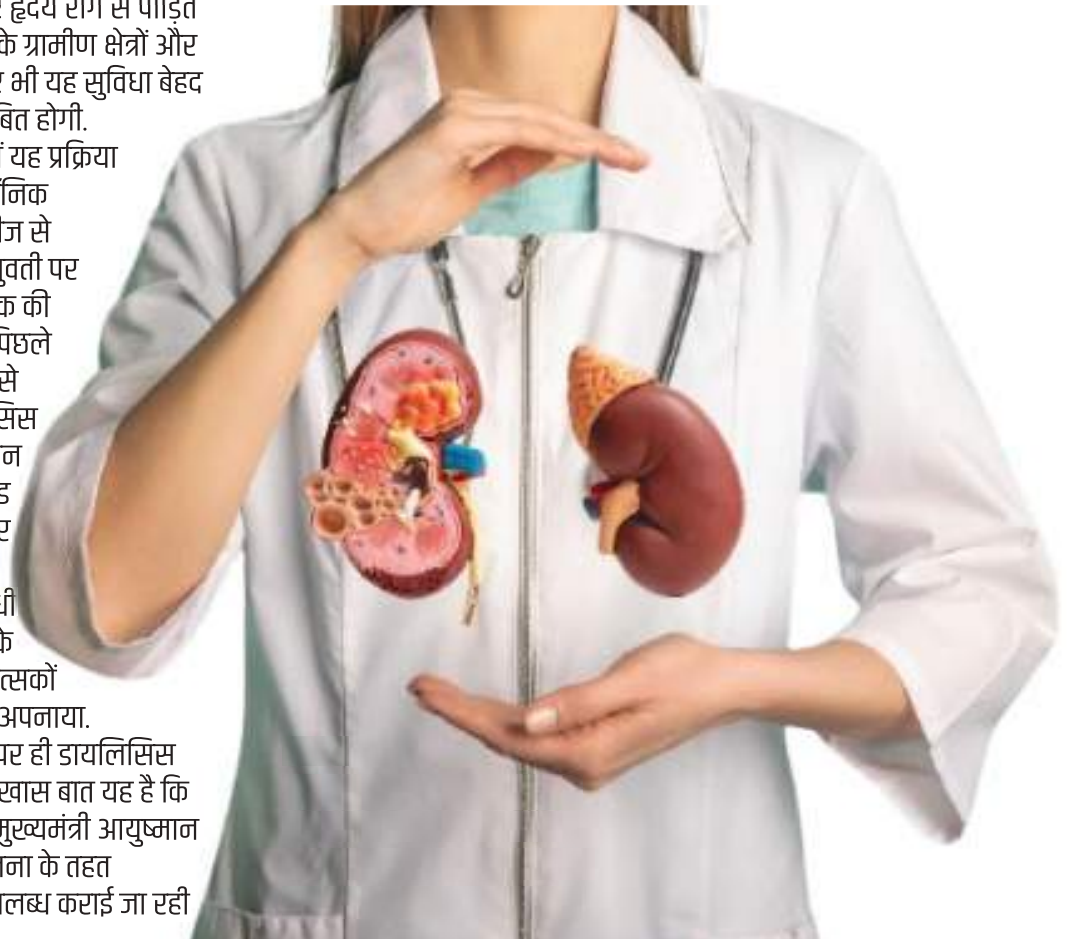
मरीज के पेट में विशेष कैथेटर: नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. पंकज बेनीवाल ने बताया कि सीएपीडी एक आधुनिक डायलिसिस पद्धति है। इसमें मरीज के पेट में विशेष कैथेटर लगाया जाता है, जिसके जरिए डायलिसिस द्रव शरीर में पहुंचाया जाता है। यह द्रव विषैले तत्वों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है। उचित प्रशिक्षण के बाद मरीज इसे घर पर सुरक्षित रूप से कर सकता है। यह तकनीक खासतौर पर

उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिनका हेमोडायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर बार-बार गिर जाता है, नसों में डायलिसिस एक्सेस बनाना मुश्किल होता है या जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और बच्चों के लिए भी यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी।

विभाग में यह प्रक्रिया 21 वर्षीय क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित एक युवती पर सफलतापूर्वक की गई। मरीज पिछले तीन महीने से हेमोडायलिसिस पर थी, लेकिन बार-बार ब्लड प्रेशर अस्थिर होने और एक्सेस संबंधी समस्याओं के कारण चिकित्सकों ने सीएपीडी अपनाया। अब वह घर पर ही डायलिसिस कर सकेगी। खास बात यह है कि यह सुविधा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही

है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल जैन ने इसे संभाग के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के मरीजों के लिए बड़ी राहत बताया। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अधीक्षक डॉ.

राज डामोर सहित पूरी विशेषज्ञ टीम और स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई। यूपी में मेडिकल के छात्रों में बहुत खुशी भी दी जा रही है।





# किशनगंज एयरपोर्ट रनवे विस्तार को मंजूरी भूमि अधिग्रहण के लिए मिली 5.45 करोड़ स्वीकृत

बिहार सरकार ने किशनगंज हवाई अड्डे के रनवे विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सिविल विमानन विभाग ने 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ 45 लाख 97 हजार 100 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह द्वारा 21 मई 2026 को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई। यह स्वीकृति जिलाधिकारी किशनगंज के दिसंबर 2024 के प्रस्ताव पर आधारित है। रनवे विस्तार के तहत पूर्व दिशा में 700 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 17.29 एकड़ भूमि तथा पश्चिम दिशा में 300 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 7.41 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। अधिग्रहित भूमि में रैयती जमीन के साथ बीएसएफ की भूमि भी शामिल है। अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आवासीय विकासशील श्रेणी में एमवीआर दर से मुआवजे का आकलन किया गया है। सरकार ने स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट मद "5302-भू-अर्जन" से जारी करने का निर्णय लिया है। सिविल विमानन विभाग ने भू-अर्जन पदाधिकारी किशनगंज के

पीडी/पीएल खाते में राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है। इस खाते का नाम "प्रोजेक्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रनवे ऑफ किशनगंज एयरपोर्ट" रखा गया है।

केवल रनवे विस्तार पर होगी राशि खर्च: जारी आदेश में साफ निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग सिर्फ रनवे विस्तार परियोजना के लिए ही

किशनगंज स्थित चिकन नेक क्षेत्र नेपाल और बांग्लादेश से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। गृह मंत्रालय की लगातार नजर में रहने वाले इस क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रनवे विस्तार से बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। रनवे विस्तार के बाद

ने इस संबंध में जारी पत्र का हवाला देते हुए जनता को इस उपलब्धि की जानकारी दी।

दिलीप जयसवाल, बिहार सरकार मंत्री के मंत्री ने कहा कि किशनगंज एयरपोर्ट का रनवे विस्तार सीमांचल के विकास का नया अध्याय है। चिकन नेक क्षेत्र अब हवाई संपर्क से जुड़कर तेजी से आगे बढ़ेगा। यह स्वीकृति किशनगंज एयरपोर्ट को क्षेत्रीय हब



**2026 को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई। यह स्वीकृति जिलाधिकारी किशनगंज के दिसंबर 2024 के प्रस्ताव पर आधारित है। रनवे विस्तार के तहत पूर्व दिशा में 700 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 17.29 एकड़ भूमि तथा पश्चिम दिशा में 300 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में 7.41 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी।**

किया जाएगा। किसी अन्य मद में खर्च की अनुमति नहीं होगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र और व्यय विवरणी निर्धारित समयसीमा के अंदर महालेखाकार तथा विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

किशनगंज समेत पूरे सीमांचल क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपातकालीन सेवाओं और रक्षा संबंधी गतिविधियों में भी सुविधा बढ़ेगी। मंत्री दिलीप जयसवाल

बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की संभावना है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और समग्र विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।



## दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 2: मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर... दूसरे दिन गिरी कमाई, फिर भी 100 करोड़ के करीब फिल्म

**सा** उथ सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर क्राइम थ्रिलर मसाला फिल्म लेकर थिएटर में लौटे हैं। दृश्यम 3 बीती 21 मई को एक्टर के बर्थडे के मौके पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर डाला। दृश्यम 3 ने 50 करोड़ रुपये से खाता खोला और मलयालम सिनेमा में कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना डाले। मलयालम थ्रिलर ने शुक्रवार को हर जगह जबरदस्त कमाई की और दो दिनों में वैश्विक स्तर पर 75.94 करोड़ रुपये और भारत में 30.94 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी। यह फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब इसे भारत और विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए दो दिन का शानदार वीकेंड मिल रहा है। फिल्म ने दूसरे दिन 10.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो पहले दिन के कलेक्शन से थोड़ा कम है। फिल्म ने दुनिया भर में 75.94 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें से 45 करोड़ रुपये अकेले ओवरसीज से कमाए हैं। दरअसल, फिल्म ने दूसरे दिन विदेशों में भारत से ज्यादा (20 करोड़ रुपये) की कमाई की, जो एक शानदार अचीवमेंट है।

**दृश्यम 3 को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से काफी पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं। इस फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी साख और मोहनलाल की वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी है।**

### वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर हाल



यह देखना दिलचस्प होगा कि शनिवार और रविवार को यह फिल्म कितने नए रिकॉर्ड बनाती है। यह पहले ही मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पेट्रियट' (जो 22 दिन पहले रिलीज हुई थी) के बाद इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है। दृश्यम 3, जिसकी कहानी दृश्यम 2 के अंत से शुरू होती है, में मोहनलाल अपने शानदार किरदार जॉर्जकुट्टी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अब एक फिल्म निर्माता हैं। इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है और इसमें आशा सरथ, मीना, कृष्णा प्रभा और वीना नंदकुमार सहित अन्य कलाकार भी हैं।



## नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'नल-जल' योजना का अजब तमाशा! कागजों पर दौड़ रहा पानी, धरातल पर प्यासे लोग

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल-जल' अब मुंगेर के कई इलाकों में गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल यह योजना राज्य की 'सात निश्चय योजना' का एक बेहद अहम हिस्सा है। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए राज्य के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। सर्वेक्षण में हुआ बड़ा खुलासा: अब राज्य के कई जिलों से इस योजना में भ्रष्टाचार, अधूरे निर्माण कार्य और बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में भी यह बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्य के कई जगहों पर सिर्फ पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दी गई है। ताजा मामला मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोबड़ा पंचायत का सामने आया है। इस सर्वे के अनुसार पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन धरातल पर पानी की आपूर्ति कभी शुरू ही नहीं हो सकी। कहीं मोटर खराब पड़ी है तो कहीं पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा लटका हुआ है। क्षेत्र की कई पंचायतों में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाने के बावजूद लोग आज भी

शुद्ध पानी के लिए बुरी तरह परेशान हैं। कागजों तक सीमित हुई खानापूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों के अनुसार, कई गांवों में केवल खानापूर्ति के लिए पाइपलाइन और टोटी लगा दी गई, लेकिन जलापूर्ति व्यवस्था कभी चालू ही नहीं हुई। कुछ जगहों पर कार्य पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में संवेदकों

हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तीन साल पहले ही गांव के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला। इस भीषण मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी खरीदकर अपने घर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। ग्रामीण रुपेश कुमार, मौलेश्वरी

शुरु नहीं हो सकी। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि आधे गांव में तो अभी तक पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है, जिससे योजना अधूरी अवस्था में ही छोड़ दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शुद्ध पानी की भारी समस्या है, जिससे मजबूरी में उन्हें करीब छह किलोमीटर दूर खड़गपुर बाजार से 20 लीटर पानी का जार खरीदकर लाना पड़ता है। एक जार की कीमत 20



ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। योजना का लाभ कागजों पर दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हर घर नल-जल योजना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जल्द से जल्द गांव में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। पूरे मामले पर हवेली खड़गपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप लगे हैं। जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गोबड़ा पंचायत स्थित लडुई गांव में भी स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही

यादव, कदमी देवी, सरवर मंडल और संतोष यादव ने बताया कि करीब तीन साल पहले संवेदक द्वारा गांव के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई गई थी। कई घरों में टोटी भी लगा दी गई, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति

रुपये हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पानी के जार को गांव तक पहुंचाने में अलग से करीब 20 रुपये का किराया देना पड़ता है। इस तरह एक परिवार को प्रतिदिन पीने के पानी पर भारी खर्च उठाना पड़ रहा है।



## जनसुनवाई में पहुंचे परिवार का बहू पर मारपीट का आरोप सैया तू काला मैं गोरी, तेरे साथ ना रहूंगी

बेटे से मारपीट करती है बहू, खाना भी नहीं देती. ग्वालियर में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक परिवार अपनी बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस के आगे मदद की गुहार लगाने पहुंचा. उनका कहना था कि बहू बेटे के साथ नहीं रहना चाहती. वह उसके साथ मारपीट करती है. कहती है कि बेटा काला है और वह गोरी है, इसलिए साथ नहीं रहेगी. उसने पहले ही घर का बंटवारा करवा दिया और अब अपने पति से मंहंगी मंहंगी डिमांड करती है. पुलिस ने भी आवेदन लेकर मामले की जांच कराने की बात कही है. ग्वालियर के गौसपुरा में रहने वाले एक परिवार ने अपने बेटे की शादी 2 साल पहले की थी. अपनी बहू से परेशान सास मंगलवार को जनसुनवाई में बेटे को लेकर पहुंची और बहू पर कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया. इस दौरान उसका बेटा और बड़ी बहू भी साथ थी.

शिकायतकर्ता महिला का आरोप है, "उसके बेटे की पत्नी ने अब पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है. वह आए दिन बेटे के साथ मारपीट करती है, घर के रोज

के झगड़ों को देखते हुए परिवार ने बहू और बेटे के अलग रहने की व्यवस्था कर दी. रसोई भी अलग बनवा दी लेकिन ना तो बहू अपने पति को खाना देती है और ना ही नौकरी करने जाने देती है बल्कि उससे आईफोन, एसी, आरो, बड़ा घर जैसे चीजों की डिमांड करती है." फरियादी महिला का यह भी आरोप है, "बहू उनके परिवार को

सब परिवार से अलग होने के लिए कर रही है. कहती है कि उसका पति काला है और वह गोरी है, इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहती."

जब पीड़ित परिवार ने बहू की हरकतों से तंग आकर उसके माता-पिता से बात करने का प्रयास किया तो वह भी सीधे मुंह बात नहीं करते बल्कि धमका रहे हैं कि, पूरे परिवार को झूठा

संबंध में ग्वालियर के किला गेट पुलिस थाने में भी शिकायत की थी. अब अपनी परेशानी को लेकर जनसुनवाई में भी आवेदन दिया है. इस मामले को लेकर सीएसपी कृष्ण पाल सिंह का कहना है, "गौसपुरा से एक आवेदन आया है जिसमें फरियादी ने अपनी बहू के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की है. आवेदन ले लिया



मंहंगी मंहंगी डिमांड करती है. पुलिस ने भी आवेदन लेकर मामले की जांच कराने की बात कही है. ग्वालियर के गौसपुरा में रहने वाले एक परिवार ने अपने बेटे की शादी 2 साल पहले की थी. अपनी बहू से परेशान सास मंगलवार को जनसुनवाई में बेटे को लेकर पहुंची और बहू पर कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया. इस दौरान उसका बेटा और बड़ी बहू भी साथ थी.

झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, आए दिन बेटे से मारपीट भी करती है. उन्हें परेशान करने के लिए उसने खुद फांसी लगाने की भी कोशिश की और परिवार को फंसाने का प्रयास किया. वह ये

केस लगाकर जेल भेज देंगे. इन हालातों से अब परिवार तंग आ चुका है और समझने पर भी उनकी बहू उल्टा कहती है कि वह इसी तरह से व्यवहार करेगी कोई कुछ नहीं कर पाएगा. उन्होंने इस

गया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फरियादी पक्ष ने जो तथ्य बताए हैं उनकी संबंधित थाने से भी जांच कराई जाएगी और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी."



## 48 घंटे बिना हिले-डुले छत पर लेटे रहे, आतंकी आए तो... पल में ठोक दिया, पैटागन में दिया लेक्चर

पैरा एसएफ भारतीय सेना की अजेय परंपरा है. इसी एसएफ यूनिट के कर्नल हेमोन्टो पैंगिंग नाइन पैरा एसएफ के मेजर सुधीर वालिया को याद करते हुए कहते हैं-मेजर सुधीर सर, भारतीय सेना के ब्रेवैस्ट ऑफ दि ब्रेव थे. उन्हें एक सूचना मिली थी कि एक दुकान में आतंकी आते हैं. मेजर सुधीर उस दुकान की छत पर बैठ गए. छत की सीलिंग पतली लकड़ी की थी. मेजर सुधीर सर 48 घंटे बिना हिले-डुले छत पर रहे ताकि किसी को भनक न लगे. यूरिन भी उन्होंने एक बॉटल में किया. जैसे ही आतंकी आए तो मेजर सुधीर ने छत की सीलिंग से ही तीन आतंकियों को ठोक दिया. कर्नल पैंगिंग के पास मेजर सुधीर वालिया की बहादुरी के कई किस्से हैं. वर्ष 1996 में अकेले मेजर सुधीर ने पांच में से तीन आतंकियों को मारा था. उन आतंकियों ने भारतीय सेना की घातक टुकड़ी पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था. उस ऑपरेशन में कर्नल पैंगिंग भी सुधीर वालिया के साथ थे.

खुद वीरता की देवी जिसकी शौर्य गाथा गाए, मां भारती के उस सपूत का नाम था मेजर सुधीर वालिया. भारतीय सेना का रैंबो, ब्रेवैस्ट ऑफ ब्रेव, लॉयन ऑफ इंडियन आर्मी जैसे अनेक नामों से अलंकृत भारत मां के इस वीर की कहानियां अभी भी सेना के पैरा एसएफ जवानों व अफसरों को रोमांचित करती हैं. मेजर सुधीर वालिया के

शौर्य किस्सों से आज इंटरनेट की दुनिया भरी पड़ी है. गूगल या यू-ट्यूब पर सिर्फ मेजर सुधीर वालिया लिखें और आपके पास एक पल में सैंकड़ों कंटेंट आ जाते हैं. इन्हीं अमर बलिदानों मेजर सुधीर वालिया की आज जयंती है. यहां उनकी वीरता के कुछ किस्से दर्ज करना कृतज्ञ देश की आदरांजलि होगी.

मेजर सुधीर वालिया...रक्षा मंत्रालय का पन्ना खोलिए और उनके बारे में सर्व

(सीडबलओएमएआर) में उनके जीवन के अनछुए पहलू हैं. एनडीए खडकवासला में उनके सम्मान और स्मृति में एक पोर्ट्रेट स्थापित किया गया है. दो बार सेना मेडल और अशोक चक्र (बलिदान उपरांत) से सम्मानित मेजर सुधीर वालिया तत्कालीन भारतीय सेना के मुखिया जनरल वीपी मलिक के ओएसडी रहे. करगिल वार में जूनू टॉप पर क जा करने वाले मेजर सुधीर वालिया ने विजय दिवस के एक

पैरा एसएफ यूनिट से थे. उन्होंने दो बार सियाचिन में सेवाएं दीं. वे करगिल युद्ध में जिद करके अपनी इच्छा से गए थे. वे उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक के ओएसडी थे. जनरल मलिक ने अपनी किताब में मेजर सुधीर वालिया पर खूब लिखा है. मेजर सुधीर वालिया भारतीय सेना के अकेले ऐसे अफसर थे, जो अमेरिका में अस्सी देशों के स्पेशल फोर्सिज के कमांडो के ट्रेनिंग



**मेजर सुधीर वालिया के शौर्य की कहानियां अनेक हैं. उसके लिए पाठक इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं. यहां ईटीवी भारत हिमाचल व देश की माटी के लाल को उनकी जयंती पर कृतज्ञता अर्पित करता है. वर्ष 1999 में अगस्त महीने में हफुरदा के जंगलों में आतंकियों का सफाया करते हुए मेजर सुधीर वालिया ने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया. मां भारती का ये वीर सपूत इस समय परमसत्ता की गोद में विश्राम पा रहा है.**

कीजिए. नाइन पैरा-एसएफ के रत्न अमर बलिदानों मेजर सुधीर वालिया पर जितना लिखा जाए उतना कम है. रैंबो नाम से उन पर कर्नल आशुतोष काले की पुस्तक मेजर वालिया के शौर्य किस्सों का संकलन है. जयश्री लक्ष्मीकांत की पुस्तक कुमार

महीने बाद कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दे दिया. पैरा एसएफ में आने वाले हर भारतीय वीर के लिए मेजर सुधीर वालिया आदर्श हैं.

मेजर सुधीर वालिया हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के बन्डूरी से थे. वे नाइन

प्रोग्राम में सर्वश्रेष्ठ चुने गए थे. उनकी अतुलनीय मेधा को देखते हुए अस्सी देशों के कोर्समेट उन्हें सम्मान से कर्नल कहते थे. कोर्स पूरा होने पर मेजर सुधीर वालिया को पैटागन अमेरिका के सेना मुख्यालय में स्पीच देने का गौरव मिला था.



# Satellite News Channel 24X7

Also Available on All Leading  
MSO & OTT Platform



**658**



**TATA | sky**  
coming soon

Also Available on cable network



@raftaarmedia 
 @raftaarmedia 
 @raftaarmedia 
 @raftaarmedia47

[www.raftaarmedia.com](http://www.raftaarmedia.com)



## करनाल की महिला क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ऑस्ट्रेलिया-बैंकॉक में रची गई मर्डर की साजिश

हरियाणा के करनाल के सेक्टर-9 में हुए चर्चित क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. पुलिस के मुताबिक इस सनसनीखेज हत्या की साजिश विदेश में रची गई, जबकि वारदात को अंजाम देने के लिए पेशेवर शूटर का इस्तेमाल किया गया. मामले में गिरफ्तार आरोपी शूटर विकास को अदालत में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े हर किरदार और इस्तेमाल किए गए हथियारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. डीएसपी राजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 15 मई को करनाल के सेक्टर-9 इलाके में बिजली निगम की क्लर्क डिंपल अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात को एक युवक ने गन पॉइंट पर अंजाम दिया था. घटना के बाद सीआईए-1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए लाडवा के गांव सलेमपुर निवासी आरोपी शूटर विकास को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में दो गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने 25 मई को आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और अब कोर्ट से उसकी 6 दिन की रिमांड हासिल कर ली है. पुलिस जांच

में सामने आया है कि मृतक महिला के पड़ोसी विकास पुत्र इंदर सिंह का परिवार लंबे समय से पार्किंग विवाद को लेकर पीड़ित परिवार से रंजित रखता था. इस विवाद को लेकर सेक्टर-9 थाने में कई शिकायतें भी दर्ज हुई थीं. डीएसपी राजीव के अनुसार इसी दौरान पड़ोसी इंदरजीत की मौत हो गई थी और आरोपी विकास को ये शक था कि लगातार हो रही शिकायतों के कारण

लाडवा के सलेमपुर निवासी विकास से हुई. दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई. पुलिस के मुताबिक पड़ोसी विकास ने आर्थिक रूप से शूटर विकास की मदद की थी और इसी संबंध के चलते शूटर ने महिला की हत्या को अंजाम दिया. डीएसपी राजीव ने बताया कि अब इस मामले में इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के माध्यम से विदेश में बैठे आरोपी तक

पहले भी हत्या के मामले में दोषी है और सजा काट रहा था. वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था. बताया गया कि आरोपी दो बार पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुका था, जबकि तीसरी बार पैरोल मिलने के बाद वो फरार हो गया था. उसके खिलाफ पहले से कई अपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. एक और वारदात की थी तैयारी : डीएसपी राजीव ने खुलासा किया कि



**पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने पर इतनी बड़ी वारदात करवाई गई, वह विदेश में बैठा हुआ है. इस पर डीएसपी राजीव ने कहा कि परिवार को खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि करनाल पुलिस हर गंभीर अपराध को सुलझाने में सक्षम रही है और इस मामले में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.**

ही उसके पिता की मौत हुई. इसी रंजित ने धीरे-धीरे हत्या की साजिश का रूप ले लिया. पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि पड़ोसी विकास कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया गया था. इसके बाद वो बैंकॉक पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात

पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि साजिशकर्ता को भी जल्द गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा. पहले भी हत्या मामले में सजा काट रहा था आरोपी : पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शूटर विकास

महिला हत्याकांड के बाद आरोपी किसी अन्य बड़ी वारदात को भी अंजाम देने की तैयारी में था. पुलिस अब रिमांड के दौरान उससे इस पूरे नेटवर्क और संभावित अगली साजिश के बारे में पूछताछ करेगी.



## धनबाद का मेयर बदलते ही चर्चा में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', जाने कौन हैं शहर के नए 'सरकार' संजीव सिंह

कोयलांचल की सियासत में 'सिंह मेशन' की धमक एक बार फिर पूरे शबाब पर है। धनबाद नगर निगम के चुनाव परिणामों ने न केवल राज्य की सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को चौंका दिया है, बल्कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जबरदस्त वापसी पर मुहर लगा दी है। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के त्रिकोणीय घेराबंदी को ध्वस्त करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी संजीव सिंह ने मेयर की कुर्सी पर क जा जमा लिया है। इस जीत के साथ ही धनबाद की गलियों में एक बार फिर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'सिंह मेशन' के रसूख की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस चुनाव में संजीव सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी शनिवार देर रात घोषित परिणामों के अनुसार, संजीव सिंह को कुल 1,14,362 वोट मिले। यह धनबाद नगर निगम के इतिहास में पहली बार है जब किसी प्रत्याशी ने एक लाख से अधिक मतों का आंकड़ा पार किया है। दूसरी ओर, झामुमो समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460 वोट

मिले, जबकि कांग्रेस के शमशेर आलम 59,079 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार का

आते हैं, जिसकी नींव उनके पिता और मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह ने रखी थी। सूर्यदेव सिंह झरिया से कई बार विधायक रहे और धनबाद की राजनीति में दशकों

से प्रेरित बताया जाता है। संजीव की इस जीत ने यह संदेश दिया है कि सिंह मेशन का दबदबा न केवल झरिया तक सीमित है, बल्कि अब पूरे धनबाद शहर में इसकी

### संजीव सिंह की जीत के 5 बड़े कारण



संजीव सिंह की जीत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। इसके पीछे निम्नलिखित पांच मुख्य कारक रहे: युवाओं की गोलबंदी: सोशल मीडिया पर संजीव सिंह के पक्ष में एक लहर देखी गई। युवाओं के एक बड़े वर्ग ने न केवल उनके पक्ष में प्रचार किया, बल्कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर जीत सुनिश्चित की। सहानुभूति लहर: संजीव सिंह करीब 8 साल जेल में रहे। नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट से बरी होने के बाद जनता के एक बड़े हिस्से में यह संदेश गया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। निर्दलीय होने के बावजूद संजीव सिंह ने भाजपा के पारंपरिक वोटों में बड़ी संधमारी की। धनबाद और बाघमारा जैसे क्षेत्रों में भी उन्हें अप्रत्याशित समर्थन मिला। सांसद दुलू महतो के आक्रामक बयानों को संजीव समर्थकों ने 'बाहरी बनाम भीतरी' का मुद्दा बना दिया, जिससे स्थानीय मतदाताओं का झुकाव संजीव की ओर हुआ। चुनाव

के दौरान सभी बड़े दलों के निशाने पर अकेले संजीव सिंह थे। इस चौतरफा हमले ने मतदाताओं के मन में संजीव को एक 'अकेले योद्धा' के रूप में स्थापित कर दिया। संजीव सिंह का हालिया इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्हें 2017 में अपने चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। अप्रैल 2017 से अगस्त 2025 तक वे न्यायिक हिरासत में रहे। 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत दी थी। इसके तुरंत बाद, 27 अगस्त 2025 को धनबाद की विशेष MP-MLA कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या की साजिश का कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। जेल से बाहर आने के ठीक बाद इस बड़ी जीत ने उनके राजनीतिक करियर को नई दिशा दे दी है।

रहा, जो सांसद और विधायकों की पूरी फौज के प्रचार के बावजूद मात्र 57,895 वोट पाकर चौथे स्थान पर खिसक गए। संजीव सिंह 'सिंह मेशन' परिवार से

तक उनका एकछत्र राज रहा। बॉलीवुड की महशूर फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में रामाधीर सिंह का किरदार काफी हद तक सूर्यदेव सिंह के जीवन और रसूख

धमक बढ़ी है। बता दें कि संजीव सिंह के परिवार का झरिया में विधायकी कायम है। फिलहाल उनकी पत्नी रागिनी सिंह यहां से बीजेपी की विधायक हैं।



## पलामू टाइगर रिजर्व में बीड़ी पत्ता माफिया सक्रिय प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से टूट रहा बीड़ी पत्ता

पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया कहने के लिए तो पूरी तरह प्रोटेक्ट वन क्षेत्र है। लेकिन यहां बीड़ी पत्ता माफिया सक्रिय हैं। यहां प्रतिदिन बड़े पैमाने पर बीड़ी पत्ता की अवैध तुड़ाई हो रही है। इससे जहां जंगल को नुकसान हो रहा है, वहीं जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी दावा करते हैं कि बीड़ी पत्ता की तुड़ाई कराने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके को सरकार ने पूरी तरह प्रोटेक्ट वन क्षेत्र घोषित कर रखा है। जंगल और जंगल के उत्पादन की किसी भी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रखी गई हैं। इसी कारण जब बीड़ी पत्ता का सीजन आता है तो सामान्य जंगलों में बीड़ी पत्ता तुड़ाई के लिए टेंडर होता है। लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में बीड़ी पत्ता तोड़ने के लिए टेंडर भी नहीं किया जाता है। सरकार के इतने प्रतिबंध के बावजूद बीड़ी पत्ता माफिया पीटीआर के जंगलों में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन बीड़ी पत्ता की तुड़ाई करवा रहे हैं। बीड़ी पत्ता का सीजन आने के बाद कई बीड़ी पत्ता कारोबारी इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। इन्हीं बीड़ी पत्ता कारोबारी के

द्वारा गांव के किसी व्यक्ति को पैसे देकर मजदूरों से बीड़ी पत्ता की तुड़ाई कराई जाती है। गांव के मजदूर घने जंगलों में जाकर बीड़ी पत्ता तोड़कर लाते हैं और उसे कारोबारी के दलाल को बेचते हैं। ग्रामीण को 100 पोला बीड़ी पत्ता बेचने पर 200 से 250 रुपए की आमदनी होती है। एक पोला में लगभग 52 पत्ता

गया है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित पीरी समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में भी बड़े पैमाने पर अवैध बीड़ी पत्ता के खलिहान लगे हुए हैं। इन इलाकों में लगे खलिहानों में पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों से तोड़कर ले गए बीड़ी पत्ता सुखाए जाते हैं। इधर पीटीआर के इलाके में धड़ल्ले

कि पीटीआर एरिया में खुलेआम अवैध रूप से बीड़ी पत्ता की तुड़ाई की जा रही है। मामले की शिकायत सांसद कालीचरण सिंह से भी लिखित रूप से की गई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की मिलीभगत के कारण पीटीआर के जंगल को नुकसान हो



**मामले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेंजर उमेश दुबे ने बताया कि पीटीआर के इलाके में बीड़ी पत्ता तोड़ना या खलिहान लगाना दोनों पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।**

होता है। वर्तमान समय में पलामू टाइगर रिजर्व से सटे हुए हाटा, होसिर, हुम्मामारा, शिवचरण टोला, कुमंडीह, आतीखेता, बड़काडीह, ओपाग समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर बीड़ी पत्ता का खलिहान भी लगाया

से अवैध रूप से बीड़ी पत्ता की तुड़ाई की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी करते हैं। मनिका प्रखंड के भाजपा मंडल अध्यक्ष मंदीप कुमार ने इस संबंध में एक लिखित आवेदन सांसद को भी दिया है। मंदीप कुमार ने बताया

रहा है। वहीं इस संबंध में पूछने पर पलामू टाइगर रिजर्व के रेंजर अजय टोप्पो ने बताया कि अवैध बीड़ी पत्ता तोड़ने वाले और इसके कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम बनाई जा रही है।



# सुपारी देकर रची गई थी हत्या की साजिश खूंटी पुलिस ने शूटर समेत दो को दबोचा

जिला में जमीन विवाद में सुपारी देकर करार गए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करार थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में 18 मई को हरमन होरो पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और शूटर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता में बताया कि पदमपुर गांव निवासी हरमन होरो का राहुल मुंडा उर्फ नन्दू के साथ लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में राहुल मुंडा ने हरमन होरो की हत्या कराने के लिए अपराधियों को 1 लाख 20 हजार रुपये की सुपारी दी थी। इसमें से 20 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे। पुलिस के अनुसार, इससे पहले भी हरमन होरो की हत्या की कोशिश की गई थी लेकिन अपराधी सफल नहीं हो पाए थे। एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तोरपा डीएसपी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और अनुसंधान के

आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल मुंडा उर्फ नन्दू और शूटर रमेश तिकी उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार रमेश तिकी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि राहुल मुंडा पदमपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पदमपुर

ऋषभ गर्ग से जब जिला में लगातार एक जैसे हथियार मिलने और उनके पीएलएफआई उग्रवादियों से संबंध को लेकर सवाल पूछा गया। इसपर उन्होंने कहा कि पिस्तौल पर बने चिन्हों से ऐसा प्रतीत होता है कि हथियार बनाने वाला कारीगर एक ही हो सकता है। हालांकि, पीएलएफआई से किसी सीधे

एसपी ने बताया कि इस गोलीकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई में तोरपा डीएसपी विजय कुमार सिंह, करार थाना प्रभारी राजू कुमार, पुअनि जुगेथ सिंह, पुअनि जितेन्द्र राम, सअनि मनोरंजन सिंघु और करार



मुख्य आरोपी राहुल मुंडा उर्फ नन्दू और शूटर रमेश तिकी उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार रमेश तिकी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि राहुल मुंडा पदमपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पदमपुर जंगल में छिपाकर रखी गई एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। हथियार बरामदगी को लेकर करार थाना में अलग से मामला भी दर्ज किया गया है।

जंगल में छिपाकर रखी गई एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। हथियार बरामदगी को लेकर करार थाना में अलग से मामला भी दर्ज किया गया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान एसपी

संबंध की पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में किसी मिनी गन फैक्ट्री की सूचना फिलहाल नहीं है लेकिन अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

थाना के रिजर्व गार्ड के जवान शामिल रहे। करार थाना प्रभारी राजू कुमार, पुअनि जुगेथ सिंह, पुअनि जितेन्द्र राम, सअनि मनोरंजन सिंघु और करार थाना के रिजर्व गार्ड के जवान शामिल रहे।



## थारु जनजाति जमीन मामले में सीएम धामी का कांग्रेस पर तंज बताया नई बोतल में पुरानी शराब भरने का प्रयास

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे के दौरान ब्लॉक सभागार में स्थानीय पंचायत एवं निकाय जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं के बयानों पर तंज कसा. उन्होंने साल 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के थारु जनजाति की जमीनों के छीनने के बयान पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को नई बोतल में पुरानी शराब भरने के समान बताया. कहा कि साल 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी. सीएम धामी ने कांग्रेस का बयान रुपी सिक्का एक बार ही चलने की बात कही. गौर हो कि उत्तराखंड में थारु जनजाति समाज के जमीन मामले में कांग्रेस के वार पर सीएम धामी ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के बयानों को आड़े हाथों लिया है. सीएम धामी ने खटीमा

जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान अपने संबोधन में कहा कि बीते रोज खटीमा में कांग्रेस के एक सम्मेलन में एक बार फिर कांग्रेस ने 2022 का पुराना राग अलापने का काम किया है. खटीमा क्षेत्र में जमीनों को छीनने के विषय को

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा उधम सिंह नगर में एक लाख बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रही है, 4000 से अधिक सीलिंग की भूमि पर पट्टे दिए गए हैं. फिर किसी की जमीन छीनने का सवाल कहां उठता है.

किया कि उनके रहते खटीमा में किसी के भी हित प्रभावित नहीं होने देंगे. कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी भ्रम फैलाएं. 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी. सीएम धामी ने



शराब भरने के समान बताया. कहा कि साल 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी. सीएम धामी ने कांग्रेस का बयान रुपी सिक्का एक बार ही चलने की बात कही. गौर हो कि उत्तराखंड में थारु जनजाति समाज के जमीन मामले में कांग्रेस के वार पर सीएम धामी ने पलटवार किया है.

उठा नई बोतल में पुरानी शराब भरने का प्रयास किया है. उन्होंने 2022 चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा इस तरह के भ्रम को फैलाकर नैरेटिव सेट करने की बात कही थी. सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पूछा कि बीते साढ़े चार साल में किसी भी थारु जनजाति की कोई जमीन छीनी है क्या खटीमा में? सीएम धामी ने मंच से सभी को आश्चस्त

कांग्रेस का बयान रुपी सिक्का एक बार ही चलने की बात कही. गौर हो कि उत्तराखंड में थारु जनजाति समाज के जमीन मामले में कांग्रेस के वार पर सीएम धामी ने पलटवार किया है.



इस मौसम में विशेष

देखभाल की जरूरत

## नैनीताल में ये क्या हो गया, अचानक बीमार पड़ रहे बच्चे, रोजाना 40 से ज्यादा ओपीडी में आ रहे, जानें क्या है कारण?

नैनीताल. उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है. बीते कुछ दिनों से तापमान में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सुबह और शाम में ठंडक, जबकि दिन में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है. इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जो तेजी से वायरल बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, रोजाना अस्पताल की ओपीडी में 40 से 50 तक बच्चे पहुंच रहे हैं. इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया और वायरल इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस समय नैनीताल में आने वाले पर्यटकों के बच्चे भी बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं, जो इस स्थिति को और चिंताजनक बना रहा है. नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविन्द्र मेर के मुताबिक, मौसम में अचानक बदलाव और हाल ही में हुई बारिश के कारण बच्चों की इम्यूनिटी पर असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि मेडिकल

साइंस में इसे वायरल इलनेस कहा जाता है. इस समय जो केस सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं. रोजाना करीब 40 से 50 बच्चे ओपीडी में आ रहे हैं, जिनमें लगभग 40

को एडजस्ट करने में परेशानी होती है, जिससे वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. इस समय नैनीताल में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जहां सुबह-शाम ठंडी हवाएं

मेर ने कहा कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां नहीं देनी चाहिए. कई बार लापरवाही भारी पड़ सकती है. अगर बच्चे में लगातार बुखार, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर



बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. बच्चों को ताजा और साफ खाना देना चाहिए, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना चाहिए. साथ ही, बच्चों को मौसमी फल खिलाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. पर्यटकों के लिए भी डॉक्टर मेर ने कहा कि जो लोग इन दिनों नैनीताल घूमने आ रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मौसम के अनुसार कपड़े पहनाना, ठंडी हवाओं से बचाव और खानपान में सावधानी बेहद जरूरी है.

प्रतिशत मामले वायरल इन्फेक्शन के हैं. डॉक्टर मेर ने यह भी बताया कि इन मामलों में स्थानीय बच्चों के साथ-साथ पर्यटकों के बच्चे भी शामिल हैं. लगभग रोजाना 3 से 4 केस ऐसे आ रहे हैं, जो बाहर से आए पर्यटकों के बच्चों के हैं. अचानक मौसम बदलने के कारण बच्चों

चल रही हैं, वहीं दिन में धूप के कारण हल्की गर्मी महसूस होती है. इस तरह का मौसम छोटे बच्चों के लिए अनुकूल नहीं होता, जिससे वे जल्दी सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार की चपेट में आ जाते हैं. डॉक्टरों ने अभिभावकों को खास सतर्क रहने की सलाह दी है. डॉक्टर रविन्द्र

से संपर्क करना जरूरी है. उत्तराखंड के नैनीताल में अचानक मौसम बदलने से छोटे बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है. जिला अस्पताल के अनुसार रोजाना 40-50 बच्चे ओपीडी में आ रहे हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन के मामले अधिक हैं.



**फ्रिज का पानी काफी**

**नुकसानदायक**

## गर्मी में आप भी पीते हैं फ्रिज का पानी तो हो जाएं सावधान एक्सपर्ट से जानिए- क्या हैं मटके के पानी के फायदे

राजधानी दिल्ली में हीट वेव का कहर जारी है. सुबह 11:00 के बाद घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है तेज धूप और गर्म हवाएं दोपहर में दिल्ली के लोगों पर गहरा असर डाल रही है, जिसकी वजह से अब कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं. आम तौर पर उनके बीमार पड़ने की सबसे बड़ी वजह बाहर से चलकर आकर आते ही फ्रिज का पानी पीना है. जब लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर तेज धूप होती है और जब घर में वह पहुंचते हैं तो तुरंत ही फ्रिज से पानी उस समय तो उन्हें गर्मी से राहत दिलाता है लेकिन अचानक से बाहर की गर्मी के बाद फ्रिज का ठंडा पानी लोगों को बीमार कर देता है. उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है. फ्रिज का पानी हमारे हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है वहीं मटका यानी घड़े का पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस हीट वेव में काफी सुरक्षित है. इसके बारे में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने खास जानकारी दी. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया है कि इस समय बहुत जरूरी है लोगों का जानना कि गर्मी में बाहर से आकर तुरंत फ्रिज का पानी पीना उनके लिए कितना नुकसानदायक

है. एयर कंडीशनर में रहने वाले फ्रिज के पानी का ना करें इस्तेमाल : प्रोफेसर वैद्य ने कहा कि आजकल ज्यादातर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वहां ऑफिस एयर कंडीशनर होता है. ऐसे में जब वह घर

कर थोड़ा नॉर्मल होने दे तब उसे पिएं या फिर अपने घर में ऐसे मौसम में घड़ा रखें और आप कहीं से भी आते हैं तो घड़े का पानी पीएं और आदत ऐसी बनाएं की फ्रिज के पानी से परहेज करें.

डिहाइड्रेशन ना हो. दोपहर में नारियल पानी भी आप ले सकते हैं यह भी बहुत फायदेमंद है. घड़े के पानी में मिलता है भरपूर नेचुरल एलिमेंट्स : कुछ स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि घड़ा का पानी



**फ्रिज का पानी या फिर बर्फ डालकर कोल्ड ड्रिंक में या पानी में मिलाकर पीना ऐसे मौसम में बेहद खतरनाक होता है. मिट्टी का घड़े का पानी आरों के पानी से ज्यादा प्रभावकारी : मिट्टी का घड़ा पानी को शुद्ध करके ठंडा करता है जो 'आरों' का पानी भी उतना शुद्ध नहीं कर पाता. घड़े (मटके) का पानी पीना सबसे अच्छा इसलिए भी माना जाता है कि यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और शरीर को बिना किसी नुकसान के ठंडक प्रदान करता है. वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण घड़े का पानी शरीर के तापमान के अनुसार अनुकूलित रहता है.**

आते हैं तो उनका बाँडी टेंपरेचर ठंड और गर्म के संपर्क में आता है ऐसे में आते ही फ्रिज से पानी निकाल कर पीना खासकर छोटे बच्चों को जब वे खेल कर या स्कूल से पढ़कर लौटते हैं ऐसे में तुरंत फ्रिज का पानी उन्हें हिट स्ट्रोक का शिकार बना सकता है. इसलिए पहले पानी को फ्रिज से निकाल

हाई टेंपरेचर में खुद को लू से बचाने का करें उपाय : अभी राजधानी दिल्ली का टेंपरेचर बहुत हाई है और इस टेंपरेचर में खुद को लू से बचाने के लिए थोड़े-थोड़े टाइम पर शुद्ध पानी, गन्ने का जूस तरबूज, खरबूज खाते रहे ताकि आपके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और

हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है जब हम पानी को घड़े में रखते हैं तब उसमें नेचुरल एलिमेंट्स, मिनरल्स मिट्टी के मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हैं और पानी के जरिए हमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं.



## BKTC और प्रशासन पर उठ रहे सवाल केदारनाथ धाम में कंधों में चढ़कर बनाई जा रही रील

केदारनाथ धाम, जहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर अपने आराध्य बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वही पवित्र धाम अब सोशल मीडिया रीलबाजी और वायरल कंटेंट की होड़ के कारण चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। धाम से आई कुछ वायरल तस्वीरों और वीडियो ने ना केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और अनुशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक मंदिर परिसर के आसपास अपने साथियों के कंधों पर चढ़कर रील बनाते नजर आ रहे हैं। कोई फिल्मी स्टाइल में वीडियो शूट कर रहा है, तो कोई बाबा केदार के धाम को सोशल मीडिया कंटेंट का बैकग्राउंड बनाकर लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ में शामिल दिखाई दे रहा है। धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं के प्रतीक माने जाने वाले केदारनाथ धाम में इस प्रकार की गतिविधियों ने श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि बाबा केदार का धाम कोई मनोरंजन स्थल, शूटिंग लोकेशन या

सोशल मीडिया स्टूडियो नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां इस प्रकार की हरकतों धाम की गरिमा और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ

गतिविधियों पर रोक लगाने के दावे किए जाते हैं, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं खुलेआम कैसे हो रही हैं? श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में हर समय पुलिस, सुरक्षा बलों और सीसीटीवी

तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, हिमांशु तिवारी एवं गौरव तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा केदार धाम का मजाक बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस धाम में लोग श्रद्धा और भक्ति



रहा है कि आखिर मंदिर परिसर में अनुशासन बनाए रखने और धार्मिक मर्यादाओं का पालन कराने के लिए बनाए गए नियम-कानून कहां गायब हो गए? जब यात्रा शुरू होने से पहले बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) की ओर से रील, डांस वीडियो और अशोभनीय

निगरानी की बात कही जाती है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो यह बताने के लिए काफी हैं की जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी हैं।

मामले को लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संगठनों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए BKTC सदस्य विनीत पोस्ती ने कहा कि इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं और समिति लगातार श्रद्धालुओं को सुगम एवं व्यवस्थित दर्शन कराने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भीड़ के बीच कुछ लोग कंधों पर चढ़कर रील बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि पहले ही केदारनाथ यात्रा में भारी भीड़, VIP संस्कृति, ट्रैफिक जाम, महंगाई और अव्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

लेकर पहुंचते हैं, वहां कंधों पर चढ़कर रील बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में BKTC और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।



## खेती का नया विज्ञान

# खेत से फार्मसी तक

क्या आने वाले समय में भारत के खेत सिर्फ अनाज नहीं, दवाएँ भी उगाएंगे? भारत की खेती अब सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं रह सकती। बायोटेक्नोलॉजी, सेंसर नेटवर्क और ब्लॉकचेन भारतीय कृषि के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इनका संगम एक ऐसी नई कृषि अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है, जहाँ खेत दवा, डेटा और डिजिटल मूल्य - तीनों का स्रोत बन सकते हैं।

### रफ्तार मीडिया || सवांददाता

भारत की कृषि कहानी हमेशा से ही विरोधाभासों से भरी रही है। यह देश दुनिया की लगभग पाँचवें हिस्से की आबादी का पेट भरता है, जबकि इसके पास ज़मीन और पानी के संसाधन बहुत ही सीमित हैं। आधिकारिक वैश्विक अनुमानों के अनुसार, भारत दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत ज़मीन और वैश्विक ताजे पानी के संसाधनों के केवल 4 प्रतिशत हिस्से पर दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करता है; फिर भी, कृषि लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार बनी हुई है। भारत के लगभग आधे कामगार आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का राष्ट्रीय GDP में योगदान केवल लगभग छठा हिस्सा ही है। इन आँकड़ों के पीछे छोटे किसानों का रोज़मर्रा का संघर्ष छिपा है, जिनकी आय मौसम की मार, बाजार के उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की व्यवस्थागत कमजोरियों के कारण हमेशा जोखिम में रहती है।

### छोटे खेत, बड़ी चुनौती

पूरे ग्रामीण भारत में, दशकों के दौरान खेती-बाड़ी की संरचना में धीरे-धीरे बदलाव आया है। विरासत और बढ़ती आबादी के कारण ज़मीन के टुकड़े बँटते चले गए हैं। नतीजतन, भारत के लगभग 85 प्रतिशत किसान अब दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन वाले छोटे और सीमांत जोतों पर खेती करते हैं। इससे पारंपरिक फ़सल उत्पादन के ज़रिए स्थिर और टिकाऊ आय कमाना

बेहद मुश्किल हो गया है। चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। एक अनुमान के मुताबिक, भंडारण के खराब बुनियादी ढाँचे, परिवहन के कमज़ोर नेटवर्क और बिखरे हुए बाजारों के कारण हर साल 1.5 लाख करोड़ से अधिक का पोस्ट-हार्वैस्ट नुकसान होता है। कई मामलों में, किसान आज भी बिचौलियों और स्थानीय कमीशन एजेंटों पर ही निर्भर रहते हैं, जिनका बाजारों तक पहुँच और कीमतों की जानकारी पर पूरा नियंत्रण होता है।



### पारंपरिक सुधार पर्याप्त हैं?

दशकों से, भारत में कृषि सुधारों का मुख्य जोर

सिंचाई के विस्तार, उर्वरक सब्सिडी, फ़सल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे क्रमिक सुधारों तक सीमित रहा है। हालाँकि ये उपाय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर खेती की आर्थिक स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला पाते हैं। नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के सामने अब यह सवाल तेज़ी से उभर रहा है कि क्या कृषि को केवल पारंपरिक खाद्य उत्पादन तक ही सीमित न रखकर, किसानों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करने हेतु इसका स्वरूप और दायरा विस्तृत किया जाना चाहिए?

### प्लांट मॉलिक्यूलर फार्मिंग: खेती की नई परिभाषा

एक उभरती हुई संभावना 'प्लांट मॉलिक्यूलर फ़ार्मिंग' (पादप आणविक खेती) में निहित है। यह तकनीक खेतों को औषधीय यौगिकों के उत्पादन की जैविक प्रणाली में बदल सकती है। मतलब—फसल सिर्फ भोजन नहीं, दवा (जैविक उत्पाद) भी बन सकती है। यह विचार कृषि के बारे में प्रचलित पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग और एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। फ़सलों की खेती केवल भोजन के लिए करने के बजाय, किसान ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन करते हैं।



## वैज्ञानिक प्रमाण और संभावनाएँ

कई देशों के वैज्ञानिकों ने यह पहले ही साबित कर दिया है कि पौधों को आनुवंशिक रूप से इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि वे उन जटिल प्रोटीनों का उत्पादन कर सकें, जिन्हें आमतौर पर महँगी औद्योगिक प्रक्रियाओं के जरिए ही बनाया जाता है। मक्का, चावल और तंबाकू जैसी फसलों का उपयोग प्रायोगिक प्रणालियों में औषधीय अणुओं के उत्पादन के लिए किया जा चुका है।

एक व्यापक रूप से उद्धृत उदाहरण एप्रोटिनिन है - एक प्रोटीन जिसका उपयोग कुछ हृदय शल्यक्रियाओं के दौरान रक्तस्राव और सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए किया जाता है।

परंपरागत रूप से इस प्रोटीन को गाय के फेफड़ों के ऊतकों से निकाला जाता रहा है, जो एक महँगी प्रक्रिया है और इसमें जैव सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं।

शोधकर्ताओं ने पौधों को इस तरह से संश्लेषित किया है कि वे अपने बीजों में समान प्रोटीन का उत्पादन कर सकें, जिससे एक सुरक्षित और संभावित रूप से व्यापक विकल्प उपलब्ध हो सके।

## पौधों की जैविक ताकत

वैज्ञानिक संभावनाएं केवल एक यौगिक तक सीमित नहीं हैं। पौधे मानव कोलेजन, एंजाइम और यहाँ तक कि वैक्सिन प्रोटीन भी बना सकते हैं। पौधों में उतने रोगजनक नहीं होते जितने पशुओं से प्राप्त फार्मास्यूटिकल्स को दूषित कर सकते हैं। वे जैविक गतिविधि के साथ जटिल प्रोटीन बनाने में सक्षम हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें खेतों में उगाया जा सकता है।

## बीज: स्थायित्व का विज्ञान

बीज एक और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। बीजों में संशोधित औषधीय प्रोटीन लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं क्योंकि सूखे अनाज में नमी का स्तर बहुत कम होता है, आमतौर पर 11 से 15 प्रतिशत के बीच, जिससे प्रोटीन बिना रेफ्रिजरेशन के जैविक रूप से बरकरार रहते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि किसान मूल्यवान औषधीय यौगिकों को

## नई खेती, नए जोखिम

हालाँकि, खुले खेतों में औषधीय फसलों की खेती नई चुनौतियाँ पेश करती है। जब फसलों में उच्च मूल्य वाले औषधीय यौगिक होते हैं, तो वे चोरी, तोड़फोड़ और अवैध हेरफेर के लिए आकर्षक लक्ष्य बन जाते हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि ऐसी फसलें खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश न करें। जैव सुरक्षा मानकों और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सख्त क़ायदे-कानून बनाना आवश्यक होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या छोटे किसान इस तकनीकी छलांग के लिए तैयार हैं?

## ब्लॉकचेन: डेटा की सुरक्षा

सेंसर से प्राप्त डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक उपयोगी हो सकती है। यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है, जहाँ डेटा छेड़छाड़ से सुरक्षित रहता है। ब्लॉकचेन 'सीड-टू-फार्मसी' नेटवर्क बना सकता है जहाँ हर चरण दर्ज होता है। खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक हर चरण रिकॉर्ड करने से पूरी सप्लाय चेन

पारंपरिक अनाज भंडारण की तरह संग्रहित कर सकते हैं।

एक ऐसे देश के लिए जहाँ लाखों किसान छोटे-छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं, इस तरह का परिवर्तन प्रति हेक्टेयर उत्पन्न होने वाले मूल्य में नाटकीय रूप से बदलाव ला सकता है। पारंपरिक फसल से मौसमी आय मामूली हो सकती है, लेकिन औषधीय प्रोटीन का उत्पादन करने वाली फसल विशेष बाजारों में कहीं अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती है।

## सेंसर तकनीक: खेत की निगरानी

यहीं पर उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एयरोस्पेस अनुसंधान से प्रेरित सेंसर नेटवर्क खेतों में तैनात किए जा सकते हैं, जो पर्यावरणीय स्थितियों की वास्तविक समय में निगरानी कर सकते हैं। ये सेंसर तापमान, आर्द्रता, नुदा रसायन और गैस उत्सर्जन जैसे संकेतों को रियल-टाइम में माप सकते हैं। यदि फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं या उनमें छेड़छाड़ होती है, तो पौधों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक संकेत बदलते हैं। सेंसर इन संकेतों का तुरंत पता लगाकर अलर्ट भेज सकते हैं। इससे किसान या सुरक्षा टीमों समय रहते कार्रवाई कर सकती हैं।

पारदर्शी बनती है।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पेमेंट ऑटोमेट हो सकता है। शर्त पूरी होते ही पेमेंट सीधे किसान के खाते में। अगर इसे UPI से जोड़ा जाए, तो भुगतान लगभग तुरंत संभव है। डिजिटल रिकॉर्ड किसानों को क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करेंगे। इससे बैंक वास्तविक डेटा के आधार पर ऋण दे सकेंगे। इस तरह तकनीक के माध्यम से किसान एग्रीप्रेन्योर तक का सफर तय पाएंगे।





## डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती है। जहाँ एक तरफ स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है, वहीं कई इलाकों में स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी भरोसेमंद नहीं है। यहीं से 'हाइब्रिड सिस्टम' की ज़रूरत सामने आती है। सेंसर नेटवर्क और ब्लॉकचेन जैसे प्लेटफॉर्म को ऐसे वातावरण में भी काम करना होगा, जहाँ कनेक्टिविटी अस्थिर हो। समाधान वही होंगे जो ज़मीनी हकीकत के अनुकूल हों - जैसे लोकल डेटा स्टोरेज और कनेक्शन बहाल होते ही ऑटो-सिंक करने वाली तकनीक। यही लचीलापन इस डिजिटल ढांचे को व्यावहारिक बना सकता है।

## नियमन और सावधानियाँ

तकनीकी संभावनाएँ आकर्षक हैं, लेकिन दवा-उत्पादक फ़सलों के लिए सरल बायोसेफ्टी नियम आवश्यक होंगे। भारत में बायोसेफ्टी का ढांचा पहले से मौजूद है - पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैज़ल कमेटी (GEAC) जैसी जैसी एजेंसियाँ इस प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगी। ऐसे में किसी भी व्यावसायिक

खेती को सरल बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के दायरे में रहना होगा, ताकि पर्यावरणीय जोखिम न्यूनतम रहें और स्वाद्य आपूर्ति श्रृंखला में इनका अनचाहा प्रवेश रोका जा सके।

## एक उभरता हुआ भविष्य

खेती की दुनिया में शांत लेकिन गहरा बदलाव आकार ले रहा है, जिसकी आहट खेतों से ज्यादा रिसर्च लैब्स में सुनाई दे रही है। अगर ये अलग-अलग तकनीकें एक साथ आती हैं, तो खेती महज़ उत्पादन का जरिया नहीं, बल्कि जैविक निर्माण केंद्र में बदल सकती है - जहाँ फ़सलें सिर्फ अनाज नहीं, जटिल प्रोटीन और औषधीय तत्व भी तैयार करेंगी। दिलचस्प यह है कि ज़मीन पर तस्वीर अब भी परिचित है। ग्रामीण इलाकों की फ़िल्ड रिपोर्टिंग में किसानों की चिंता आज भी खाद की बढ़ती लागत, पानी की किल्लत और बाज़ार के उतार-चढ़ाव तक सीमित दिखती है। लेकिन इसी के समानांतर, लैब्स और बायोटेक संस्थानों में एक नया कृषि-नज़रिया आकार ले रहा है। वैज्ञानिक ऐसी फ़सलों पर काम कर रहे हैं जो जटिल प्रोटीन बना सकें; इंजीनियर ऐसे स्मार्ट सेंसर विकसित कर रहे हैं जो पौधों की सेहत को रियल-टाइम में ट्रैक करें; और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही लेन-देन के तौर-तरीकों को बदल चुका है। संकेत साफ़ हैं - अगर ये धाराएँ मिलती हैं, तो खेती का अगला अध्याय बिल्कुल

अलग होगा। भविष्य का किसान सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगा - वह तकनीक-समझ रखने वाला उद्यमी भी होगा। अगर मौजूदा तकनीकी धाराएँ एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो खेती एक नए युग में प्रवेश कर सकती है - जहाँ खेत महज़ खाद्यान्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि विकेंद्रीकृत जैविक उत्पादन केंद्र बनेंगे। ऐसे परिदृश्य में भारतीय किसान कम मार्जिन वाले कमोडिटी बाज़ारों तक सीमित रहने के बजाय, वैश्विक बायोटेक सप्लाइ चैन का सक्रिय हिस्सेदार बन सकता है। यह बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं, पहचान का भी होगा। ग्रामीण भारत की नई पीढ़ी के लिए खेती अब 'मजबूरी' नहीं, बल्कि एक हाई-टेक पेशा बन सकती है। सेंसर-आधारित फ़सल प्रणालियों का संचालन, डेटा और डिजिटल बाज़ारों की समझ, और फ़ार्मा कंपनियों के साथ तालमेल - ये सभी भूमिकाएँ किसान को एक नए अवतार में गढ़ेंगी। यानी, आने वाले समय में 'किसान' की परिभाषा बदल सकती है और उसकी जगह ले सकता है एक नया किरदार: एग्रीप्रेन्योर।

## युवा और कौशल का अवसर

नई तकनीकें नए कौशल मांगती हैं और ग्रामीण भारत का युवा इसके लिए तेज़ी से तैयार हो रहा है। असली चुनौती अब स्किल-गैप को पाटने की है, न कि संभावनाओं की कमी की। सेंसर नेटवर्क का संचालन, डेटा एनालिटिक्स की

समझ और डिजिटल सप्लाइ चैन का प्रबंधन—ये सभी ऐसे कौशल हैं जो पारंपरिक खेती से आगे की मांग करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग और डिजिटल साक्षरता इस बदलाव की धुरी बनेंगे फिर भी तस्वीर उम्मीद जगाती है। देश की डेमोग्राफ़िक

ताकत, खासकर ग्रामीण युवाओं का बढ़ता डिजिटल एक्सपोज़र, इस संक्रमण को आसान बना सकता है। स्मार्टफोन और ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म से उनकी परिचितता उन्हें टेक-ड्रिवन कृषि मॉडल अपनाने के लिए स्वाभाविक बढ़त देती है।



# धान का कटोरा, बदलाव की दहलीज पर

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य की कृषि व्यवस्था, उसकी उपलब्धियों, सीमाओं और भविष्य की चुनौतियों को समझने के लिए 'कृषि भूमि' पत्रिका के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज कुमार ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व कुलपति और एसोसिएशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एस. के. पाटिल से विस्तृत बातचीत की। इस साक्षात्कार में प्रो. पाटिल ने धान-प्रधान कृषि, फसल विविधीकरण, सिंचाई, जल संकट, बाजार ढांचे, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार विस्तार से साझा किए।



प्रो. एस. के. पाटिल

**“उद्यानिकी ने छत्तीसगढ़ में कृषि आय के नए द्वार खोले हैं - यह धान के विकल्प के रूप में उभर रही है।”**

## फसल विविधीकरण

धान का कटोरा' कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में पिछले 25 वर्षों में फसल विविधीकरण की क्या स्थिति रही है?

छत्तीसगढ़ की लगभग 70 प्रतिशत कृषि भूमि आज भी धान के अंतर्गत आती है। राज्य में धान का रकबा लगभग 37-38 लाख हेक्टेयर है,

जबकि दलहन (चना, तुअर, उड़द, मूंग) का रकबा केवल 8-10 लाख हेक्टेयर तक सीमित है। पिछले 25 वर्षों में दलहन क्षेत्र में 8-9 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन धान के व्यापक रकबे की तुलना में यह वृद्धि सीमित ही कही

जाएगी। इसका प्रमुख कारण दलहन फसलों की अपेक्षाकृत कम उत्पादकता और इनके लिए मजबूत बाजार व्यवस्था का अभाव है। जहाँ धान की उत्पादकता 3500-4000 किग्रा/हेक्टेयर तक पहुँच रही है, वहीं दलहन की उत्पादकता 800-1000 किग्रा/हेक्टेयर के आसपास ही है। इसके अतिरिक्त



धान के लिए लगभग 3100 प्रति क्विंटल का प्रभावी मूल्य और सुदृढ़ सरकारी खरीदी व्यवस्था किसानों को धान की ओर आकर्षित करती है। हालाँकि, हॉर्टिकल्चर में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। वर्ष 2000 में जहाँ हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र लगभग 92,000 हेक्टेयर था, वहीं अब यह बढ़कर 8.5 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। टमाटर, भिंडी, बैंगन, आम, अमरूद, पपीता, काजू और लीची जैसी फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि इनसे धान की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक आय संभव है।

## सिंचाई और जल प्रबंधन

राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? राज्य गठन के समय (वर्ष 2000) छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2025-26 तक बढ़कर लगभग 21.40 लाख हेक्टेयर हो गई है। हालाँकि, वास्तविक सिंचाई केवल 11-12 लाख हेक्टेयर में ही हो पा रही है, जिससे लगभग

45-50% क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अवधि 80-90 दिनों से घटकर लगभग 65 दिन रह गई है। इस बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

## उत्पादकता में बदलाव

पिछले 25 वर्षों में फसलों की उत्पादकता में क्या परिवर्तन आया है? वर्ष 2000 में राज्य की औसत खाद्यान्न उत्पादकता लगभग 900-1000 किग्रा/हेक्टेयर थी, जो अब बढ़कर 2300-2400 किग्रा/हेक्टेयर हो गई है। धान की औसत उत्पादकता 1300-1600 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 2500-2700 किग्रा/हेक्टेयर

तक पहुँच गई है। मक्का में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। हाइब्रिड बीजों और तकनीकी हस्तक्षेप के कारण इसकी उत्पादकता 1500 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 3000-3500 किग्रा/हेक्टेयर तक पहुँच गई है। फिर भी कृषि यंत्रीकरण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का उपयोग अभी अपेक्षाकृत सीमित है।

## किसान हितैषी योजनाएँ

धान खरीदी, ब्याज-मुक्त ऋण और अन्य योजनाओं का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है? धान की सरकारी खरीदी और ब्याज-मुक्त ऋण योजना ने छोटे और सीमांत किसानों की आय में महत्वपूर्ण सुधार किया है। सहकारी समितियों के माध्यम से त्वरित भुगतान और इनपुट सब्सिडी मिलने से किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है। हालाँकि, इन योजनाओं ने धान की और

**“नीतियाँ पर्याप्त हैं, लेकिन बाजार और मूल्य प्रोत्साहन के बिना जैविक खेती का विस्तार संभव नहीं।”**

झुकाव को और मजबूत किया है, जिससे फसल विविधीकरण की गति प्रभावित हुई है। जैविक और प्राकृतिक खेती कार्यक्रमों से क्या परिणाम मिले हैं?

राज्य में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन किसानों की भागीदारी अभी भी सीमित है। इसका प्रमुख कारण प्रमाणन प्रक्रिया की जटिलता, तीन वर्ष का लंबा परिवर्तन काल (कन्वर्जन पीरियड) और जैविक उत्पादों के लिए अलग एवं लाभकारी बाजार का अभाव है, जिसके चलते किसान इस दिशा में अपेक्षित रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं।



सहकार से समृद्धि

आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व  
Wholly owned by Cooperatives

इफको नैनो यूरिया प्लस और

इफको नैनो डी.ए.पी.

का बादा

लागत कम और लाभ ज्यादा

FCO अधिसूचित दुनिया का पहला नैनो उर्वरक

500 मिली  
बोतल मात्र  
₹ 225/- में

500 मिली  
बोतल मात्र  
₹ 600/- में

इफको  
नैनो  
यूरिया  
प्लस  
(तरल)



इफको  
नैनो  
डी.ए.पी.  
(तरल)



इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, राँची (झारखण्ड)

राज्य विपणन कार्यालय: एम1 (डी/एस) हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 1800 103 1967; वेबसाइट : [www.nanourea.in](http://www.nanourea.in) / [www.nanodap.in](http://www.nanodap.in)



## भविष्य की चुनौतियाँ

आने वाले 25 वर्षों में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और जल संकट होगी। धान पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूजल का दोहन तेजी से बढ़ रहा है, जो दीर्घकाल में गंभीर जल संकट का कारण बन सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि कृषि पद्धतियों

में बदलाव लाया जाए, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) और श्री विधि (SRI) जैसी जल-संरक्षण तकनीकों को अपनाना, मक्का और मिलेट्स जैसी कम पानी वाली फसलों का विस्तार करना, दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा देना, तथा वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना।

## युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुधार

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में यह धारणा तेजी से बढ़ रही है कि खेती एक कठिन और अनिश्चित आय वाला कार्य है, इसलिए अधिकांश युवा कृषि से दूर होकर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। यदि कृषि को भविष्य में टिकाऊ और लाभकारी बनाना है, तो इसे पारंपरिक आजीविका से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीक और उद्यमिता आधारित क्षेत्र बनाना होगा। कृषि में नवाचार, तकनीकी हस्तक्षेप और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देकर युवाओं को "किसान" से आगे बढ़कर "एग्री-प्रेन्योर" बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की कृषि ने 25 वर्षों में मजबूत आधार तैयार किया है, लेकिन अब अगली छलांग—फसल विविधीकरण, जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और

युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही संभव होगी। भविष्य की कृषि—पानी, तकनीक और युवा शक्ति पर आधारित होगी।

### छत्तीसगढ़: धान, पानी और भविष्य

राज्य की लगभग 70% कृषि भूमि धान पर आधारित उद्यानिकी क्षेत्र 92,000 हेक्टेयर से बढ़कर 8.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, लेकिन उपयोग में अंतर मक्का में उत्पादकता वृद्धि सबसे तेज जलवायु परिवर्तन और जल संकट सबसे बड़ी चुनौती धान की प्रधानता के साथ संतुलित विविधीकरण ही भविष्य का रास्ता है

**जल सुरक्षा :** कृषि के लिए जल सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी और संरचनात्मक उपायों को अपनाना आवश्यक है। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विस्तार, मल्लिंग तकनीक का उपयोग, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा, खेत तालाब और स्टॉप डैम का निर्माण तथा भूजल रिचार्ज संरचनाओं का विकास जैसे कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

### मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण

कृषि में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के लिए क्या आवश्यक है? राज्य को कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय प्रसंस्करण आधारित कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार, प्री-कूलिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास, मिनी फूड पार्क की स्थापना तथा एफपीओ आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही "बस्तर ऑर्गेनिक्स" जैसे स्थानीय ब्रांड विकसित कर कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार और मूल्य दिलाया जा सकता है।

### प्रमुख सुधार

1. एग्री-टेक आधारित कृषि का विकास: कृषि को डिजिटल तकनीक, डेटा विश्लेषण और स्मार्ट उपकरणों से जोड़कर आधुनिक बनाना होगा।
2. ड्रोन तकनीक का उपयोग: ड्रोन के माध्यम से छिड़काव, फसल सर्वेक्षण और रोग पहचान जैसे कार्य तेजी और कम लागत में किए जा सकते हैं।
3. प्रिसेजन फार्मिंग (Precision Farming): सेंसर और डेटा आधारित तकनीकों से

इनपुट का सटीक उपयोग संभव होगा, जिससे लागत कम और उत्पादन अधिक होगा।

4. पालीहाउस और ग्रीनहाउस खेती: संरक्षित खेती के माध्यम से वर्षभर उत्पादन और अधिक आय सुनिश्चित की जा सकती है।
5. एग्री-स्टार्टअप और ग्रामीण एग्री-सर्विस सेंटर: युवाओं को कृषि आधारित उद्यमों—जैसे ड्रोन सेवा, मिट्टी परीक्षण, मशीनरी किराया और तकनीकी परामर्श—के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

### डिजिटल कृषि बाजार

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बाजार से कैसे जोड़ा जा सकता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे e-NAM किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि लॉजिस्टिक्स और भंडारण की कमी के कारण इनका उपयोग अभी सीमित है। इसलिए किसानों को एफपीओ के माध्यम से संगठित करना आवश्यक है। बिचौलियों को हटाने के बजाय उन्हें सेवा प्रदाता के रूप में शामिल करना अधिक व्यावहारिक होगा, जिससे किसान और बाजार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।



भारतीय खेती अब सिर्फ मौसम और मेहनत की कहानी नहीं रही। ट्रैक्टर के टॉर्क से लेकर ड्रोन की सटीकता तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग खेतों को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और स्मार्ट बना रही है - एक ऐसी साइलेंट क्रांति, जो हमारी थाली तक पहुँचने वाले हर दाने को बदल रही है।

# फसल के पीछे की असली इंजीनियरिंग

## रफ्तार मीडिया || सवांददाता

भारतीय खेत की पारंपरिक छवि, आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरें उठाए किसान - अब धीरे-धीरे बदल रही है। इसके साथ ही खेत एक जटिल इंजीनियरिंग इकोसिस्टम में तब्दील हो रहा है, जहाँ हर उपकरण, हर प्रवाह और हर प्रक्रिया गणना और डिजाइन का नतीजा है। 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश में, जहाँ 40% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, उत्पादन बढ़ाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। इसके बावजूद, भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर लगभग 45% ही है - अमेरिका (95%) और चीन (60%) की तुलना में काफी पीछे। यही वह अंतर है जिसे भरने में इंजीनियरिंग निर्णायक भूमिका निभा रही है। ट्रैक्टर भारतीय खेत का सबसे भरोसेमंद साथी है - लेकिन यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सटीक इंजीनियरिंग का परिणाम है। कम गति पर अधिक टॉर्क पैदा करना, मिट्टी के संघनन को नियंत्रित करना, और ईंधन दक्षता बनाए रखना - ये सभी डिजाइन की जटिल चुनौतियाँ हैं। भारतीय इंजीनियरों ने ऐसे ट्रैक्टर विकसित किए हैं जो धूल, गर्मी और कठिन भूभाग में भी टिकाऊ प्रदर्शन देते हैं - और वह भी अपेक्षाकृत कम कीमत पर। यही वजह है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है, जहाँ हर साल 10 लाख से अधिक इकाइयाँ बनती हैं। ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाले उपकरण - रोटावेटर, कल्टीवेटर और डिस्क हैरो - भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये मिट्टी को इस तरह तैयार करते हैं कि बीज के लिए आदर्श वातावरण बन सके, वह भी न्यूनतम ऊर्जा खर्च के साथ।

## पानी की राजनीति: फ्लूइड डायनामिक्स और सिंचाई

भारतीय खेती लंबे समय तक मॉनसून पर निर्भर रही है - एक तरह का जोखिम भरा दांव। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस दांव को रणनीति में बदल देती है। सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप, नहरों और भूमिगत जल से पानी खींचकर खेत तक पहुँचाते हैं। लेकिन असली बदलाव सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के साथ आया है। PM-KUSUM जैसी योजनाओं ने डीजल

निर्भरता घटाकर ऊर्जा लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों कम किए हैं। ड्रिप और सिंचकलर जैसी माइक्रो-सिंचाई प्रणालियाँ पानी के उपयोग को 50% तक घटा सकती हैं, जबकि पैदावार में 20-30% तक वृद्धि संभव बनाती हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे जल-संकटग्रस्त राज्यों में यह तकनीक खेती की दिशा बदल रही है।



## यहीं से इंजीनियरिंग की दूसरी पारी शुरू होती है

कंबाइन हार्वेस्टर: एक साथ कटाई, थ्रेशिंग और सफाई—समय और श्रम दोनों की बचत  
कोल्ड स्टोरेज: थर्मोडायनामिक्स आधारित सिस्टम जो तापमान और नमी को नियंत्रित रखते हैं  
ग्रेडिंग मशीनें: सेंसर और एयर जेट तकनीक से गुणवत्ता आधारित छँटाई  
इन तकनीकों से न सिर्फ नुकसान कम होता है, बल्कि किसान को बेहतर कीमत भी मिलती है।





## मिट्टी और मशीन की साझेदारी

मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब खेत के बाहर की चीज नहीं रही - यह खेत की धड़कन का हिस्सा बन चुकी है। सूरज की ऊर्जा, मिट्टी की उर्वरता और बीज की क्षमता इन तीनों को प्रभावी बनाने में मशीनें एक अदृश्य सेतु का काम कर रही हैं। ट्रैक्टर की गर्जना से लेकर ड्रिप की शांत बूंद तक, यह तकनीक सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ा रही - यह खेती को टिकाऊ, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बना रही है। आखिरकार, यह सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है। यह उस साझेदारी की कहानी है, जहाँ इंजीनियरिंग और किसान मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि की नई इबारत लिख रहे हैं।

## कटाई के बाद की लड़ाई

पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग खेती सिर्फ उगाने तक सीमित नहीं है - उत्पाद को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में 15-25% फल-सब्जियाँ और लगभग 10% अनाज कटाई के बाद खराब हो जाता है।



## खेत से थाली तक : इंजीनियरिंग का सफर



## स्मार्ट खेती: ड्रोन और प्रिसिजन एग्रीकल्चर

खेती अब 'अनुमान' से 'डेटा' की ओर बढ़ रही है। प्रिसिजन फार्मिंग इसी बदलाव का केंद्र है। कृषि ड्रोन - जो पहले भविष्य की चीज लगते थे - अब वास्तविकता हैं। ये खेतों पर उड़कर मिलीमीटर स्तर की सटीकता से कीटनाशक और उर्वरक छिड़कते हैं, जिससे: रसायनों का उपयोग 30% तक

घटता है पानी की बचत होती है किसान का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है इसके साथ ही, कंप्यूटर विज्ञान आधारित ऑटोमैटिक वीडर मशीनें बिना रसायन के खरपतवार हटाने लगी हैं - मतलब एक बड़ा पर्यावरणीय लाभ।

## इस चुनौती ने इनोवेशन को जन्म दिया है

मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर: छोटे खेतों के लिए किफायती और बहुउद्देश्यीय एगोनोमिक औजार: खासकर महिलाओं के श्रम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCS): मशीनों का

'Uber मॉडल', जहाँ किसान जरूरत के अनुसार किराए पर उपकरण ले सकते हैं यह "स्केल-एप्रोप्रियेट मैकेनाइजेशन" भारतीय कृषि का सबसे व्यावहारिक रास्ता बनकर उभर रहा है।

## भारतीय संदर्भ : छोटे किसानों के लिए समाधान

भारत की सबसे बड़ी वास्तविकता है - छोटे और सीमांत किसान। लगभग 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे में बड़े, महंगे उपकरण व्यावहारिक नहीं।





भारत में कार्बन मार्केट अब कानून से संचालित है। इंडस्ट्री पर उत्सर्जन घटाने का दबाव है- लेकिन उसका समाधान खेतों में खोजा जा रहा है। बिना कानूनी सुरक्षा के लंबे कॉन्ट्रैक्ट में बंधे किसान इस बदलाव का सबसे बड़ा जोखिम उठा रहे हैं।

# क्लाइमेट पॉलिसी: कार्बन का कारोबार, किसानों पर बोझ

रफ्तार मीडिया || सवांददाता

भारत ने अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्लाइमेट कम्प्लायंस को कानूनी तौर पर लागू कर दिया है। एमिशन इंटेंसिटी टारगेट नोटिफाई कर दिए गए हैं। कार्बन ट्रेडिंग अब महज़ एक प्रस्ताव या पायलट प्रोजेक्ट नहीं रह गया है; यह कानून द्वारा समर्थित एक्टिव पॉलिसी है। जिस बात पर उतनी गंभीरता से चर्चा नहीं हुई है, वह यह है कि इस अनुपालन के लिए संसाधन कहाँ से आ रहे हैं - और ज़मीनी स्तर पर चुपचाप इसका जोखिम कौन उठा रहा है। इसका जवाब भारत के खेतों, मिट्टी और किसानों द्वारा साइन किए गए लॉन्ग-टर्म कार्बन कॉन्ट्रैक्ट में छिपा है, जो किसी भी कानूनी सुरक्षा से बाहर हैं।

## छूट या धकेलना?

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत कृषि को ज़रूरी एमिशन टारगेट से बाहर रखा गया है। इसका कारण हमेशा किसानों की सुरक्षा बताया गया है। असल में, इस छूट ने किसानों को और भी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में डाल दिया है। जहां इंडस्ट्रीज़ को कानून से रेगुलेट किया जाता है, वहीं खेती को कॉन्ट्रैक्ट वाले मार्केट में धकेल दिया गया है, जहां दशकों से ज़मीन बिना किसी साफ़ कानूनी सुरक्षा के रखी गई है। किसानों को टारगेट से छूट दी गई है, लेकिन उनकी ज़मीन को डिमोड से छूट नहीं दी गई है।

## सस्ते क्रेडिट, महंगा असर

वर्ष 2026 की शुरुआत तक उपलब्ध रजिस्ट्री डेटा से पता चलता है कि जारी किए गए कुल कार्बन क्रेडिट में से लगभग 40 प्रतिशत कृषि और वानिकी से जुड़ी गतिविधियों से प्राप्त हो रहे हैं। इनमें मिट्टी में कार्बन का भंडारण (मृदा कार्बन पृथक्करण - soil carbon sequestration), एग्रीफॉरेस्ट्री, पेड़ लगाना, बचे हुए सामान का मैनेजमेंट, और क्लाइमेट सॉल्यूशन के तौर पर बढ़ावा दिए जाने वाले ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव शामिल हैं। ये क्रेडिट औद्योगिक उत्सर्जन में कटौती से प्राप्त होने वाले क्रेडिट की तुलना में कहीं अधिक सस्ते पड़ते हैं। जैसे-जैसे फैक्ट्रियों पर कम्प्लायंस का दबाव बढ़ता है, बाज़ार अपने आप खेती की ज़मीन की ओर मुड़ जाता है। यह बदलाव किसानों की सुरक्षा के लिए किसी पैरेलल कानून के बिना हुआ है।



## ज़मीन उनकी, कार्बन नहीं

सबसे गंभीर कमी कृषि भूमि पर कार्बन अधिकारों की किसी भी वैधानिक मान्यता का अभाव है। ज़मीन किसानों की अपनी होती है। वे ही मिट्टी में खेती करते हैं। वे मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करते हैं। फिर भी, इस ज़मीन से उत्पन्न होने वाले कार्बन को कानूनी तौर पर उनका अपना नहीं माना जाता है। कार्बन क्रेडिट का स्वामित्व और बिक्री उन प्रोजेक्ट डेवलपर्स या एग्रीगेटर्स के पास होता है, जो इन प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण और सत्यापन करते हैं। किसानों को केवल भुगतान मिलता है—स्वामित्व नहीं। डिज़ाइन की यही एक कमी यह तय करती है कि मूल्य पर किसका नियंत्रण होगा और जोखिम कौन उठाएगा।



## 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट, खत्म होती आज़ादी

भारत में ज्यादातर कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स लंबे समय के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर 20 से 30 साल तक चलते हैं।

ये कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं, खेती के तरीकों को तय करते हैं, और बाहर निकलने के ऑप्शन को सीमित कर देते हैं। एक बार जब ज़मीन कार्बन प्रोजेक्ट में चली जाती है, तो किसानों की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फसलों के विकल्प सीमित हो जाते हैं। चराई की सुविधा बदल जाती है। पारंपरिक मिश्रित खेती मुश्किल हो जाती है।

छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी का यह नुकसान अक्सर कम कीमतों से ज्यादा भारी पड़ता है।

## आय कम, अनिश्चितता ज़्यादा

बदले में मिलने वाली इनकम मामूली और अनिश्चित होती है। साइड कार्बन और एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स में, किसानों को पेमेंट आमतौर पर ₹2,000 से ₹5,000 प्रति एकड़ प्रति साल के बीच बताया जाता

है, जो वेरिफिकेशन के नतीजों और कार्बन की कीमतों पर निर्भर करता है। डेवलपर्स मिट्टी की बेहतर सेहत और कम लागत जैसे को-फ़ायदों पर ज़ोर देते हैं, और कुछ किसान बेहतर नमी बनाए रखने और मिट्टी की

बनावट में सुधार की भी रिपोर्ट करते हैं। ये फ़ायदे असली हैं। लेकिन यह भी सच है कि कार्बन इनकम ज़्यादातर छोटे किसानों के लिए एक फसल चक्र की भी जगह नहीं ले पाती है।

## वेरिफिकेशन फेल, किसान फेल

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन इनकम की कोई गारंटी नहीं है। क्रेडिट वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाते हैं, जिसमें महीनों लग सकते हैं। रजिस्ट्री प्रोसेस, खरीदार की मांग, या मेटहडोलॉजी रिव्यू के कारण पेमेंट में अक्सर देरी होती है। अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाता है या नियम बदल जाते हैं, तो क्रेडिट बिल्कुल भी जारी नहीं किए जाते। ऐसे मामलों में किसानों को कुछ नहीं मिलता। हालांकि, ज़मीन उनके कब्जे में ही रहती है—लेकिन बिना किसी सुरक्षा के। कोई कानूनी मुआवज़ा देने का सिस्टम नहीं है, कोई सरकारी भरोसा नहीं है, और कोई तय शिकायत अथॉरिटी भी नहीं है। जब

प्रोजेक्ट रुकता है यहीं पर रिस्क नीचे की ओर बढ़ता है। इंडस्ट्रीज़ को कानूनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और जगहों पर रिस्क को बांट सकते हैं। किसान ऐसा नहीं कर सकते। एक आम छोटे किसान के पास एक या दो ज़मीन के टुकड़े होते हैं। जब वह ज़मीन कार्बन के लिए कमिटेड हो जाती है, तो घर की पूरी रोजी-रोटी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर हो जाती है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है, तो किसानों के पास ज़मीन कम रह जाती है और कोई इनकम नहीं होती।



## ऑडिट, आरटीआई और ज़मीनी सच

2025 के आखिर में संवैधानिक अधिकारियों द्वारा पेश किए गए ऑडिट ऑब्ज़र्वेशन में खेती से जुड़े कार्बन प्रोजेक्ट्स में बार-बार होने वाली कमियों को उजागर किया गया - जिनमें खराब लैंड-टाइटल वेरिफिकेशन, रेवेन्यू शेयरिंग में पारदर्शिता की कमी, और लागू करने लायक सुरक्षा उपायों का अभाव शामिल है। पूर्वी भारत से प्राप्त आरटीआई खुलासों से पता चला है कि हज़ारों हेक्टेयर कार्बन प्रोजेक्ट्स बिना ग्राम सभा की मंजूरी के चल रहे हैं - यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जहाँ जंगल और सामुदायिक भूमि कानून लागू होते हैं। जब झगड़े सामने आते हैं, तो क्रेडिट रोक दिए जाते हैं, पेमेंट रुक जाते हैं - और किसान अधर में लटक जाते हैं।

## खाद्य सुरक्षा बनाम कार्बन

इसका असर ग्रामीण इलाकों में पहले से ही दिख रहा है। कई बारिश पर निर्भर इलाकों में, जो ज़मीन पहले मिली-जुली फ़सल या चराई के लिए इस्तेमाल होती थी, अब पेड़-आधारित या मोनोकल्चरल सिस्टम की तरफ़ शिफ्ट हो गई है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सोखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेड़ क्रेडिट देते हैं - वे खाना नहीं देते। जहाँ सार्वजनिक चरागाह की ज़मीन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाती है, वहाँ पशुपालकों की रोजी-रोटी पर असर पड़ता है। ये बदलाव नीतिगत दस्तावेजों में मामूली लग सकते हैं, लेकिन गांव के स्तर पर ये खाद्य असुरक्षा और कर्ज़ का कारण बनते हैं।



## भूमि मॉडल: संभावना और जोखिम

आज भारत में सबसे अधिक दिखाई देने वाले सॉइल कार्बन मॉडलों में से एक को भूमि मॉडल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक अमेरिकी डेवलपर है और कई राज्यों में काम कर रहा है। इसके प्रोजेक्ट्स रेसिड्यू मैनेजमेंट, कम जुताई, कम्पोस्टिंग, इंटरक्रॉपिंग और बेहतर वॉटर मैनेजमेंट जैसे रिजेनेरेटिव तरीकों को बढ़ावा देते हैं। किसानों को कोई शुरुआती खर्च नहीं करना पड़ता और उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। कई लोगों ने मिट्टी की सेहत में सुधार की रिपोर्ट दी है। यह मॉडल कार्बन फार्मिंग की संभावनाओं को दर्शाता है। हालांकि, यह इसके जोखिमों को भी उतनी ही स्पष्टता से सामने

लाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल किसान लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहाँ कार्बन क्रेडिट का मालिकाना हक और बिक्री डेवलपर के पास होती है - किसान के पास नहीं। पेमेंट सफल वेरिफिकेशन और मार्केट डिमांड पर निर्भर करता है। भूमि उपयोग की फ्लेक्सिबिलिटी दशकों तक सीमित रहती है। यहां तक कि जहां डेवलपर्स ट्रांसपेरेंट तरीकों का पालन करते हैं, वहां भी कानूनी सुरक्षा की कमी का मतलब है कि किसान जोखिम में रहते हैं। एक सही कॉन्ट्रैक्ट, एक सही कानून की जगह नहीं ले सकता।

## पॉलिसी की खामोशी

बड़ी विफलता पॉलिसी डिजाइन में निहित है। इंडस्ट्री के मामले में एमिशन टारगेट लागू करने वाले सरकारी नोटिफिकेशन डिटेल में होते हैं - वे बेसलाइन, टाइमलाइन और पेनल्टी बताते हैं।

लेकिन वे जो तय नहीं करते, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

किसानों के लिए कोई मिनिमम रेवेन्यू शेयर नहीं है, कोई लैंड-यूज सीलिंग नहीं है, कोई एग्जिट प्रोटेक्शन नहीं है, और कार्बन कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़मीन, टेनेंसी या फॉरेस्ट राइट्स कानूनों के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है।

ऐसा लगता है कि यह मान लिया गया है कि बाज़ार खुद ही खुद को नियंत्रित कर लेंगे। जब मोलभाव करने की ताकत बराबर नहीं होती, तो बाज़ार खुद को रेगुलेट नहीं करते।

## कार्बन कॉन्ट्रैक्ट: सौदा या जोखिम?

पहलू	वास्तविक स्थिति
कॉन्ट्रैक्ट अवधि	20-30 साल
सालाना आय	2,000-5,000 / एकड़
आय की गारंटी	नहीं
पेमेंट निर्भरता	वेरिफिकेशन + मार्केट
कार्बन का मालिक	डेवलपर
ज़मीन का मालिक	किसान
लैंड-यूज स्वतंत्रता	सीमित
एग्जिट ऑप्शन	बहुत कम
कानूनी सुरक्षा	लगभग नहीं
विवाद समाधान	अस्पष्ट

...ज़मीन किसान की, नियंत्रण बाज़ार का



## किसान: स्टेकहोल्डर या पार्टिसिपेंट?

भारत के क्लाइमेट से जुड़े कमिटमेंट काफी हद तक ज़मीन पर बने कार्बन सिंक पर निर्भर हैं। किसान इस रणनीति के केंद्र में हैं। फिर भी मौजूदा सिस्टम उन्हें स्टेकहोल्डर नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट मानता है। किसानों की सुरक्षा किए बिना खेती की ज़मीन पर किया गया क्लाइमेट एक्शन टिकाऊ नहीं है। इससे यह खतरा पैदा हो जाता है कि जलवायु नीति कहीं ग्रामीण संकट का एक और ज़रिया न बन जाए।

## अभी नहीं तो कभी नहीं

भारत का कार्बन बाज़ार अभी भी नया है - और इसी वजह से इन कमियों को अभी दूर किया जाना चाहिए। एक बार जब ज़मीन लंबे समय के लिए कार्बन-उपयोग से जुड़ जाती है, तो उस फैसले को पलटना राजनीतिक और आर्थिक - दोनों ही दृष्टियों से बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर किसान क्लाइमेट पॉलिसी को अपनी ज़मीन की सुरक्षा के बजाय असुरक्षा की वजह मानने लगे, तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। भारत ने इंडस्ट्री के लिए जलवायु से जुड़े नियमों का पालन करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। अब इसके अनुपालन की ज़रूरत को खेतों और मिट्टी के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। किसानों की सुरक्षा क्लाइमेट एक्शन में कोई रुकावट नहीं है - बल्कि यह उसकी सफलता और अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त है।



## कम पौधे, ज्यादा मुनाफा

# केले की खेती का नया विज्ञान

“केला अकेला, गुच्छा है भारी” - एक ऐसा फार्मूला जो खेत की भीड़ घटाकर उत्पादन बढ़ाता है और खेती को लाभ का सौदा बना देता है। पहली नजर में यह विचार परंपरा के खिलाफ लगता है, क्योंकि किसान वर्षों से अधिक पौधों को अधिक उत्पादन का रास्ता मानते आए हैं।

### रफ्तार मीडिया || सवांददाता

भारत में केला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों की अर्थव्यवस्था का अहम आधार है। देश विश्व के अग्रणी उत्पादकों में गिना जाता है, फिर भी एक विडंबना बनी हुई है - हमारी उत्पादकता अब भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। खेतों में हरियाली तो दिखती है, लेकिन प्रति पौधा और प्रति हेक्टेयर मिलने वाला लाभ उस स्तर तक नहीं जाता, जहां विज्ञान उसे पहुंचा सकता है। इसी अंतर को भरने के लिए कृषि विज्ञान ने एक दिलचस्प, लगभग विरोधाभासी लगने वाला सिद्धांत सामने रखा है - केला अकेला, गुच्छा है भारी। पहली नजर में यह विचार परंपरा के खिलाफ लगता है, क्योंकि किसान वर्षों से अधिक पौधों को अधिक उत्पादन का रास्ता मानते आए हैं। लेकिन आधुनिक शोध इस सोच को पलट देता है।

### भीड़ से नुकसान, संतुलन से लाभ

केले के खेतों में अक्सर एक ही स्थान पर कई सकर्स (Suckers) को बढ़ने दिया जाता है। ऊपर से यह खेत भरा-भरा लगता है, पर पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए अंदर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है। इस प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा

असर पड़ता है प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) पर। जब पौधे को पर्याप्त प्रकाश और पोषण नहीं मिलता, तो उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटती है और नतीजतन गुच्छा छोटा और हल्का रह जाता है। ‘केला अकेला’ इसी समस्या का सीधा समाधान है। इसमें एक

स्थान पर एक समय में केवल एक मुख्य पौधे को बढ़ने दिया जाता है। यह पौधे को बिना किसी आंतरिक प्रतिस्पर्धा के अपनी पूरी जैविक क्षमता तक विकसित होने का मौका देता है। खेत कम भरा दिख सकता है, लेकिन हर पौधा अपनी पूरी ताकत से काम करता है।



### आंकड़े जो कहानी बदल देते हैं

हाल के शोध (2023-2025) इस तकनीक की प्रभावशीलता को मजबूत आधार देते हैं। नियंत्रित पौध घनत्व, सटीक पोषण प्रबंधन और ड्रिप-फर्टिगेशन के संयोजन से उत्पादकता में 25 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी दिखती है - बड़े, भारी और बाजार में अधिक मूल्य पाने वाले गुच्छों के रूप में।

हाल के शोध (2023-2025) इस तकनीक की प्रभावशीलता को मजबूत आधार देते हैं। नियंत्रित पौध घनत्व, सटीक पोषण प्रबंधन और ड्रिप-फर्टिगेशन के संयोजन से उत्पादकता में 25 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी दिखती है - बड़े, भारी और बाजार में अधिक मूल्य पाने वाले गुच्छों के रूप में।

## खेत में बदलाव की शुरुआत

इस तकनीक को अपनाना जटिल नहीं, बल्कि अनुशासन का खेल है। शुरुआत स्वस्थ पौधे से होती है - टिशू कल्चर से तैयार, रोगमुक्त और समान वृद्धि वाले पौधे। इसके बाद असली चुनौती आती है सकर प्रबंधन की। किसान को अपने ही खेत में 'ना' कहना सीखना पड़ता है - अतिरिक्त सकर्स को हटाना और केवल एक को बढ़ने देना। फसल चक्र भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ही स्थान पर तीन रैटून फसल के बाद खेत को बदलना या फसल चक्र अपनाना जरूरी हो जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और रोगों का दबाव न बढ़े। पौधे की पत्तियां भी उसकी उत्पादकता का संकेत देती हैं। लगभग 13-14 स्वस्थ हरी पत्तियों को बनाए रखना एक आदर्श स्थिति मानी जाती है - यही पत्तियां ऊर्जा उत्पादन का केंद्र हैं।



## पोषण और पानी: अदृश्य ताकत

केला एक ऐसी फसल है जो मिट्टी से भरपूर पोषण मांगती है। यदि उसे संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशम न मिले, तो उसकी पूरी क्षमता कभी सामने नहीं आती। पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन के साथ अब फर्टिगेशन (Drip + Fertilizer) का उपयोग

तेजी से बढ़ रहा है, जिससे न केवल 25-30 प्रतिशत उर्वरक की बचत होती है, बल्कि पौधों तक पोषण अधिक सटीक रूप से पहुंचता है। इसी तरह, जल प्रबंधन में भी बदलाव आया है। जहां पहले खेतों में पानी भर दिया जाता था, अब ड्रिप सिंचाई हर बूंद को मायने देती

है। इससे 40-50 प्रतिशत तक जल की बचत संभव है और पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार ही पानी मिलता है। जलभराव से बचना यहां उतना ही जरूरी है, क्योंकि यही स्थिति जड़ सड़न (Root Rot) जैसी समस्याओं को जन्म देती है।

### खुलेपन में छिपा है सुरक्षा कवच

जब खेत में पौधों के बीच उचित दूरी होती है, तो वायु संचार बेहतर होता है। यह साधारण-सी बात बड़े फर्क की वजह बनती है। सिगाटोका और पनामा विल्ट जैसे रोग, जो नमी और घनत्व में तेजी से फैलते हैं, इस खुले ढांचे में कम प्रभावी हो जाते हैं। जैविक नियंत्रण भी अब खेती का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। Trichoderma और Pseudomonas fluorescens जैसे एजेंट न केवल रोगों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं।

### नतीजा: कम में ज्यादा

इस पूरी तकनीक का सार एक ही है - संतुलन। जब एक पौधे को पर्याप्त संसाधन मिलते हैं, तो वह बदले में अधिक उत्पादन देता है। यही कारण है कि इस पद्धति में गुच्छों का वजन 25 से 40 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। बड़े आकार, बेहतर गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण बाजार में इसका मूल्य भी अधिक मिलता है।

### खेती का बदलता नजरिया

भारतीय किसान तेजी से बदलते दौर में खड़ा है। अब सवाल सिर्फ उत्पादन का नहीं, बल्कि दक्षता और लाभ का है। "केला अकेला, गुच्छा है भारी" इस बदलाव का प्रतीक है—जहां भीड़ नहीं, बल्कि प्रबंधन सफलता तय करता है। हरियाली की घनता नहीं, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। जब खेत में हर पौधा अपनी पूरी क्षमता से बढ़ेगा, तभी किसान की आय भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। और शायद यही वह मोड़ है, जहां पारंपरिक खेती विज्ञान से हाथ मिलाकर एक नई दिशा तय कर रही है। कम पौधे, भारी गुच्छे - यही है केले की खेती का गणित।

प्रो. (डॉ.) एस. के. सिंह, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में प्लांट पैथोलॉजी एवं नेमेटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। पौध रोग विज्ञान और मृदा सूक्ष्मजीविकी के क्षेत्र में उनका दीर्घ अनुभव रहा है, और वे जैव नियंत्रण तथा सतत कृषि के प्रमुख विशेषज्ञों में गिने जाते हैं।



# ऊन का नया दौर

हिमाचल प्रदेश के बजट 2026-27 में ऊन की कीमत में दशकों बाद बड़ा उछाल - भेड़पालकों के लिए नई उम्मीद, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह राहत कागज़ से निकलकर चरागाहों तक पहुंचेगी?

## क्या बदल जाएगी भेड़पालकों की किस्मत?

### रफ्तार मीडिया || सवांदादाता

धर्मशाला की पहाड़ियों में इस बार चर्चा मौसम की नहीं, ऊन की कीमत की है। लंबे समय से उपेक्षित इस क्षेत्र में अचानक हलचल है। वजह - हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट 2026-27, जिसमें भेड़पालन और ऊन क्षेत्र को नई प्राथमिकता दी गई है।

वूल फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मनोज ठाकुर इसे "ऐतिहासिक" बताते हैं। उनके अनुसार, पिछले लगभग 25-30 वर्षों में ऊन की कीमत में मात्र 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि अब इसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला भेड़पालकों की आय को स्थिर और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा हस्तक्षेप माना जा रहा है।

### ठहराव से उछाल तक: कीमत की नई कहानी

भारतीय ऊन क्षेत्र लंबे समय से मूल्य संकट से जूझता रहा है। सिंथेटिक फाइबर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आयातित ऊन के दबाव ने स्थानीय उत्पादन की मांग और कीमत दोनों को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, भेड़पालन धीरे-धीरे कम लाभकारी पेशा बनता गया। ऐसे में ऊन की कीमत में यह बढ़ोतरी केवल एक

प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकता में बदलाव का संकेत है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य के बीच अंतर को संतुलित करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है, ताकि भेड़पालकों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई न हो।



### एक नज़र में: बजट के बड़े फैसले

- ऊन की कीमत:** ₹7 की वृद्धि (पिछले 25-30 साल) अब ₹100 तक
- MSP और बाजार अंतर संतुलन के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान
  - ₹300 करोड़ का समग्र ऊन/भेड़पालन प्रोजेक्ट
  - भेड़पालकों के लिए ₹10 लाख तक जीवन बीमा
  - ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की सुविधा
  - 'चेंगु' नस्ल के संरक्षण पर विशेष फोकस

## गद्दी समुदाय: परंपरा से पेशे तक

हिमाचल का गद्दी समुदाय भेड़पालन से गहरे रूप से जुड़ा रहा है। यह केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी है। हालांकि, पिछले वर्षों में आय में गिरावट और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण नई पीढ़ी इस पेशे से दूर होती गई। अब सरकार का जोर भेड़पालन को एक व्यवस्थित और आय-सृजनकारी गतिविधि के रूप में विकसित करने पर है, ताकि युवाओं को फिर से इस क्षेत्र से जोड़ा जा सके।



## इसका मतलब भेड़पालक के लिए क्या है?

ऊन की कीमत में बढ़ोतरी सीधे आय पर असर डालेगी, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब

खरीद सुनिश्चित हो और भुगतान समय पर मिले। बीमा और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैसे

कदम जोखिम कम करने और बाजार में बेहतर कीमत दिलाने की दिशा में मददगार हो सकते हैं।

### केवल ऊन नहीं, पूरी

### वैल्यू चेन पर फोकस

बजट में प्रस्तावित लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना इस क्षेत्र को समग्र रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि ऊन से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन को सुदृढ़ करना है। इसके साथ ही भेड़पालकों के लिए 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की सुविधा जैसे प्रावधान इस क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और बाजारोन्मुख बनाने की पहल हैं। ऑर्गेनिक प्रमाणन के माध्यम से भेड़ के मांस, दूध और ऊन से बने उत्पादों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।

### स्थानीय नस्लों का महत्व: 'चेंगु' पर ध्यान

लाहौल-स्पीति, किन्नौर और भरमौर जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली 'चेंगु' नस्ल की भेड़-बकरियां अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती हैं। इनका संरक्षण और विकास केवल जैव विविधता के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जलवायु-अनुकूल पशुपालन (climate-resilient livestock) के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इन नस्लों पर विशेष ध्यान देना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

### क्यों अहम है यह फैसला?

- वर्षों से स्थिर कीमतों के बाद बड़ा हस्तक्षेप
- पारंपरिक पेशे को रोजगार में बदलने की कोशिश
- सिंथेटिक फाइबर के मुकाबले स्थानीय ऊन को बढ़ावा
- जलवायु-अनुकूल पशुपालन को समर्थन

### जमीनी हकीकत: चुनौती अभी बाकी

नीतिगत घोषणाएं उम्मीद जगाती हैं, लेकिन उनकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। क्या बड़ी हुई कीमत का लाभ समय पर भेड़पालकों तक पहुंचेगा? क्या विपणन ढांचा

पर्याप्त मजबूत है? और क्या नई पीढ़ी इस पेशे की ओर लौटेगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

### क्या बदलेगी तस्वीर?

हिमाचल प्रदेश का यह बजट ऊन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की एक गंभीर कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। यदि घोषित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो यह केवल कीमत में वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भेड़पालन को एक टिकाऊ और लाभकारी आजीविका के रूप में स्थापित कर सकता है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह पहल एक अस्थायी राहत साबित होती है या वास्तव में एक दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत। फिलहाल, पहाड़ों में उम्मीद की एक नई बुनाई शुरू हो चुकी है।



## छोटा कीट, बड़ा खतरा

जब हर तीसरा फल गिरने लगे, समझिए दुश्मन दिखने से पहले ही वार कर चुका है - रेड बैंडेड बोरर के बढ़ते प्रकोप के बीच यह वक्त है सबसे ज्यादा सतर्क रहने का।

# आम के बागों में खामोश तबाही

### रफ्तार मीडिया || सवांदाता

आम - “फलों का राजा” - इन दिनों एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहा है, जो दिखता कम है और नुकसान ज्यादा करता है। न आंधी, न सूखा - बल्कि एक सूक्ष्म कीट, जो बिना आहत के फल के भीतर प्रवेश कर पूरी फसल को अंदर से बर्बाद कर देता है। इस खामोश हमलावर का नाम है - रेड बैंडेड बोरर (Red Banded Mango Caterpillar - RBMC)। पिछले कुछ वर्षों में यह कीट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। कई बागों में हर तीसरा फल प्रभावित दिख रहा है। सामान्य परिस्थितियों में 30-50 प्रतिशत तक नुकसान और गंभीर प्रकोप में 80-90 प्रतिशत तक फल क्षति दर्ज की गई है, जो सीधे किसान की आय पर चोट करता है।

### क्यों बढ़ रहा है यह खतरा?

यह सिर्फ एक कीट का हमला नहीं, बल्कि बदलती जलवायु का भी संकेत है। अनियमित वर्षा, लंबे समय तक बनी रहने वाली नमी, और तापमान में उतार-चढ़ाव - ये सभी स्थितियां इस कीट के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। जब आर्द्रता 70 प्रतिशत से ऊपर रहती है और तापमान 25-32°C के बीच होता है, तब इसका प्रकोप तेजी से बढ़ता है। घने बाग, जहां वायु संचार कम होता है, वहां यह खतरा और भी गहरा हो

जाता है।

#### सबसे नाजुक समय: मटर स्टेज

इस समय अधिकांश क्षेत्रों में आम के फल मटर के दाने के आकार के हो चुके हैं - और यही वह अवस्था है, जब यह कीट सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ऊपर से बादल, हल्की बारिश की संभावना और नम मौसम - ये संकेत हैं कि खतरा दरवाजे पर है। यहीं किसान अक्सर चूक जाते हैं और यही चूक पूरे सीजन पर भारी पड़ती है।



### पहचान: खतरा के शुरुआती संकेत

इस कीट की सबसे बड़ी चुनौती है - इसका छिपा हुआ हमला। फिर भी कुछ संकेत ऐसे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फलों पर छोटे-छोटे छेद दिखाई देना, समय से पहले फल गिरना, या फल के अंदर सड़न और गलन - ये सभी शुरुआती चेतावनी संकेत हैं। कई बार बाहर से फल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खराब हो चुका होता है।

## खामोश हमलावर का विज्ञान

रेड बैंडेड बोरर का जीवन चक्र छोटा है, लेकिन बेहद प्रभावी। मादा पतंगा अपने सूक्ष्म अंडे फल के डंठल पर देती है। कुछ ही दिनों में निकलने वाला लार्वा सीधे फल के भीतर घुस जाता है। इसके बाद यह गूदे को खाते हुए धीरे-धीरे गुठली तक पहुंच जाता है। यही अवस्था सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। अंततः फल या तो समय से पहले गिर जाता है या बाजार में बेकार साबित होता है। अनुकूल मौसम में यह कीट एक ही सीजन में 3-4 पीढ़ियां विकसित कर सकता है - यानी एक बार नियंत्रण छूटा, तो समस्या तेजी से बढ़ती है।



## जहां किसान चूक जाते हैं

अक्सर किसान इस समस्या को देर से पहचानते हैं - जब नुकसान हो चुका होता है। गिरे

हुए फलों को नजरअंदाज करना, बाग की सफाई में लापरवाही, और समय पर छिड़काव न

करना - ये कुछ सामान्य गलतियां हैं जो इस कीट को बढ़ावा देती हैं।



### अभी तुरंत क्या करें?

इस समय इंतजार करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बाग का निरीक्षण करें, गिरे हुए फलों को तुरंत हटाएं, और यदि शुरूआती लक्षण दिखें तो बिना देरी वैज्ञानिक सलाह लें। याद रखें - यह कीट दिखाई कम देता है, लेकिन नुकसान बहुत तेजी से करता है। रेड बैंडेड बोरेर एक उभरता हुआ खतरा है, जो आम की खेती की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है—यदि समय पर पहचाना जाए। खेती में अक्सर जीत उसी की होती है, जो खतरे को पहले पहचान ले। क्योंकि एक छोटा कीट तभी बड़ा खतरा बनता है, जब किसान देर से जागता है।

## नियंत्रण का रास्ता: संतुलित रणनीति

इस कीट से लड़ाई एक ही उपाय से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management - IPM) अपनाना जरूरी है, जहां स्वच्छता, जैविक उपाय और आवश्यकता अनुसार रासायनिक नियंत्रण साथ-साथ चलते हैं। बाग की स्वच्छता सबसे पहला और सबसे प्रभावी कदम है। गिरे हुए संक्रमित फलों को रोजाना इकट्ठा कर नष्ट करना चाहिए, क्योंकि यही कीट के अगले चक्र का स्रोत बनते हैं।

जहां संभव हो, छोटे फलों की बैगिंग एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है। यह तरीका श्रमसाध्य जरूर है, लेकिन लगभग पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। जैविक विकल्पों में बैसिलस थुरिंगिएंसिस (Bacillus thuringiensis) और नीम आधारित उत्पाद अज़ादिरैक्टिन (Azadirachtin) प्रभावी और सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं ट्राइकोग्रामा (Trichogramma) जैसे परजीवी

कीट प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। रासायनिक नियंत्रण में आधुनिक अणु जैसे क्लोरेट्रानिलिप्रोल और इमामेक्टिन बैजोएट अच्छे परिणाम देते हैं। पहला छिड़काव फल के मटर आकार पर, और दूसरा 12-15 दिन बाद करना चाहिए। छिड़काव हमेशा शाम के समय और पूरे बाग में समान रूप से करें। अनुशंसित मात्रा का पालन अनिवार्य है और विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है।



टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के बीच डेयरी इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर है, जहां उत्पादन से अधिक महत्व प्रबंधन, इनोवेशन और वैल्यू चेन की दक्षता का ही गया है।

## डेयरी सेक्टर का बदलता चेहरा

# टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और बिज़नेस का नया समीकरण

### रफ्तार मीडिया संवाददाता

डेयरी सेक्टर ग्लोबल एग्रीकल्चर के सबसे अहम हिस्सों में से एक है, जो फूड सिक्योरिटी, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है। भारत जैसे देशों में, डेयरी फार्मिंग लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देती है और इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक मुख्य स्रोत है। दुनिया भर में, डेयरी प्रोडक्ट्स अपने प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन कंटेंट की वजह से इंसानों के न्यूट्रिशन के लिए जरूरी चीजें हैं। हाल के सालों में इस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हुई है। वैश्विक डेयरी बाजार का मूल्य 2025 में 1 ट्रिलियन USD से अधिक था और 2034 तक इसके लगभग दोगुना होने का अनुमान है, जो 8% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा। इस विकास को जनसंख्या विस्तार, शहरीकरण और प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग से बढ़ावा मिला है।

## फंक्शनल और हाई-प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग

डेयरी सेक्टर में सबसे खास ट्रेंड्स में से एक फंक्शनल फूड्स की बढ़ती मांग है। उपभोक्ता तेजी से ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश कर रहे हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रोटीन वाले फूड मार्केट का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता और फिटनेस के रुझान हैं। हाल की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि ज्यादा प्रोटीन वाले दही और डेयरी ड्रिंक्स की भारी मांग है - खासकर युवा उपभोक्ताओं के बीच - 'जो भोजन ही दवा है' (food as medicine) के उभरते रुझान को दर्शाता है।



## कहां बदल रहा है डेयरी सेक्टर?

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट डेयरी फार्मिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और डेटा एनालिटिक्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन डेयरी फार्मिंग में क्रांति ला रहा है। स्मार्ट सिस्टम जानवरों की हेल्थ, दूध देने की क्षमता और खाने के पैटर्न की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑपरेशनल

कॉस्ट कम होती है। रिसर्च से पता चलता है कि डेटा-आधारित डेयरी मैनेजमेंट बेहतर रिसोर्स इस्तेमाल के ज़रिए फ़ैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है और सस्टेनेबल खेती फार्मिंग के तरीकों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, दूध निकालने और खिलाने के सिस्टम में ऑटोमेशन से मज़दूरों की कार्यक्षमता और फ़ार्म का मुनाफ़ा बढ़ रहा है।



## सप्लाई चेन का

### आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

डेयरी सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफी आधुनिकीकरण हो

रहा है। ये टेक्नोलॉजी पूरी वैल्यू चेन में ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसिबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कम होते हैं और

बेहतर क्वालिटी कंट्रोल पक्का होता है, जो कंज्यूमर का भरोसा और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।

## दूध की यात्रा: ऑपरेशनल डायनामिक्स

डेयरी सेक्टर एक मल्टी-लेयर्ड वैल्यू चेन के ज़रिए काम करता है, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। प्रोडक्शन लेवल पर, डेवलपिंग इकॉनमी में छोटे किसान हावी हैं, जो कुल दूध प्रोडक्शन में अहम योगदान देते हैं। इसके बाद दूध को कोऑपरेटिव नेटवर्क के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है और प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी तक पहुँचाया जाता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे संस्थानों ने डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और किसानों को बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रोसेसिंग से कच्चे दूध को चीज़, दही, मक्खन और मिल्क पाउडर जैसे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। दूध के जल्दी खराब होने की वजह से अच्छे कोल्ड चेन सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं। आखिरी स्टेज में सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रिटेल चैनल के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। दुनिया भर में दूध का प्रोडक्शन हर साल करीब 1.8% की दर से लगातार बढ़ने की उम्मीद है, जो पशुओं की संख्या बढ़ाने के बजाय प्रोडक्टिविटी में सुधार की वजह से होगा। यह एफिशिएंसी-ओरिएंटेड डेयरी सिस्टम की ओर बदलाव दिखाता है।



## एक नज़र में: डेयरी सेक्टर

- वैश्विक बाज़ार (2025): 1 ट्रिलियन USD से अधिक
- अनुमानित वृद्धि दर (CAGR): 8% से अधिक
- वार्षिक उत्पादन वृद्धि: लगभग 1.8%
- प्रमुख ट्रेंड: AI, IoT, हाई-प्रोटीन उत्पाद, सस्टेनेबिलिटी
- प्रमुख चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन, कीमतों में उतार-चढ़ाव, टांचागत कमियाँ

## प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और प्रीमियमाइजेशन

डेयरी सेक्टर वैल्यू एडिशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर तेज़ी से फोकस कर रहा है। स्पेशलिटी चीज़, फ्लेवर्ड मिल्क और डेयरी-बेस्ड स्नैक्स जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। मार्केट रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशन डेयरी इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक मुख्य कारण है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर यह बदलाव, क्वालिटी, सुविधा और अपनी पसंद की चीज़ों के प्रति बदलते कंज्यूमर की पसंद को दिखाता है।

## वैकल्पिक डेयरी प्रोडक्ट्स का चलन

प्लांट-बेस्ड और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के आने से कॉम्पिटिशन का माहौल बदल रहा है। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और खान-पान की पसंद की वजह से प्लांट-बेस्ड डेयरी मार्केट के काफी बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, पारंपरिक डेयरी उत्पाद अपने पोषण संबंधी फ़ायदों और उपभोक्ताओं की उनसे जान-पहचान की वजह से अब भी बाज़ार पर हावी हैं। आने वाले सालों में पारंपरिक और वैकल्पिक डेयरी उत्पादों के बीच मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है।



## सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंटल ट्रांज़िशन

डेयरी एग्रीबिजनेस में सस्टेनेबिलिटी एक सेंट्रल थीम बन गई है। डेयरी फ़ार्मिंग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन में एक बड़ा योगदान देती है। इस वजह से, इंडस्ट्री पर पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल तरीके अपनाने का दबाव बढ़ रहा है। मीथेन कम करने वाले फ़ीड एडिटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, और सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इनोवेशन लागू किए जा रहे हैं। अध्ययन

यह भी दिखाते हैं कि तकनीकी हस्तक्षेप डेयरी कार्यों में ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी के नतीजे बेहतर हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन डेयरी उत्पादन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि बढ़ते तापमान से दूध का उत्पादन कम हो सकता है और जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यह जलवायु-अनुकूल डेयरी सिस्टम की आवश्यकता पर जोर देता है।

## डेयरी क्षेत्र में चुनौतियाँ

डेयरी सेक्टर की प्रगति के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। कीमतों में उतार-चढ़ाव और बाज़ार की अनिश्चितता, आपूर्ति और माँग के असंतुलन के कारण किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ाती है। जलवायु परिवर्तन चारे की उपलब्धता, जल संसाधनों और

पशुओं की उत्पादकता को प्रभावित करता है। हीट स्ट्रेस दूध के उत्पादन को काफी कम कर सकता है, खासकर गर्म इलाकों में। ढाँचागत कमियाँ - विशेषकर विकासशील देशों में - बड़े पैमाने पर उत्पादन के फ़ायदों को सीमित करती हैं और आधुनिक तकनीकों

को अपनाने में रुकावट डालती हैं। उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और वीगनवाद (पूरी तरह से शाकाहारी जीवनशैली) का बढ़ता चलन भी डेयरी उत्पादों की खपत के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, जिससे उत्पादकों को लगातार अनुकूलन की आवश्यकता है।



## डेयरी इंडस्ट्री की राह

डेयरी सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी की चिंताओं और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के कारण व्यापक बदलाव हो रहा है। हालांकि इस सेक्टर में ग्रोथ के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं, लेकिन इसे स्ट्रक्चरल और एनवायरनमेंटल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। डेयरी इंडस्ट्री की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलाइज़ेशन, सस्टेनेबिलिटी और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक होगा।

## कृषि-व्यवसाय पर असर

डेयरी सेक्टर में हो रहे बदलावों का कृषि-व्यवसाय पर गहरा असर पड़ रहा है। सबसे पहले, इंफ़्रास्ट्रक्चर - खासकर कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग सुविधाओं - में निवेश की आवश्यकता बढ़ रही है। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से काम की कुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अवसर मिलते हैं। तीसरा, लंबे समय तक टिके रहने के लिए बिजनेस की रणनीतियों में सस्टेनेबिलिटी को शामिल करना ज़रूरी हो गया है। तेज़ी से बदलते बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कंपनियों को इनोवेशन और प्रोडक्ट डिफ़रेंशिएशन पर भी ध्यान देना होगा।



दुनिया का एक समुद्री रास्ता जब तनाव में आता है, तो असर सिर्फ जहाजों पर नहीं, खेतों पर भी पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वैश्विक यूरिया व्यापार का 30% से अधिक और अमोनिया व फॉस्फेट व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

## हॉरमुज़ संकट: क्या महंगी होगी खरीफ की खेती?

### रफ्तार मीडिया || सवांदाता

अमेरिका-ईरान टकराव ने एक बार फिर हॉरमुज़ जलडमरूमध्य को वैश्विक चिंता के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह वही संकरा समुद्री रास्ता है, जिससे होकर तेल, गैस और उर्वरकों का बड़ा हिस्सा दुनिया भर में पहुंचता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वैश्विक यूरिया व्यापार का 30% से अधिक और अमोनिया व फॉस्फेट व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यहां पैदा हुआ तनाव केवल ऊर्जा बाजार की खबर नहीं रह जाता - यह सीधे खाद की लागत और खेती की तैयारी से जुड़ जाता है। भारत के लिए यह चिंता और गहरी है, क्योंकि खरीफ का मौसम अब दूर नहीं। बुआई से पहले किसान बीज, डीजल, सिंचाई और खाद के खर्च का हिसाब लगाने लगता है। ऐसे में अगर अमेरिका-ईरान संघर्ष लंबा खिंचता है, जहाजों की आवाजाही जोखिम भरी होती है, समुद्री बीमा महंगा पड़ता

है और गैस-आधारित उर्वरकों की आपूर्ति पर दबाव आता है, तो इसका पहला असर 'कमी' के रूप में नहीं, बल्कि 'महंगी तैयारी' के रूप में खेत तक पहुंचेगा। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चिंता है। फिलहाल स्थिति घबराहट वाली नहीं दिखती। भारत सरकार के अनुसार, 23 मार्च 2026 तक देश में 53.08 लाख टन यूरिया, 21.80 लाख टन डीएपी, 7.98 लाख टन एमओपी और 48.38 लाख टन एनपीकेएस का स्टॉक मौजूद था। यानी तात्कालिक खाद संकट के संकेत नहीं हैं। लेकिन बाजार का अनुभव कहता है कि लंबे भू-राजनीतिक तनाव पहले लागत बढ़ाते हैं, फिर अनिश्चितता फैलाते हैं। इसलिए असली सवाल युद्ध का नहीं, उसके आर्थिक असर का है। हॉरमुज़ में उठी हलचल आने वाले हफ्तों में तय कर सकती है कि खरीफ 2026 किसान के लिए सिर्फ मौसम की चुनौती होगी - या लागत की भी।

### क्यों अहम है हॉरमुज़?

हॉरमुज़ जलडमरूमध्य को समझना हो, तो उसे सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाय चैन की नब्ब की तरह देखना होगा। 2025 में औसतन करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और तेल उत्पाद इसी रास्ते से गुजरे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, 2024 में यहां से गुजरने वाला तेल वैश्विक पेट्रोलियम खपत के करीब 20% के बराबर था। यानी यहां मामूली तनाव भी वैश्विक असर पैदा करता है। भारत के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इस मार्ग से गुजरने वाला बड़ा हिस्सा एशिया की ओर आता है। IEA के अनुसार, 2025 में हॉरमुज़ से गुजरने वाले तेल और तेल उत्पादों का लगभग 80% एशियाई बाजारों के लिए था। यही कारण है कि अमेरिका-ईरान तनाव की खबर भारतीय किसान के लिए भी अप्रासंगिक नहीं है। यह रास्ता सिर्फ तेल का नहीं, ऊर्जा सुरक्षा का है - और ऊर्जा सुरक्षा ही आगे चलकर उर्वरक, दुलाई और खेती की लागत तय करती है।



### कतर की 93% और यूएई की 96% एलएनजी निर्यात इसी मार्ग से होता है

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में हॉरमुज़ से 110 बीसीएम से अधिक एलएनजी भी गुजरी, जो वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा है। IEA के अनुसार, कतर की 93% और यूएई की 96% एलएनजी निर्यात इसी मार्ग से होकर निकलता है। यही वह बिंदु है, जहां अमेरिका-ईरान संघर्ष उर्वरक की कहानी में बदलने लगता है। गैस अटकी तो अमोनिया पर दबाव, और अमोनिया महंगा हुआ तो खाद की लागत बढ़ना तय है। समुद्र में तनाव का यही सीधा अर्थ है। ऊपर से, युद्ध का सबसे तेज असर जहाजों की आवाजाही पर दिखता है।



## भारत की स्थिति: घबराहट नहीं, लेकिन ठील भी नहीं

अमेरिका-ईरान तनाव और हॉरमुज पर बढ़ते जोखिम के बीच भारत की स्थिति को एक वाक्य में समझा जाए, तो तस्वीर यह है - हालात अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन यह नियंत्रण स्वतः नहीं बना रहेगा। सरकार ने मार्च में उर्वरक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी, ताकि घरेलू उत्पादन पर पहला झटका न पड़े। यही इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत है: संकट के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, पहले से तैयारी करना। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की उर्वरक व्यवस्था केवल कारखानों पर निर्भर नहीं करती; यह आयात, गैस, समुद्री मार्ग, सख्सीडी और समय पर आपूर्ति - इन सभी के संतुलन पर टिकी है। इसलिए भले ही इस समय बाजार में घबराहट के संकेत न दिखें, लेकिन लंबा अमेरिका-ईरान संघर्ष इस संतुलन को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है। सरकारी संकेत भी यही बताते हैं कि तैयारी मजबूत रखनी होगी, क्योंकि खरीफ से पहले सप्लाई चेन की स्थिरता ही सबसे बड़ा सवाल है।

## भारत को सतर्क रहना होगा

यहीं से भारत की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर तनाव जल्द थमता है, तो मौजूदा व्यवस्था दबाव सह सकती है। लेकिन यदि समुद्री जोखिम, गैस आपूर्ति की अनिश्चितता और शिपिंग लागत लंबे समय तक बनी रहती है, तो असर सीधे 'कमी' के रूप में नहीं, बल्कि 'प्रबंधन पर बढ़ते दबाव' के रूप में सामने आएगा। सरकार को आयात, घरेलू उत्पादन और वितरण - तीनों मोर्चों पर एक साथ सतर्क रहना होगा। किसान की नजर से देखें, तो तस्वीर साफ है। अभी कहानी संकट की नहीं, तैयारी की है। लेकिन खरीफ की खेती समय के अनुशासन पर चलती है - और समय पर सबसे पहले चोट अनिश्चितता करती है। अगर अमेरिका-ईरान तनाव लंबा खिंचता है, तो भारत की चिंता 'खाद उपलब्ध है या नहीं' से पहले 'दबाव कितना बढ़ेगा' पर टिक जाएगी। आने वाले हफ्तों में यही फर्क सबसे निर्णायक साबित हो सकता है।



## तेल नहीं, असली कहानी

### गैस और अमोनिया की

अमेरिका-ईरान तनाव की खबर आते ही सबसे पहले कच्चे तेल का जिक्र होता है। लेकिन उर्वरक की दुनिया की असली धड़कन कहीं और है - गैस और उससे बनने वाला अमोनिया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, दुनिया में अमोनिया उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा प्राकृतिक गैस पर आधारित है, जबकि तेल और बिजली की संयुक्त हिस्सेदारी बेहद सीमित है। यानी अगर समुद्री तनाव गैस की उपलब्धता, दुलाई या कीमत पर असर डालता है, तो उर्वरक बाजार पर उसका दबाव पड़ना लगभग तय है। यही वजह है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष को सिर्फ 'कच्चे तेल की कहानी' के रूप में पढ़ना अधूरा होगा। हॉरमुज में जोखिम बढ़ने का मतलब सिर्फ तेल की कीमतों में उछाल नहीं है; इसका अर्थ यह भी है कि एलएनजी की आवाजाही, अमोनिया की सप्लाई और उर्वरक कच्चे माल की लागत पर दबाव बढ़ सकता है। IEA साफ कहता है कि कई देश आयातित एलएनजी पर आधारित उर्वरक उत्पादन करते हैं। ऐसे में गैस आपूर्ति में कोई भी व्यवधान सीधे खाद की लागत और उपलब्धता की शर्तों को प्रभावित कर सकता है।

## भारत जैसे देश के लिए यही सबसे बड़ा संकेत

युद्ध का असर बाजार में हमेशा एक तय क्रम से आता है। पहले समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ता है, फिर जहाजों की रफ्तार धीमी पड़ती है या वे रुक जाते हैं, इसके बाद बीमा और मालभाड़ा महंगा होता है, और अंततः कच्चे माल की कीमतें ऊपर जाती हैं। रॉयटर्स ने मार्च की शुरुआत में रिपोर्ट किया कि अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान हॉरमुज से शिपिंग कई दिनों तक गंभीर रूप से बाधित रही। इसका मतलब यह है कि उर्वरक बाजार पर दबाव अचानक नहीं आता, बल्कि परत-दर-परत बनता है - और जब तक यह साफ दिखता है, तब तक लागत पहले ही बढ़ चुकी होती है। भारत जैसे देश के लिए यही सबसे बड़ा संकेत है। अगर तनाव अल्पकालिक रहा, तो बाजार धीरे-धीरे संतुलन पा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका-ईरान टकराव लंबा खिंचता है, तो खरीफ से पहले उर्वरक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।



## पहला दबाव कहां दिखेगा?

अमेरिका-ईरान तनाव का पहला असर अक्सर वहां नहीं दिखता, जहां लोग सबसे पहले डरते हैं। आम चर्चा यह होती है कि क्या खाद की कमी हो जाएगी। लेकिन बाजार का अनुभव कुछ और कहता है - शुरुआत 'कमी' से नहीं, 'महंगाई और अनिश्चितता' से होती है। जैसे ही हॉरमुज पर जोखिम बढ़ता है, सबसे पहले शिपिंग महंगी होती है, बीमा दरें चढ़ती हैं और माल की आवाजाही पर अतिरिक्त शर्तें लगने लगती हैं। यही शुरुआती दबाव है, जो धीरे-धीरे उर्वरक बाजार तक उतरता है। यही वजह है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष को सिर्फ युद्ध की खबर के रूप में नहीं, बल्कि लागत की खबर के रूप में पढ़ना चाहिए। सॉयटर्स ने मार्च की शुरुआत में बताया कि मध्य-पूर्व से तेल और गैस टुलाई की दरें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं, जबकि कुछ जहाजों के लिए युद्ध-जोखिम बीमा कई गुना बढ़ गया। बाद की रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि बड़ी शिपिंग कंपनियों की अतिरिक्त साप्ताहिक लागत करोड़ों डॉलर तक पहुंच रही है। इसका सीधा अर्थ है - समुद्र में पैदा हुआ जोखिम अंततः उन देशों और सेक्टरों तक बिल बनकर पहुंचता है, जो यह माल खरीदते हैं।

उर्वरक के मामले में यह दबाव और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यहां केवल मालभाड़ा ही नहीं, समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खरीफ से पहले सप्लाई चेन में मामूली देरी भी चिंता पैदा कर सकती है। ऊपर से सरकार ने खुद माना है कि पश्चिम एशिया की परिस्थितियों को देखते हुए उर्वरक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देनी पड़ी। इसका मतलब साफ है - जोखिम केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि नीति-स्तर पर भी गंभीरता से महसूस किया जा रहा है।

इसलिए किसान की भाषा में निष्कर्ष सीधा है: पहला संकट 'खाद नहीं मिलेगी' वाला नहीं, बल्कि 'खाद पर दबाव बढ़ रहा है' वाला होता है। अगर अमेरिका-ईरान तनाव लंबा खिंचता है, तो यही दबाव आगे चलकर खरीफ की लागत, सरकारी सब्सिडी और समय पर उपलब्धता - तीनों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल कहानी चेतावनी की है, लेकिन बाजार में चेतावनी ही अक्सर सबसे पहली और सबसे महंगी खबर साबित होती है।

## खरीफ पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर अमेरिका-ईरान तनाव लंबा खिंचता है, तो उसका असर खरीफ पर सीधे एक रूप में नहीं दिखेगा। खेती में दबाव हमेशा धीरे-धीरे बनता है - पहले बाजार बेचैन होता है, फिर लागत का हिसाब बदलता है, और अंततः किसान अपनी तैयारी पर दोबारा विचार करता है। खरीफ 2026 के लिए भी यही क्रम निर्णायक रहेगा। इस समय सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि अचानक पूरे देश में खाद गायब हो जाएगी, बल्कि यह है कि समुद्री जोखिम, गैस की अनिश्चितता और शिपिंग लागत मिलकर तैयारी को महंगा और अस्थिर बना सकते हैं। खरीफ की खेती समय के अनुशासन

पर चलती है। बीज, खाद, डीजल, सिंचाई और मजदूरी - इनमें से किसी एक कड़ी पर भी दबाव बढ़ा, तो पूरी तैयारी प्रभावित होती है। उर्वरक के मामले में यह और भी संवेदनशील है, क्योंकि बुआई के समय उपलब्धता के साथ-साथ भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। अगर बाजार को संकेत मिलता है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष लंबा चलेगा, तो असर केवल आयात बिल तक सीमित नहीं रहेगा; यह आपूर्ति की गति, सरकारी प्रबंधन और किसानों के मनोविज्ञान - तीनों को प्रभावित करेगा। कई बार वास्तविक कमी से पहले ही अनिश्चितता खुद एक दबाव बन जाती है।

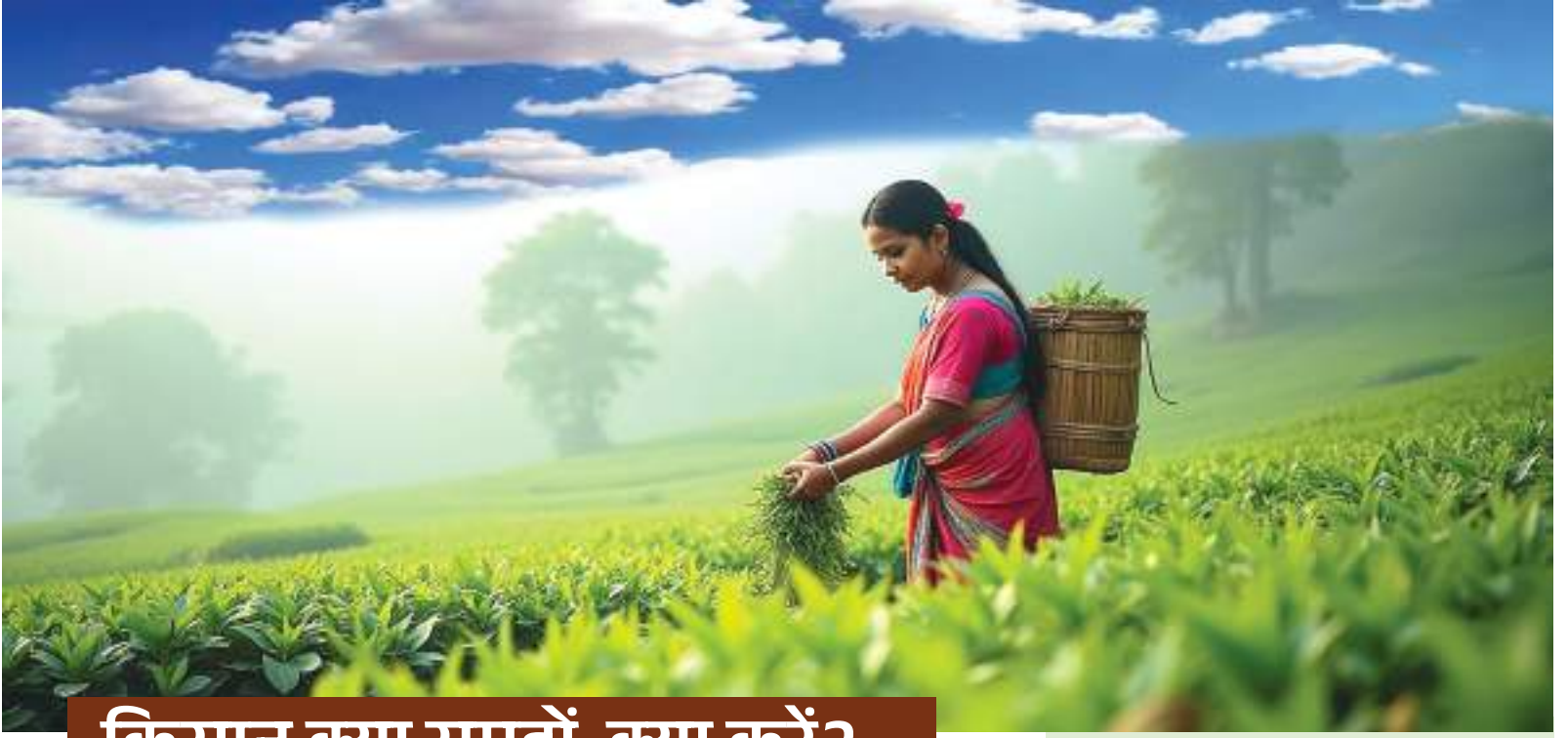


## फसलों में शुरुआती निवेश अधिक होता

इसका असर फसल-स्तर पर भी दिख सकता है। जिन फसलों में शुरुआती निवेश अधिक होता है, वहां किसान लागत को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकता है। जहां सिंचाई, खाद और डीजल का खर्च पहले से ही भारी है, वहां मामूली लागत वृद्धि भी फसलों को बदल सकती है। यही कारण है कि अमेरिका-ईरान तनाव की यह कहानी केवल अंतरराष्ट्रीय

बाजार की नहीं, बल्कि खेत के फैसले की भी कहानी है। किसान मौसम को जितना देखता है, उतना ही अपनी जेब को भी तौलता है। अगर दोनों तरफ दबाव बढ़ा, तो खरीफ की शुरुआत ही अधिक जोखिमभरी लग सकती है। फिलहाल सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि खरीफ पर तात्कालिक झटका तय मान लेना जल्दबाजी होगी। भारत के पास प्रबंधन

की क्षमता है और सरकार ने पहले से कुछ एहतियाती कदम भी उठाए हैं। लेकिन अगर अमेरिका-ईरान तनाव लंबा चलता है, तो खरीफ 2026 में सबसे पहले असर लागत, समय और भरोसे पर दिखेगा। कई बार खेत में संकट मौसम से नहीं, बल्कि तैयारी की बढ़ती कीमत से शुरु होता है - और इस बार भी असली परीक्षा शायद वहीं होगी।



## किसान क्या समझें, क्या करें?

अमेरिका-ईरान तनाव और हॉरमुज पर बढ़ते खतरे की इस पूरी कहानी में किसान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल घबराहट से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। ऐसे समय में बाजार में अफवाहें तेजी से फैलती हैं - कहीं कहा जाएगा कि खाद गायब हो जाएगी, कहीं कीमतों में अचानक उछाल की बात होगी। लेकिन खेती अफवाहों पर नहीं, तैयारी पर चलती है। इसलिए पहला कदम यही है कि किसान स्थानीय उपलब्धता, सहकारी समितियों, अधिकृत विक्रेताओं और सरकारी वितरण व्यवस्था पर नजर रखें - न कि हर उड़ती खबर पर।

दूसरा, खरीफ की तैयारी इस बार थोड़ा ज्यादा संतुलित वित्तीय नजरिए से करनी होगी। बीज, खाद, डीजल और सिंचाई - इन सभी को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक समग्र लागत के रूप में देखना होगा। क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय तनाव लंबा खिंचता है, तो असर केवल खाद तक सीमित नहीं रहेगा; पूरी खेती की लागत पर दबाव बनेगा। ऐसे

में संतुलित उर्वरक उपयोग, जरूरत के अनुसार खरीद और समय पर योजना - ये तीनों पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तीसरा, अनिश्चितता के समय अंधाधुंध खरीद समाधान नहीं होती। कई बार घबराहट में की गई अतिरिक्त खरीद बाजार पर और दबाव डालती है। समझदारी यह है कि किसान अपनी वास्तविक जरूरत पहचानें, स्थानीय सलाह लें और तैयारी चरणबद्ध ढंग से करें। खरीफ की सफलता केवल मानसून पर निर्भर नहीं करती; यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि दबाव के समय फैसले कितने संतुलित लिए जाते हैं। अखिरकार, इस पूरी कहानी का सबसे अहम संदेश यही है कि दुनिया की हलचल अब खेत से बहुत दूर नहीं रही। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर वैश्विक संकट सीधे तबाही में बदलेगा। सही जानकारी, समय पर निर्णय और संतुलित तैयारी - ये तीनों मिलकर बड़े झटकों का असर कम कर सकते हैं। फिलहाल किसान के पास यही सबसे बड़ी ताकत है।

## असली सवाल युद्ध नहीं, लागत है

अमेरिका-ईरान तनाव की इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि खेत पर असर अक्सर सीधे और अचानक नहीं दिखता। कई बार युद्ध की आवाज पहले समुद्र में सुनाई देती है, फिर बाजार में, और अंततः किसान की लागत में। हॉरमुज पर बढ़ता जोखिम भी फिलहाल उसी क्रम से आगे बढ़ रहा है। अभी भारत में तात्कालिक उर्वरक संकट जैसी स्थिति नहीं दिखती, लेकिन यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि दुनिया का यह तनाव खेत तक नहीं पहुंचेगा। इस परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीफ 2026 की चुनौती सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि लागत और अनिश्चितता भी हो सकती है। अगर अमेरिका-ईरान संघर्ष लंबा खिंचता है, तो पहला दबाव उर्वरक, शिपिंग, गैस और सरकारी प्रबंधन पर दिखेगा। उसके बाद यही दबाव धीरे-धीरे किसान की तैयारी, बजट और निर्णयों तक पहुंचेगा। कई बार संकट की शुरुआत गोदाम से नहीं, बल्कि दिमाग से होती है - जब किसान को लगने लगता है कि इस बार खेती पहले से ज्यादा महंगी और जोखिमभरी हो सकती है। यही कारण है कि इस समय सबसे संतुलित नजरिया न तो घबराहट का है और न ही लापरवाही का। सच यह है कि भारत ने तैयारी की है, लेकिन तैयारी की असली परीक्षा तब होती है जब बाहरी संकट लंबा चलता है। आने वाले हफ्ते सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए नहीं, बल्कि भारतीय खेती के लिए भी निर्णायक होंगे।

## अफवाह से नहीं, जानकारी से चलना

अमेरिका-ईरान तनाव की यह कहानी केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ भारतीय किसान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हॉरमुज पर बढ़ता जोखिम धीरे-धीरे उर्वरक, शिपिंग, गैस और खेती की लागत पर दबाव बना सकता है। फिलहाल हालात ऐसे नहीं हैं कि तुरंत घबराहट हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि लंबा तनाव बाजार को अस्थिर कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे सीधा निष्कर्ष यही है कि खतरा फिलहाल 'कमी' से

ज्यादा 'लागत' का है। अगर समुद्री रास्तों पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो उसका असर पहले महंगे मालभाड़े, महंगे बीमा, गैस पर दबाव और आपूर्ति प्रबंधन पर दिखेगा - और फिर वही दबाव किसान की खरीफ तैयारी तक पहुंचेगा। किसान के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यही है - अफवाह से नहीं, जानकारी से चलना। सरकार और बाजार - दोनों की चाल पर नजर रखनी होगी। खरीफ की तैयारी में इस बार लागत का आकलन थोड़ी अतिरिक्त सावधानी से करना होगा।



## गर्मियों में एक्वेरियम की देख-रेख

जब तापमान बढ़ता है, तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता - आपके एक्वेरियम की छोटी-सी दुनिया भी खतरे में आ जाती है। सही देखभाल से आप अपनी मछलियों को सुरक्षित और खुश रख सकते हैं।

# नाज़ुक दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी

### रफ्तार मीडिया || सवांदाता

गर्मियों की एक दोपहर। खिड़की से आती तेज धूप, कमरे में चल रहा पंखा, और कोने में रखा आपका सुंदर एक्वेरियम - जिसमें रंग-बिरंगी मछलियाँ शांति से तैर रही हैं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर बढ़ता तापमान इस शांत दुनिया को भीतर ही भीतर प्रभावित कर रहा है? एक्वेरियम केवल सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) है। इसमें रहने वाली मछलियाँ पूरी तरह आप पर निर्भर होती हैं - खासकर तब, जब मौसम उनके अनुकूल न हो। गर्मियों में यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। एक्वेरियम में रहने वाली सबसे सामान्य मछली गोल्ड फिश के लिए 20°C से 28°C तक का तापमान आदर्श माना जाता है। इस सीमा के भीतर वह सक्रिय, स्वस्थ और सहज रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान इससे ऊपर जाता है, पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है— और यहीं से समस्या शुरू होती है। सिर्फ गोल्ड फिश ही नहीं, बल्कि अधिकांश एक्वेरियम मछलियाँ उच्च तापमान को लंबे समय तक सहन नहीं कर पातीं। गर्म पानी उनके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, जिससे उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है - जो उस समय पानी में कम हो रही होती है।

## मछलियों की भाषा समझें : खतरे के संकेत

मछलियाँ बोल नहीं सकतीं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कुछ कहता है। यदि आप ध्यान दें, तो वे समय रहते चेतावनी दे देती हैं।

- ▶ मछलियों का बार-बार पानी की सतह पर आना
- ▶ मुँह खोलकर तेजी से सांस लेना

▶ गलफड़ों (गिल्स) का तेजी से फड़फड़ाना  
ये सभी संकेत हैं कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है और तापमान बढ़ चुका है। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है - यहाँ तक कि मछलियों की जान भी जा सकती है।



## गर्मी से बचाव: छोटे उपाय, बड़ा असर

**1. एरेटर** - ऑक्सीजन का जीवनदायक स्रोत एक्वेरियम में एरेटर (Aerator) लगाना गर्मियों में सबसे जरूरी कदमों में से एक है। यह पानी में हवा का संचार बढ़ाता है और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखता है, जिससे मछलियाँ सहज रूप से सांस ले पाती हैं।  
**2. पानी को ठंडा रखने के आसान तरीके**  
एक्वेरियम का ढक्कन हटाकर उसके पास पंखा चलाना सबसे आसान उपाय है। इससे पानी की सतह ठंडी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। अगर स्थिति ज्यादा खराब हो जाए, तो आप बर्फ की थैली या ठंडा पानी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें - तापमान को कभी भी अचानक न बदलें। धीरे-धीरे किया गया बदलाव ही सुरक्षित होता है।

**3. उपकरणों का संतुलित उपयोग**  
गर्मियों में एक्वेरियम के बल्ब और हीटर का कम से कम उपयोग करें। अक्सर लोग इन्हें बंद करना भूल जाते हैं, जिससे पानी का तापमान अनजाने में बढ़ता रहता है।

**4. सही स्थान का चुनाव**  
अगर आपका एक्वेरियम खिड़की के पास रखा है, तो उसे तुरंत बदल दें। सीधी धूप और गर्म हवा पानी को तेजी से गर्म करती है, जिससे मछलियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

**5. थर्मोमीटर - आपका सबसे भरोसेमंद साथी**  
एक्वेरियम में थर्मोमीटर लगाना बेहद जरूरी है। यह आपको हर समय पानी का तापमान बताता है, जिससे आप समय रहते कदम उठा सकते हैं।



## तेल से जीरे तक

कच्चे तेल की उछाल, महंगी लॉजिस्टिक्स और दबाव में रुपया—पश्चिम एशिया का संघर्ष अब भारत के मसाला बाजार की संरचना को बदल रहा है। मांग बरकरार है, लेकिन आपूर्ति की राहें टूट रही हैं।

# तेल से जीरे तक: पश्चिम एशिया का तनाव कैसे बदल रहा है भारत का मसाला गणित

## रफ्तार मीडिया || सवांददाता

“जिनके घर शीशे के होते हैं...” यह कहावत आज की दुनिया में बेमानी लगती है। ईरान-अमेरिका तनाव के बीच हर कोई पत्थर फेंक रहा है - और उसके टुकड़े अब वैश्विक व्यापार के हर कोने में गिर रहे हैं।

पश्चिम एशिया का तनाव अब केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं है। यह एक बहु-स्तरीय मैक्रो झटका बन चुका है, जो मुद्राओं, लॉजिस्टिक्स और कृषि व्यापार की बुनियादी संरचना को प्रभावित कर रहा है - और भारत का मसाला उद्योग इसकी सीधी चपेट में है। पिछले एक महीने में घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, माल दुलाई और बीमा महंगे हुए हैं, और भारतीय रुपया दबाव में आया है। ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं - यह एक जुड़ी हुई आर्थिक श्रृंखला है। ऊर्जा महंगी होती है तो परिवहन और प्रोसेसिंग लागत बढ़ती है; रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा और निर्यात अनिश्चित हो जाता है; और जब लॉजिस्टिक्स बाधित होते हैं, तो व्यापार धीमा और खर्चीला बन जाता है।

## मसालों की कीमतों को अभी क्या चला रहा है?

कारक	मसाला व्यापार पर प्रभाव
कच्चे तेल की कीमतें	परिवहन और प्रोसेसिंग लागत बढ़ती है
माल दुलाई व बीमा लागत	निर्यात मार्जिन घटता है
रुपया कमजोर	आयात महंगा, निर्यात अनिश्चित
लॉजिस्टिक्स में बाधा	खेप में देरी, कार्यशील पूंजी पर दबाव
उर्वरक व इनपुट लागत	अगली फसल पर जोखिम



## स्पाइस मार्केट की स्थिति

कमोडिटी	मौजूदा रुझान	मुख्य कारण
हल्दी	कीमतें नरम	कटाई के बाद निर्यात में सुस्ती
जीरा	अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन	खेप में देरी, बंदरगाहों पर भीड़
इलायची	कीमतों में गिरावट	खाड़ी देशों की सतर्क मांग
धनिया	तेजी की संभावना	कम कैरीओवर स्टॉक, FMCG मांग

## मांग है, लेकिन रास्ते बंद

पश्चिम एशिया लंबे समय से भारतीय मसालों का एक प्रमुख बाजार रहा है। जीरा, हल्दी और इलायची जैसे प्रमुख उत्पादों के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में जाता है। लेकिन मौजूदा हालात ने एक विरोधाभासी स्थिति पैदा कर दी है। मांग मौजूद है, लेकिन डिलीवरी ठप है। खेप में देरी हो रही है, शिपिंग रूट बदले जा रहे हैं और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी लंबे समय तक फंसी रह रही है। परिणामस्वरूप, वैश्विक मांग और घरेलू कीमतों के बीच एक स्पष्ट असंतुलन उभर आया है।

“यह मांग नहीं, बल्कि सप्लाई चेन और लागत हस्तांतरण का संकट है।”  
“कच्चे तेल से लेकर जीरे तक—पूरी वैल्यू चेन अब आपस में गहराई से जुड़ चुकी है।”



## बाज़ार का असंतुलन

इस असंतुलन के संकेत अब मंडियों में साफ दिखाई दे रहे हैं। हल्दी की कीमतें नरम पड़ गई हैं, क्योंकि कटाई के बाद के अहम समय में निर्यात की रफ्तार धीमी हुई है। जीरा, वैश्विक आपूर्ति की कमी और भारत की मजबूत स्थिति के बावजूद, लॉजिस्टिक्स बाधाओं के कारण किसानों को अपेक्षित कीमत नहीं दिला पा रहा है। इलायची बाजार में गिरावट और भी तेज है - खाड़ी देशों के खरीदार अनिश्चितता के चलते सतर्क रुख अपना रहे हैं। स्पष्ट है कि यह मांग में कमी का मामला नहीं है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में आई गड़बड़ी का असर है।

## महंगी खेती का दबाव

तत्काल व्यापारिक बाधाओं से आगे, एक और गंभीर चिंता उभर रही है—बढ़ती इनपुट लागत। वही भू-राजनीतिक तनाव जो तेल की कीमतों को बढ़ा रहा है, उर्वरकों और कृषि रसायनों की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। मसाला किसानों के लिए इसका सीधा अर्थ है खेती की लागत में वृद्धि। इससे बुवाई के फैसलों में बदलाव हो सकता है और आने वाले सीजन में उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों पर दबाव पड़ सकता है - विशेषकर हल्दी जैसी इनपुट-संवेदनशील फसलों में।

## रुपया: फायदा या भ्रम?

भारतीय रुपया हाल के हफ्तों में अस्थिर रहा है और दबाव में भी आया है। आमतौर पर कमजोर रुपया निर्यात को बढ़ावा देता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। बढ़ी हुई दुलाई लागत, भुगतान में देरी और वैश्विक अनिश्चितता ने इस लाभ को लगभग समाप्त कर दिया है। निर्यातक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ लागत और जोखिम दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि मुनाफे के मार्जिन सिमट रहे हैं। सरकारी राहत उपाय और नीतिगत लचीलापन फिलहाल कुछ स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि मसाला उद्योग अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ कीमतें केवल उत्पादन और मांग से नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक घटनाओं से भी प्रभावित होंगी।

## आगे का रास्ता

इस बदलते परिदृश्य में भारतीय मसाला उद्योग को अधिक लचीला और रणनीतिक बनना होगा। बाजारों का

विविधीकरण, मजबूत लॉजिस्टिक्स योजना और सक्रिय जोखिम प्रबंधन अब अनिवार्य हो गए हैं।

## तेल से मसाले तक: असर की श्रृंखला



## आने वाले 2-3 महीने: क्या देखें

आने वाले महीनों में मसाला बाजार की दिशा कई कारकों पर निर्भर करेगी—मॉनसून, रुपये की चाल, कैरीओवर स्टॉक और पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति। धनिया में कम स्टॉक के कारण मांग बढ़ने पर कीमतों में सुधार संभव है, खासकर नए वित्तीय वर्ष में FMCG कंपनियों की री-स्टॉकिंग के चलते। जीरा की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन निर्यात भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहेगा। हल्दी में स्टॉक-टू-यूज अनुपात तंग बना हुआ है, जिससे अस्थिरता बनी रह सकती है और मॉनसून निर्णायक कारक साबित होगा। अब मसालों की कीमतें सिर्फ मौसम से नहीं - दुनिया की सियासत से तय होंगी।

रकबे में विस्तार, MSP समर्थन और बेहतर उत्पादकता – रेपसीड-सरसों इस सीजन में सिर्फ अच्छी फसल नहीं, बल्कि खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के संतुलन को बदलने वाला कारक बनकर उभर रही है।



# सरसों की तेज़ी: 119 लाख टन उत्पादन का अनुमान क्या बदलेगा भारत का खाद्य तेल समीकरण?

## रफ्तार मीडिया

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है, अब धीरे-धीरे अपनी रणनीति बदलता दिख रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है - सरसों।

पिछले कुछ वर्षों में तिलहन उत्पादन को लेकर नीतिगत फोकस, MSP समर्थन और बेहतर कृषि तकनीकों ने इस फसल को फिर से मुख्यधारा में ला खड़ा किया है। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ अनिश्चित हैं, घरेलू उत्पादन में यह मजबूती आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से अहम हो जाती है।

## उत्पादन में मजबूती, बड़े बदलाव के संकेत

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) का रबी 2025-26 के लिए 119.4 लाख टन का उत्पादन अनुमान केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। यह पिछले वर्ष के 115.2 लाख टन से स्पष्ट वृद्धि है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार भी भारत में रेपसीड-सरसों उत्पादन लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है, जो तिलहन क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। दिलचस्प यह है कि यह वृद्धि किसी एक कारक का परिणाम नहीं, बल्कि बेहतर मौसम, तकनीक और नीति समर्थन का संयुक्त असर है।

## मंडी और बाजार: क्या बदलेगा?

बड़ी फसल का असर बाजार में धीरे-धीरे दिखना शुरू हो गया है। सरसों की आवक बढ़ने से कीमतों में स्थिरता आई है। तेल मिलों की क्रशिंग गतिविधि तेज हुई है। पीक सीजन में कीमतों पर दबाव संभव है। हालांकि, मजबूत घरेलू मांग और कम आयात इस दबाव को संतुलित कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक खाद्य तेल कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो घरेलू सरसों तेल की प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी।

इसका मतलब साफ है: घरेलू उत्पादन बढ़ेगा

आयात निर्भरता पर दबाव घटेगा कीमतों में स्थिरता आ सकती है

## नीति और संरचना: अगला कदम

सरसों उत्पादन में यह उछाल सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के साथ भी जुड़ा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) के तहत भारत 2030 तक घरेलू उत्पादन बढ़ाकर मांग का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करने का लक्ष्य रखता है।

**इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी होगा:**

बीज और तकनीक में निवेश प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन सुधार किसानों को स्थिर मूल्य संकेत



## रकबा बढ़ा, ट्रेंड मजबूत

इस साल रकबे में बढ़ोतरी - 92.15 से 93.91 लाख हेक्टेयर - सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि किसानों के बदलते भरोसे की कहानी है। MSP में हालिया बढ़ोतरी ने इस रुझान को और मजबूती दी है। 2025-26 सीजन के लिए सरसों का MSP बढ़ाया गया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य सुरक्षा मिली। साथ ही, उच्च उत्पादकता वाली नई किस्मों और बेहतर कृषि तकनीकों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। हाल ही में विकसित हाइब्रिड किस्में 10-15% तक अधिक पैदावार देने का दावा करती हैं।

## मैक्रो असर: खाद्य तेल समीकरण बदलेगा

भारत का खाद्य तेल बाजार आज भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। 2022-23 में देश ने करीब 16.5 मिलियन टन खाद्य तेल आयात किया था, जो कुल खपत का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब संकेत बदल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बढ़ती घरेलू सरसों फसल के चलते आयात में गिरावट देखी जा रही है और खरीदार सतर्क रुख अपना रहे हैं।

## जोखिम अभी भी बाकी

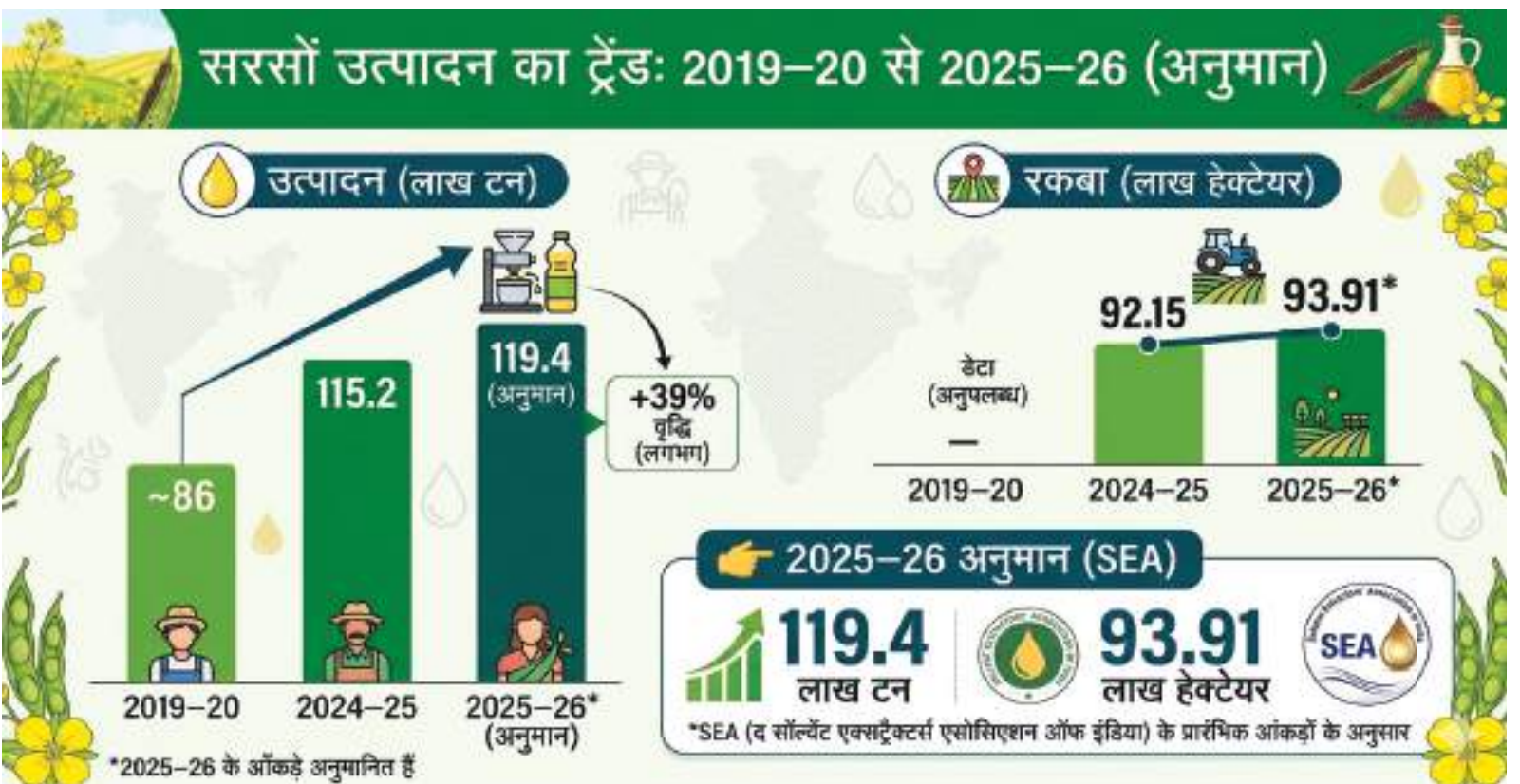
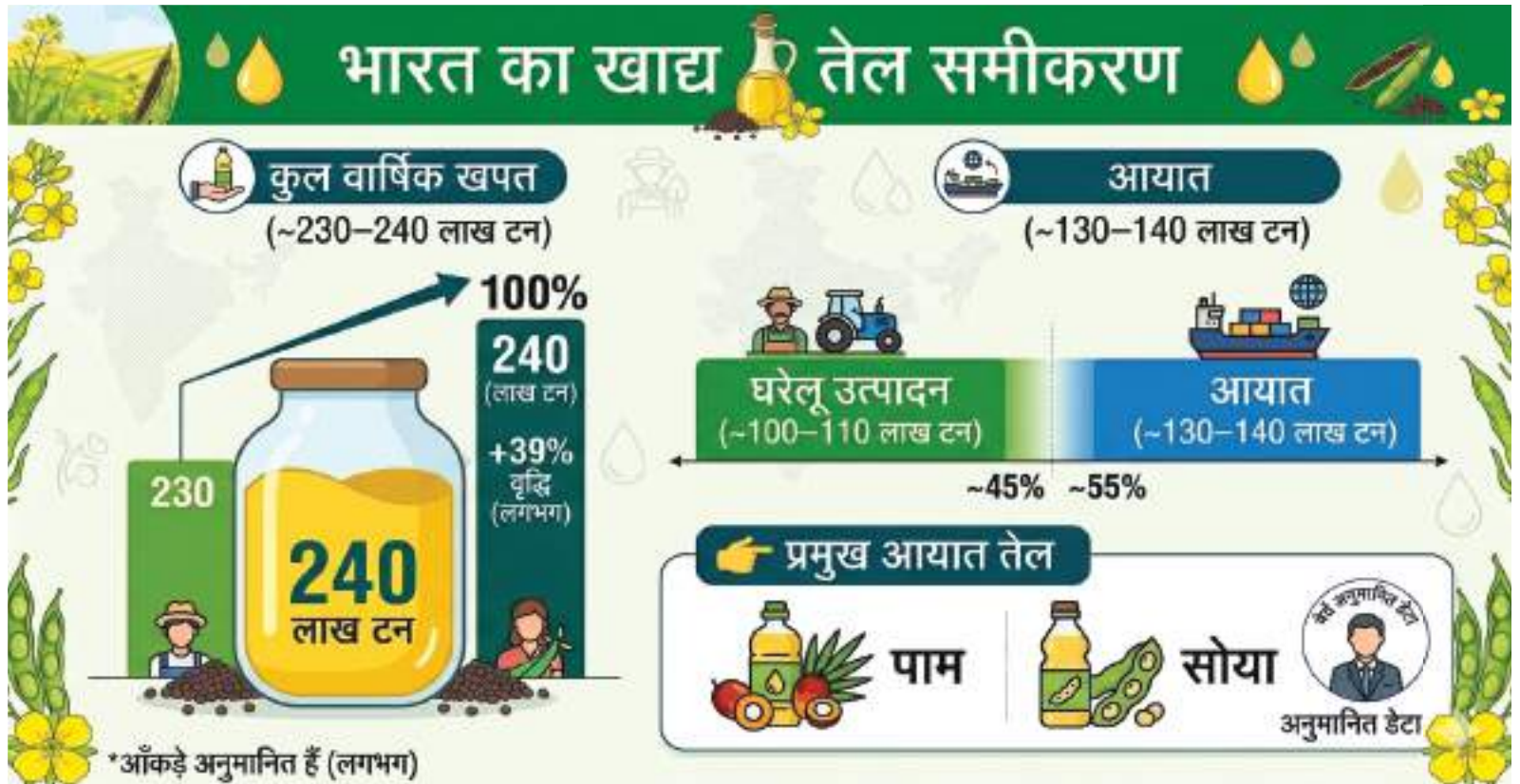
तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। कुछ जोखिम अभी भी बने हुए हैं: वैश्विक बाजार में अस्थिरता - खासकर कच्चे तेल और पाम ऑयल में उतार-चढ़ाव मौसम में अंतिम समय का बदलाव

लॉजिस्टिक्स और कटाई के बाद नुकसान इसके अलावा, भारत की औसत उत्पादकता अभी भी वैश्विक औसत से कम है, जो दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है।

## क्या यह टर्निंग पॉइंट है?

सरसों की यह बढ़त केवल एक अच्छा कृषि सीजन नहीं, बल्कि एक संभावित टर्निंग पॉइंट है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो भारत आयात पर निर्भरता घटा सकता है

घरेलू तेल उद्योग मजबूत होगा किसानों की आय में स्थिरता आएगी लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादन की यह गति कितनी टिकाऊ बनती है।





## शहरों में 'हीट आइलैंड' कंक्रीट की गर्मी

शहरों में गर्मी का असर और भी ज्यादा महसूस होता है। कंक्रीट की इमारतों, डामर की सड़कें और कम होती हरियाली - ये सभी मिलकर 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव पैदा करते हैं। दिन में जमा हुई गर्मी रात में भी बाहर नहीं निकलती। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में यह असर साफ दिखता है, जहां रात का तापमान भी कई बार 30°C से नीचे नहीं जाता। एसी और कूलर की बढ़ती मांग से बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती है। लेकिन हर किसी के पास यह सुविधा नहीं है। शहरों गरीब - रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, फुटपाथ विक्रेता - सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

# जलता भारत, ठंडा समाधान?

## रफ्तार मीडिया || सवांददाता

मार्च के आखिरी हफ्ते में ही लखनऊ की 32 वर्षीय प्रिया ने महसूस कर लिया था कि इस बार गर्मी सामान्य नहीं है। सुबह 9 बजे ही धूप चुभने लगी थी। दोपहर तक सड़कें खाली और बाजार सुस्त पड़ जाते हैं। "पहले इतनी जल्दी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी," वह कहती हैं। उधर, गोरखपुर के एक गांव में किसान रामस्वरूप गेहूं की कटाई के बीच बार-बार रुकने को मजबूर हैं। तेज धूप में मजदूर ज्यादा देर काम नहीं कर पा रहे। पानी की कमी अलग चिंता है। भारत में हीटवेव अब अपवाद नहीं रही। पिछले एक दशक में गर्म दिनों की संख्या और उनकी तीव्रता दोनों बढ़ी हैं। अप्रैल से जून के बीच कई राज्यों में तापमान 40-45°C तक पहुंचना आम होता जा रहा है। कई जगहों पर रात का तापमान भी इतना अधिक रहता है कि शरीर को राहत नहीं मिलती। यह बदलाव सिर्फ मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का सीधा असर मानते हैं - जहां ग्लोबल वार्मिंग स्थानीय मौसम को और चरम बना रही है।

## गांव और खेत: आजीविका पर असर

ग्रामीण भारत में हीटवेव सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आजीविका का संकट है। तेज गर्मी का असर सीधे खेती पर पड़ता है: गेहूं और दालों की पैदावार घटती है सब्जी और फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है पशुओं पर असर - दूध उत्पादन कम होता है इसके साथ ही, खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता है। मजदूरों के काम के घंटे घटते हैं, जिससे आय पर असर पड़ता है। पानी की कमी इस संकट को और गहरा करती है। कई इलाकों में कुएं और तालाब जल्दी सूखने लगते हैं। यानी गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है।

## स्वास्थ्य पर बढ़ता खतरा

हीटवेव का सबसे गंभीर असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ते हैं बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं बाहर काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं

शहरों में अस्पतालों पर दबाव बढ़ता है, जबकि गांवों में सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं इस खतरे को और गंभीर बना देती हैं। कई बार हीटवेव 'साइलेंट किलर' बन जाती है - जिसका असर आंकों से ज्यादा जमीन पर दिखता है।

जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे पानी और बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ती है। शहरों में पानी की सप्लाई पर दबाव बढ़ता है, टैंकों पर निर्भरता बढ़ती है। गांवों में जलस्रोत जल्दी सूखने लगते हैं। बिजली की मांग गर्मी के महीनों में चरम पर पहुंच जाती है। कई राज्यों में पावर कट आम हो जाते हैं। यह एक चक्र है - जितनी ज्यादा गर्मी, उतना ज्यादा संसाधनों पर दबाव, और उतनी ही ज्यादा असमानता।

## पानी और बिजली: संसाधनों पर दबाव



## हीटवेव क्या है?

जब तापमान सामान्य से 4-5°C ज्यादा हो और लगातार कई दिनों तक बना रहे, तो उसे हीटवेव कहा जाता है।

मुख्य संकेत:

- \* तापमान 40°C या उससे अधिक
- \* तेज, शुष्क हवाएं
- \* रात में भी गर्मी बनी रहना

## तैयारी: कागज बनाम जमीन

सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में 'हीट एक्शन प्लान' लागू किए हैं।

- \* चेतावनी प्रणाली
- \* कूलिंग सेंटर
- \* पानी की उपलब्धता
- \* जागरूकता अभियान

में इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन योजनाओं की पहुंच सीमित है - खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अक्सर तैयारी तब तेज होती है, जब संकट पहले से शुरू हो चुका होता है।

## गर्मी से बचाव—5 जरूरी उपाय

1. दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
2. पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें
3. हल्के और ढीले कपड़े पहनें
4. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें
5. हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें

## बदलता ट्रेंड: गर्मी के नए आंकड़े

पिछले वर्षों में भारत में हीटवेव के पैटर्न में बदलाव साफ दिखता है:

- \* हीटवेव के दिनों की संख्या बढ़ी है
  - \* तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं
  - \* रात का तापमान भी लगातार ऊंचा बना रहता है
- यह ट्रेंड बताता है कि भविष्य में यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

## समाधान: सिर्फ राहत नहीं, बदलाव

गर्मी से निपटने के लिए तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है।

### शहरों में

- \* ग्रीन कवर बढ़ाना
- \* कूल रूफ तकनीक (सफेद या रिफ्लेक्टिव छत)
- \* बेहतर शहरी योजना

### गांवों में

- \* जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
- \* सूखा-रोधी फसलें
- \* माइक्रो-इरिगेशन तकनीक

साथ ही, लोगों के व्यवहार में भी बदलाव जरूरी है - ऊर्जा की बचत, पानी का सही उपयोग और जागरूकता।



हीटवेव अब एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि भारत की नई वास्तविकता है। यह शहरों और गांवों दोनों को प्रभावित कर रही है - अलग-अलग रूपों में, लेकिन समान तीव्रता के साथ। 2026 की गर्मी हमें एक स्पष्ट चेतावनी दे रही है - अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले साल और ज्यादा कठिन होंगे। भारत के सामने चुनौती सिर्फ तापमान को मापने की नहीं, बल्कि उससे निपटने की है। क्योंकि 'जलता भारत' अब खबर नहीं, हकीकत है - और 'ठंडा समाधान' अब विकल्प नहीं, जरूरत है।

### संकट अब स्थायी है?



# मिडिल क्लास का बजट 2026: कमाई बढ़ी, बचत क्यों घटी?

रफ्तार मीडिया || सवांददाता

मुंबई के उपनगर में रहने वाले 35 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल आकाश की सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि एक नोटिफिकेशन से होती है - "EMI deducted"। घर, कार और क्रेडिट कार्ड - महीने की शुरुआत ही तय खर्च से होती है। उधर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसान ओम प्रकाश की सुबह खेत से शुरू होती है - लेकिन उनकी चिंता भी उतनी ही भारी है। खाद, बीज और डीजल की बढ़ती लागत, और फसल की अनिश्चित कीमत। दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन एक सच्चाई समान - कमाई बढ़ने के बावजूद बचत लगातार सिकुड़ रही है।

**सैलरी और आमदनी: बढ़ती, पर अधूरी राहत**  
: शहरी भारत में सैलरी ग्रोथ औसतन 8-10% के आसपास रही है। आईटी और सर्विस सेक्टर में यह थोड़ी बेहतर दिखती है। लेकिन इसी दौरान मेट्रो शहरों में किराए में पिछले दो वर्षों में 15-20% तक की बढ़ती दर्ज की गई है। बाहर खाने, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की सेवाओं की लागत भी तेजी से बढ़ी है। गांवों और छोटे कस्बों में स्थिति और जटिल है। यहां आमदनी स्थिर नहीं, बल्कि मौसम, फसल और बाजार कीमतों पर निर्भर है। कई बार अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाते। आमदनी बढ़ रही है, लेकिन 'रियल इनकम' - यानी खर्च के बाद बचने वाली राशि - घट रही है।

## मिडिल क्लास बजट 2026—एक नजर में

- \* औसत सैलरी ग्रोथ: 8-10%
- \* शहरी किराया बढ़ती: 15-20% (मेट्रो शहरों में)
- \* हेल्थकेयर खर्च में वृद्धि: 10-15%
- \* एजुकेशन कॉस्ट: 8-12% सालाना बढ़ती
- \* औसत EMI बोझ: आय का 30-40%

### निष्कर्ष:

कमाई बढ़ने के बावजूद खर्च की रफ्तार ज्यादा तेज

## EMI का जाल: सुविधा

### से फंदा तक

एक समय था जब EMI सिर्फ घर या गाड़ी तक सीमित थी। अब यह मिडिल क्लास की पूरी लाइफस्टाइल में घुल चुकी है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि छुट्टियां भी किस्तों पर खरीदी जा रही हैं। 'Buy Now Pay Later' और आसान क्रेडिट ने खर्च को सहज बना दिया है। गांवों में भी यह ट्रेंड पहुंच चुका है -

ट्रैक्टर, बाइक, कृषि उपकरण - सब कुछ लोन पर। किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रोफाइनेंस ने कर्ज लेना आसान किया है, लेकिन जोखिम भी बढ़ाया है।

व्याज दरों में बढ़ती ने इस दबाव को और बढ़ाया है। आज स्थिति यह है कि कई परिवारों की आय का 30-40% हिस्सा EMI में चला जाता है।

## हेल्थ और एजुकेशन: हर वर्ग पर दबाव

कोविड के बाद स्वास्थ्य खर्च मध्यम वर्ग के बजट का स्थायी हिस्सा बन गया है। प्राइवेट अस्पतालों के बिल, बढ़ते इंश्योरेंस प्रीमियम और नियमित जांच—सब मिलकर जेब पर दबाव डाल रहे हैं। गांवों में भी स्थिति अलग नहीं है। बेहतर इलाज के लिए शहरों पर निर्भरता और निजी

क्लीनिक का खर्च बढ़ा है। इसी तरह शिक्षा भी लगातार महंगी होती जा रही है - शहरों में स्कूल फीस और कोचिंग, और गांवों में निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान। ये दोनों ऐसे खर्च हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता और इसलिए सबसे ज्यादा असर बचत पर पड़ता है।

## निवेश: बढ़ती जागरुकता

## घटती निरंतरता



निवेश का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। शहरों में SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और डिजिटल गोल्ड लोकप्रिय हो रहे हैं। गांवों में भी बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। लेकिन एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आ रहा है - निवेश बढ़ रहा है, लेकिन उसकी निरंतरता घट रही है। क्रेडिट कार्ड बकाया, पर्सनल लोन और अनिश्चित आय के कारण लोग निवेश शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे जारी रखना मुश्किल होता है। मिडिल क्लास के खर्च का सबसे तेज बढ़ता हिस्सा है - लाइफस्टाइल। शहरों में वीकेंड डाइनिंग, ट्रैवल, OTT और गैजेट्स आम हो चुके हैं। गांवों में भी स्मार्टफोन, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और डिजिटल कंटेंट का असर तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया ने आकांक्षाओं को एक नया आयाम दिया है। FOMO (Fear of Missing Out) यानी पीछे छूट जाने का डर - अब खर्च का बड़ा कारण बन चुका है। जरूरत और इच्छा के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, और इसका सीधा असर बचत पर पड़ रहा है। मिडिल क्लास के लिए चुनौती अब सिर्फ कमाई बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने की है। बजटिंग, सीमित कर्ज, इमरजेंसी फंड और नियमित निवेश - ये पुराने फॉर्मूले आज भी उतने ही जरूरी हैं, शायद पहले से ज्यादा।



## नई कमाई, नए इम्तिहान

2026 का मिडिल क्लास पहले से ज्यादा कमाता है, लेकिन उतना ही ज्यादा जोखिम भी उठाता है। यह वर्ग अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन चुका है - जहां हर बढ़ती सैलरी के साथ एक नया

वित्तीय दबाव जुड़ जाता है। भारत का मिडिल क्लास अब एक नए दौर में है - जहां समृद्धि और असुरक्षा साथ-साथ चल रहे हैं। असली चुनौती यही है कि आकांक्षाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

पहलू	शहरी मिडिल क्लास	ग्रामीण मिडिल क्लास / किसान
आमदनी	स्थिर (सैलरी आधारित)	अस्थिर (फसल/मौसम पर निर्भर)
मुख्य खर्च	किराया, EMI, लाइफस्टाइल	खेती लागत, घरेलू जरूरतें
कर्ज	होम/कार/क्रेडिट कार्ड	KCC, माइक्रोफाइनेंस
निवेश	SIP, स्टॉक्स	सोना, जमीन, बचत योजनाएं
जोखिम	नौकरी का अनिश्चित भविष्य	मौसम और बाजार कीमत

## खेती की लागत: डबल दबाव

खाद, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों ने खेती की लागत बढ़ा दी है। MSP और बाजार कीमत के बीच का अंतर कई बार किसानों की कमाई को सीमित कर देता है।

इसका असर शहरों तक पहुंचता है - महंगी सब्जियां और अनाज। यानी किसान और शहरी मिडिल क्लास दोनों एक ही आर्थिक दबाव के अलग-अलग हिस्से झेल रहे हैं।



# RAFTAAR INSTITUTE OF MEDIA STUDIES

## Admission Started for Crash/Vocational Course in Mass Communication

We Are Ready to Welcome You at  
Raftaar Institute of Media Studies



**Be Ready  
to  
Join**

**Course**

**100%**  
PLACEMENT  
ASSISTANCE

**Anchor**

**Reporter**

**Scriptwriter**

**Video Editor**

**Cameraman**

**Helpline Number**  
**6203592707, 9334722857**

**UTTAM NIWAS, HARMU HOUSING COLONY  
RANCHI- 02, JHARKHAND**



## हॉकी पाठशाला : खिलाड़ियों को हॉकी की तकनीकी ज्ञान देशभर में हॉकी की नई क्रांति, झारखंड बनेगा केंद्र

**भा** रत में हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और गौरव की पहचान रही है. खासकर झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में हॉकी गांव-गांव की मिट्टी में बसती है. यही वजह है कि देश को सबसे अधिक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी देने वाले राज्यों में झारखंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. अब इसी परंपरा को और मजबूत करने के लिए हॉकी इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है "हॉकी पाठशाला". यह पहल डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खिलाड़ियों को हॉकी के तकनीकी ज्ञान, नियम और आधुनिक कौशल से जोड़ने का प्रयास है. हॉकी इंडिया ने इस योजना को अपनी सभी इकाइयों के साथ साझा किया है और हॉकी झारखंड को भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए. हॉकी पाठशाला दरअसल एक विशेष डिजिटल वीडियो सीरीज और प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं, उभरते खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों को खेल की बुनियादी और उन्नत तकनीकों से परिचित कराना है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तथा अनुभवी कोच हॉकी के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हैं. इसमें ड्रिलिंग, पारिंग, डिफेंस, पेनल्टी कॉर्नर, गोलकीपिंग,

फिटनेस, खेल के नियम और मैच के दौरान मानसिक तैयारी जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाती है. हॉकी इंडिया का मानना है कि अगर खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर सही तकनीकी ज्ञान मिल जाए तो उनकी प्रतिभा और बेहतर तरीके से निखर सकती है.

झारखंड में इस योजना को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है. इसकी

कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने देश के लिए पदक जीते और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया.

झारखंड की धरती ने भारतीय हॉकी को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं. ओलंपियन सिलवानुस डुंगडुंग, मनोहर टोपनो, सावित्री पूर्ति, सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जैसे कई खिलाड़ियों

झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार खिलाड़ियों को खेल की बुनियादी तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सिर्फ बांस की स्टिक लेकर अभ्यास करते हैं. उनमें जुनून और मेहनत की कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें खेल के नियम, तकनीकी समझ और आधुनिक



इस पहल की खास बात यह भी है कि इसमें पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. हॉकी झारखंड चाहता है कि राज्य के दिग्गज खिलाड़ी अपने अनुभव नई पीढ़ी के साथ साझा करें. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी और उन्हें यह समझने का मौका मिलेगा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और सही मार्गदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है.

सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य को लंबे समय से भारतीय हॉकी की नर्सरी माना जाता रहा है. राज्य के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची और आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों में हॉकी सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा है. यहां के बच्चे बचपन से ही लकड़ी या बांस की स्टिक बनाकर मैदान में उतर जाते हैं. संसाधनों की कमी के बावजूद यहां से

ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. यही वजह है कि हॉकी इंडिया चाहता है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से और मजबूत किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें. हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह का कहना है कि

प्रशिक्षण की जरूरत होती है. हॉकी पाठशाला इसी कमी को दूर करने का प्रयास है.

विजय शंकर सिंह बताते हैं कि हॉकी पाठशाला के पहले चरण में ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी. वीडियो मॉड्यूल के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को हॉकी की बारीकियां सिखाई जाएंगी.



# विनेश फोगाट को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की दी अनुमति

**म** हिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की फटकार लगाई है। कोर्ट ने विनेश फोगाट एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की दी अनुमति देते हुए कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ के दो स्वतंत्र पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ट्रायल की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, खेल और न्याय के हित में विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति देना जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि डब्ल्यूएफआई की चयन नीति भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश से वापसी कर रही फोगाट जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि एशियाई खेलों के चयन ट्रायल की WFI द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ के दो स्वतंत्र पर्यवेक्षक मौजूद

फोगाट के सीनियर वकील ने बेंच से गुजारिश की कि उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वकील ने दलील दी कि 9 मई को फोगाट को एक 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notice) जारी किया गया था। यह नोटिस गोंडा में होने वाले एक घरेलू टूर्नामेंट में उनके हिस्सा लेने से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया था। वकील ने कहा कि इस नोटिस से साफ ज़ाहिर होता है कि कोई उन्हें बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।



रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि WFI ने पहले

की उस परंपरा को तोड़ दिया है, जिसके तहत मशहूर खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती थी। बता दें कि कोर्ट विनेश फोगाट की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने 18 मई

को एक सिंगल-जज द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में कोर्ट ने फोगाट को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। फोगाट ने मांग की थी कि WFI द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद, उन्हें इस साल के एशियन गेम्स के लिए 30-31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने इस 'कारण बताओ नोटिस' पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की। कोर्ट ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में फोगाट का बाहर होना पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर यह क्यों न मान लिया जाए कि WFI ने जान-बूझकर फोगाट को बाहर करने के लिए सिलेक्शन के नियमों में बदलाव किया है।



## पहले किया डीएक्टिवेट फिर तुरंत इंस्टाग्राम पर लौटे सलमान फैंस शॉकड, पूछा- अब क्या हुआ 'भाईजान' ?

**स** लमान खान का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार, 25 मई को कुछ समय के लिए बंद हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गई. खबरों के मुताबिक, एक्टर की प्रोफाइल खोजने वाले यूजर्स को उनका अकाउंट नहीं मिल पा रहा था, जिससे कई लोग यह सोचने लगे कि क्या उनका अकाउंट हैक हो गया है, डिलीट कर दिया गया है, या फिर उसे कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है. प्रोफाइल गायब होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर सलमान खान का गायब इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होने लगा. फैंस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस अचानक हुई घटना पर चर्चा की. कई फैंस ने चिंता जाहिर की कि सलमान का अकाउंट किसी तरह से खतरे में तो नहीं है? दबंग एक्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट करीब 30 मिनट तक गायब रहा, जिसके बाद वह फिर से दिखवा देने लगा. हालांकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होने के लगभग 30 मिनट बाद फिर से दिखने लगा. फिलहाल, न तो सलमान और न ही उनकी टीम ने अकाउंट के गायब होने के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट किसी तकनीकी खराबी के कारण हटाया गया था, स्वेच्छा से डीएक्टिवेट किया गया था, या फिर किसी हैकिंग के प्रयास का शिकार हुआ था

यह अभी भी साफ नहीं है कि यह गायब होना किसी तकनीकी गड़बड़ी, कुछ समय के लिए बंद होने या किसी संभावित हैकिंग की कोशिश की वजह से था. सलमान के इंस्टाग्राम पर 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यह एक्टर अक्सर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी फिल्मों, फिटनेस, निजी पलों और परिवार से जुड़ी बातों शेयर करने के लिए करते हैं.

## सलमान के पास अभी दो फिल्में लाइन में हैं



'मातृभूमि' और वामशी पैडिपल्ली की अनटाइटल्ड फिल्म. जहां 'मातृभूमि' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वहीं वामशी की फिल्म अभी प्रोडक्शन में है. 'मातृभूमि' इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है, और नई रिलीज डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है. यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी झड़प की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. अपूर्व लाखिया की निर्देशित इस फिल्म में जेन शां, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं. इसके अलावा, सलमान के पास नयनतारा के साथ एक और अनटाइटल फिल्म भी है.

**ONGOING PROJECT**



Three balconies outside, dark iron



Nandan enclave, Jaspurda

**MODE OF PAYMENT**

- At the time of Booking - 20%
- At the time of Foundation - 20%
- At the time of 1st floor casting - 15%
- At the time of 2nd floor casting - 15%
- At the time of 3rd floor casting - 15%
- At the time of 4th floor casting - 12%
- At the time of 5th floor casting - 12%
- Slipwork and plaster and finishing work in the time of registry - 80%

**Terms and Conditions:**

- \*Any Tax Charges will be extra as per Government Norms
- \*Registry charges extra

**LOCATION MAP**



**PROJECT BY**  
**NANDAN HEIGHTS LLP**

Plot No. 10, Jaspurda, Gaya, Bihar, India  
 9334457379, 7970599666  
 nandanheights@gmail.com

Architect Engineer & Structural Designer  
 ARORA BYPASS RD, ARORA, BIHAR  
 Mob: 9334457379

**NANDAN HEIGHTS LLP**

Projects

**Saraswati Nandan Enclave**

**EMI FREE**  
RMC APPROVED



Well Planned 2 BHK Apartments at  
Tupurda (Ranchi)

**BOOKING CONTACT NO**  
6203592707, 9334457379, 7970599666

9334457379, 7970599666, 6203592707



# NANDAN VILLA





**BLOCK - A**



**BLOCK - B**

**SITE ADDRESS :** BELLAHI , OPPOSITE GAYA AIRPORT  
GAYA (BIHAR)

**raftaarhr@gmail.com**

**6203592707, 8709733241, 6203764769**

**7970599666**



**सलुजा गोल्ड**

**TMT BARS**



**मज़बूती  
सबकुछ है**

